चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित

01 जून –07 जून 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

राहुल गांधी की राजनीति और रणनीति बदल गई है

"कांग्रेस पार्टी बदली-बदली सी नज़र आ रही है. राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में नई ऊर्जा भरने में सफल साबित हो रहे हैं. राहुल गांधी की छवि अब एक अनिच्छुक नेता की नहीं रही, बल्कि वह एक सक्रिय नेता बनकर उभर रहे हैं. राहुल गांधी की रणनीति साफ़ है. इस रणनीति के दो पहलू हैं. पहला यह कि भारतीय जनता पार्टी को अमीरों और कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुंचाने वाली पार्टी के रूप में पेश करना है. दूसरा यह कि कांग्रेस पार्टी को ग़रीबों, किसानों, मज़दूरों के लिए संघर्ष और आंदोलन करने वाली पार्टी के रूप में खड़ा करना है. राहुल गांधी का नया अवतार और संसद के अंदर मोदी सरकार के हर क़दम का विरोध भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन गया है."

मनीष कुमार

राहुल गांधी जबसे अवकाश से वापस लौटे हैं, तबसे वह बिल्कुल अलग अंदाज़ में दिख रहे हैं. राहुल गांधी का न सिर्फ़ अंदाज़ नया है, बल्कि उनकी सोच भी नई है. रणनीति नई है. राजनीति नई है. सलाहकार नए हैं और नज़रिया नया है. यही वजह है कि पिछले दस सालों में वह जितना संसद में बोले, उससे कहीं ज़्यादा बजट सत्र में उन्होंने अपनी बात रखी. संसद में वह भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं, साथ ही किसानों के मुद्दे को लेकर संसद से सड़क तक नज़र आ रहे हैं. किसानों की आत्महत्या के ख़िलाफ़ वह चिलचिलाती गर्मी में पदयात्रा भी कर रहे हैं. गांवों में जाकर वह लोगों के बीच खाट पर बैठकर चाय पीते हैं, ग्रामीणों से बातचीत करते हैं. संसद के अंदर चाहे भूमि अधिग्रहण का मामला हो या फिर नेट न्यूट्रैलिटी का, राहुल गांधी एक नए अवतार में नज़र आ रहे हैं. यह भी कहना पड़ेगा कि उनका प्रदर्शन जबरदस्त रहा है. कहने का मतलब यह कि राहुल गांधी जबसे अवकाश से वापस लौटे हैं, वह काफी प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे हैं. राहुल के इस प्रदर्शन से जहां एक तरफ़ भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर चली गई, वहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बेचैनी फैली हुई है. कांग्रेस का हर बड़ा और छोटा नेता पार्टी में अपने भविष्य को लेकर गहन चिंतन कर रहा है.

चौथी दुनिया ने तीन महीने पहले ही यह ख़बर दी थी कि सितंबर में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा. राहुल गांधी के सारे क्रियाकलाप कांग्रेस की इसी महायोजना के हिस्से हैं. राहुल गांधी न सिर्फ़ कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, बल्कि वह अपने पसंद की टीम भी बनाएंगे. अपनी नई टीम की ज़रिये ही वह पार्टी को फिर से मजबूत करने की रणनीति ज़मीन पर लागू करेंगे. राहुल की टीम में कौन-कौन होगा और किस-किसकी छुट्टी होगी, इसे लेकर नए और पुराने कांग्रेसी नेता आजकल बेचैन हैं. बेचैनी की वजह यह है कि राहुल गांधी का पूरा अंदाज़ बदल चुका है.

राहुल गांधी को इस बात का एहसास हो चुका है कि अब कांग्रेस विपक्ष के रोल में है और सरकार पर आक्रमण करना ही सबसे कारगर रणनीति है. इसलिए वह हर मुद्दे पर आक्रामक नज़र आ रहे हैं. उनकी रणनीति साफ़ है. वह मोदी सरकार को ग़रीब, किसान एवं मज़दूर विरोधी सरकार के रूप में प्रचारित करना चाहते हैं. यही वजह है कि वह भूमि अधिग्रहण बिल के ख़िलाफ़ संसद से सड़क तक आंदोलन करने में जुटे हैं.

राहुल गांधी अब कांग्रेस को ऐसी पार्टी के रूप में विकसित करना चाहते हैं, जिसमें पदाधिकारियों को ज़िम्मेदारी लेनी होगी. वह अब कुछ खास सलाहकारों से सलाह लेने के बजाय विस्तृत परामर्श के बाद फ़ैसले लेने लगे हैं. यही वजह है कि कल तक जो लोग राहुल गांधी के निकटतम सलाहकार थे, उनका प्रभाव

और महत्व कम हो गया है. राहुल गांधी को अब यह बात समझ में आ गई है कि उनके कई सारे फ़ैसले जो उन्होंने अपने निकटतम सलाहकारों की सलाह पर लिए थे, उनसे उन्हें और पार्टी को नुक़सान हुआ है. ऐसे लोगों में जयराम रमेश, मधुसूदन मिस्त्री, मोहन प्रकाश और सीपी जोशी आदि शामिल हैं.

राहुल गांधी को इस बात का एहसास हो चुका है कि अब कांग्रेस विपक्ष के रोल में है और सरकार पर आक्रमण करना ही सबसे कारगर रणनीति है. इसलिए वह हर मुद्दे पर आक्रामक नज़र आ रहे हैं. उनकी रणनीति साफ़ है. वह मोदी सरकार को ग़रीब, किसान एवं मज़दूर विरोधी सरकार के रूप में प्रचारित करना चाहते हैं. यही वजह है कि वह भूमि अधिग्रहण बिल के ख़िलाफ़ संसद से सड़क तक आंदोलन करने में जुटे हैं. भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध के पीछे वह उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के ग़रीब किसानों को लुभाने की कोशिश में लगे हैं. राहुल गांधी को लगता है कि लोकसभा चुनाव में हार की वजह मनमोहन सरकार की ग़रीब विरोधी छवि रही है. साथ ही उन्हें इस बात से नाराज़गी है कि यूपीए सरकार के मंत्रियों ने कई सारी जनहितकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में ढिलाई बरती. उन्हें लगता है कि यदि किसानों एवं ग़रीबों को सीधे-सीधे नकदी (कैश) देने वाली योजनाओं को सही ढंग से लागू किया गया होता और किसानों एवं ग्रामीण मज़दूरों को राहत देने वाली विभिन्न योजनाओं पर ध्यान दिया गया होता, तो पार्टी की यह हालत न होती. राहुल गांधी को एक और बात की शिकायत है कि भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी की जो छवि बनी, उससे पारंपरिक समर्थकों का विश्वास और समर्थन पार्टी ने खो दिया. अभी लोकसभा चुनाव में चार साल का वक्त है. इस बीच बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं. राहुल ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ़ निर्देश दिए हैं कि पार्टी के पुनर्निर्माण का काम ज़मीनी स्तर से शुरू होना चाहिए. इसमें युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़ा मिलना चाहिए. इसके साथ ही पार्टी

(शेष पृष्ठ 2 पर)

उत्तर प्रदेश : विकास के काम में सेना डाल रही बाधा | P-3

मध्य प्रदेश : आर-पार की लड़ाई की तैयारी में विस्थापित | P-5

किसान: न खेत को पानी, न हाथ को काम | P-6

राहुल गांधी की राजनीति और रणनीति बदल गई है

पृष्ठ 1 का शेष

पदाधिकारियों और नेताओं को अपने–अपने क्षेत्रों में जाकर काम करने की सलाह दी गई है.

राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हैं. पार्टी को फिर से खड़ा करने की रणनीति भी उन्होंने बना ली है. उन्हें चुनौतियों का अंदाज़ा भी हो चुका है. कांग्रेस पार्टी के अंदर मौजूद कमियों को भी उन्होंने समझने की कोशिश की है और उसका विश्लेषण किया है. कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी ऊहापोह की स्थिति है, कोई आगे बढ़कर बोलना नहीं चाहता. पार्टी नेताओं में राहुल गांधी की नज़रों में योग्य दिखने की होड़ लगी है. कांग्रेस के एक युवा नेता ने बताया कि राहुल गांधी ने चुनाव नतीजे आने के बाद क़रीब 500 ज़मीनी कांग्रेसी नेताओं और पदाधिकारियों से बातचीत की. सबसे हार के कारणों को चिन्हित करने को कहा. राहुल गांधी यह काम दो महीने तक करते रहे और उसके बाद उन्होंने रणनीति तय की. इसके चार चरण हैं. पहला, पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत करना. दूसरा, स्थानीय मुद्दों को उठाकर कांग्रेस के पारंपरिक मतदाताओं–समर्थकों के साथ संपर्क स्थापित करना. तीसरा, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहां सरकार का विरोध करते हुए जनता के बीच अपनी उपस्थिति बनाए रखना. चौथा यह कि पिछले दिनों हुईं ग़लतियों का सुधारना, जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से प्रो–मुस्लिम नज़र आना.

राहुल गांधी ने यह रणनीति फरवरी में ही तैयार कर ली थी, लेकिन इसे कब से लांच किया जाए, यह तय नहीं हो पाया था. देरी इसलिए हुई, क्योंकि पार्टी के अंदर राहुल के ख़िलाफ़ ही कई नेता बयानबाजी करने लगे. कांग्रेस पार्टी के पुराने और अनुभवी नेता भी विरोध पर उतारू थे. कांग्रेस के अंदर यह भय भी पैदा हो गया था कि कहीं कुछ नेता विद्रोह न कर बैठें. इसलिए किसी भी बदलाव के फ़ैसले को रोका गया. सोनिया गांधी ने पुराने नेताओं से बातचीत करके माहौल को नियंत्रित किया. ख़बर यह भी आई कि राहुल इस देरी की वजह से नाराज़ भी हुए और बजट सत्र के दौरान अवकाश पर चले गए. इसके बाद संसद के अंदर सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाला. किसानों के मुद्दे, खासकर भूमि अधिग्रहण बिल पर सोनिया गांधी की आक्रामक मुद्रा ने कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम किया. निराश और असहाय बैठे कांग्रेसी कार्यकर्ता जोश में आ गए. साथ ही राहुल गांधी के रि–लांचिंग का आधार भी बन गया. सोनिया गांधी ने बड़ी परिपक्वता के साथ राहुल के लिए राह आसान कर दी. यह तय हो गया कि राहुल गांधी अब अपने हिसाब से पार्टी को चलाएंगे और उनकी पदोन्नति में अब कोई भी पुराने एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रोड़ा नहीं बनेंगे.

यही वजह है कि राहुल गांधी ने अवकाश से वापस आते ही मोर्चा संभाल लिया. संसद के अंदर उनका शानदार प्रदर्शन रहा ही. साथ ही उन्होंने किसानों के लिए पदयात्रा और संपर्क साध कर अपनी नई भूमिका की शुरुआत कर दी. राहुल की रणनीति साफ़ है. उन्हें यह भी समझ में आ चुका है कि कांग्रेस को सांगठनिक और वैचारिक रूप से खड़ा करना होगा. उन्होंने पार्टी को ग़रीबों, किसानों, मज़दूरों और दलितों

की हितैषी दिखने वाली समाजवादी लाइन पर वापस लाने का फ़ैसला किया है. यह वैचारिक लाइन भारतीय जनता पार्टी को कॉरपोरेट्स द्वारा संचालित और अमीरों के लिए काम करने वाली पार्टी घोषित करने में मददगार साबित होगी और साथ ही इसके ज़रिये वह जनता परिवार और क्षेत्रीय दलों को वैचारिक चुनौती देने में भी सफल हो पाएंगे. राहुल गांधी अगले एक–दो साल में कांग्रेस को संगठन और विचारधारा के तौर पर बिल्कुल एक नई पार्टी के रूप में खड़ा करना चाहते हैं. वह चाहते हैं कि पार्टी युवाओं के समर्थन से युवाओं द्वारा युवाओं के भविष्य के लिए समर्पित हो.

राहुल गांधी कांग्रेस को एक संघर्षशील पार्टी के रूप में तैयार करना चाहते हैं. इसी रणनीति के तहत वह देश के हर राज्य में जा–जाकर केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने वाले हैं. केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध वह सिर्फ़ संसद और प्रेस कांफ्रेंस के ज़रिये नहीं करना चाहते हैं. वह देश के अलग–अलग इलाकों, खासकर भाजपा शासित राज्यों का खूब दौरा करने वाले हैं. इसके दो उद्देश्य हैं. एक तो संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी, दूसरे वह किसानों, मज़दूरों और ग़रीबों का मुद्दा उठाकर भाजपा सरकार को सूटबूट की सरकार साबित करेंगे. जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, उन पर राहुल गांधी का विशेष ध्यान है. ऐसे राज्यों के कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की बातों को वह ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं. उन्हें साफ़–साफ़ निर्देश दिया गया है कि वे राज्य सरकार के ख़िलाफ़ हरसंभव मुद्दे पर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करें. आने वाले दिनों में कांग्रेस के ऐसे स्थानीय आंदोलनों में स्वयं राहुल गांधी की भी हिस्सेदारी रहने वाली है. हर राज्य के कांग्रेस नेताओं को बूथ स्तर पर पार्टी संगठन तैयार करने को कहा गया है. साथ ही राहुल गांधी ने बूथ स्तर तक के लिए पार्टी संगठन में फेरबदल करने की इच्छा जताई

राहुल गांधी ने यह रणनीति फरवरी में ही तैयार कर ली थी, लेकिन इसे कब से लांच किया जाए, यह तय नहीं हो पाया था. देरी इसलिए हुई, क्योंकि पार्टी के अंदर राहुल के ख़िलाफ़ ही कई नेता बयानबाजी करने लगे. कांग्रेस पार्टी के पुराने और अनुभवी नेता भी विरोध पर उतारू थे. कांग्रेस के अंदर यह भय भी पैदा हो गया था कि कहीं कुछ नेता विद्रोह न कर बैठें.

है. वह चाहते हैं कि पार्टी के हर स्तर पर विचारधारा में आस्था रखने वालों को ज़िम्मेदारी दी जाए. ऐसे लोगों को स्थानीय स्तर पर फ़ैसले लेने में हिस्सेदार बनाया जाए. कांग्रेस पार्टी जल्द ही ऐसे लोगों की पहचान और उन्हें पार्टी में वापस शामिल करने के लिए एक मुहिम की शुरुआत करेगी. इसमें युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और इस कार्य के पूरा होते ही उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाएगा.

कई लोगों को लग सकता है कि राहुल गांधी पिछले कई सालों से संगठन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह कभी सफल नहीं हो पाए. इसलिए इसमें कुछ भी नया नहीं है. यह सवाल भी जायज है. लेकिन, इस बार राहुल गांधी जो फ़ैसले ले रहे हैं, उनमें राजनीतिक परिपक्वता नज़र आ रही है. साथ ही सरकार का बंधन भी नहीं है. पहले भी वह किसानों, मज़दूरों, ग़रीबों और वनवासियों की आवाज़ उठाते रहे हैं. चाहे मामला भट्टा– पारसौल के किसानों का हो या फिर नियमगिरि के वनवासियों का, राहुल ने इन मुद्दों को उठाया ज़रूर, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार राहुल गांधी के विचारों को योजनाओं में कार्यान्वित नहीं कर सकी. जनता को लगा कि कांग्रेस पार्टी में विरोधाभास है. राहुल कहते कुछ हैं और उनकी सरकार करती कुछ और है. कांग्रेस पार्टी के सामने अब यह दुविधा नहीं है. राहुल गांधी राजनीतिक फ़ैसले ले रहे हैं. उनकी ज़्यादातर गतिविधियां उन राज्यों में केंद्रित होंगी, जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है. लेकिन, फिलहाल राहुल गांधी बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं. बिहार में सितंबर–अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो जाएगी.

हालांकि, राहुल देश के कई राज्यों में संगठन के पुनर्गठन का काम करेंगे, राज्य स्तर पर कई नेताओं की छुट्टी भी हो सकती है. सबसे ज़्यादा कलह की आशंका उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जताई जा रही है. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, इसके लिए वह कुछ कड़े फ़ैसले भी ले सकते हैं. कांग्रेस संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत राहुल युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़ा देना चाहते हैं. उनकी नई रणनीति मूल रूप से युवा केंद्रित रणनीति है. ऐसे लोगों को मौक़ा दिया जाएगा, जो एनएसयूआई और युवक कांग्रेस के साथ कई सालों से जुड़े हैं. इसी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी आएदिन देशव्यापी बंद और आंदोलन का आह्वान करेगी. राहुल चाहते हैं कि सड़कों पर कांग्रेस का जो भी आंदोलन हो, उसमें युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो. युवाओं का समर्थन हासिल करने के लिए राहुल गांधी के सोशल मीडिया पर एकाउंट खोले गए हैं. भाजपा और आम आदमी पार्टी की तरह कांग्रेस भी सोशल मीडिया के ज़रिये युवाओं से सीधे जुड़ने की तैयारी कर रही है.

राहुल की रणनीति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी पुराने बड़े नेता को दरकिनार नहीं किया जाएगा. हां, इतना ज़रूर है कि उनकी ज़िम्मेदारी तय की जाएगी. राहुल गांधी के सामने चुनौतियों का पहाड़ है. चुनौतियां पार्टी के अंदर भी हैं और पार्टी के बाहर भी. अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी पार्टी में जान फूंकने में सफल होते हैं या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि राहुल गांधी जबसे अवकाश से वापस लौटे हैं, तबसे उनकी हर गतिविधि एक योजना के तहत है. इस योजना का पहला मकसद कांग्रेस को एक सक्षम विपक्ष के रूप में तैयार करना है, जिससे लोगों को यह विश्वास हो सके कि कांग्रेस मोदी का मुकाबला कर सकती है. फिलहाल, राहुल गांधी अपनी रणनीति में सफल होते नज़र आ रहे हैं. ■

manishbph244@gmail.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 13
दिल्ली, 01 जून –07 जून 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

आप की जंग!

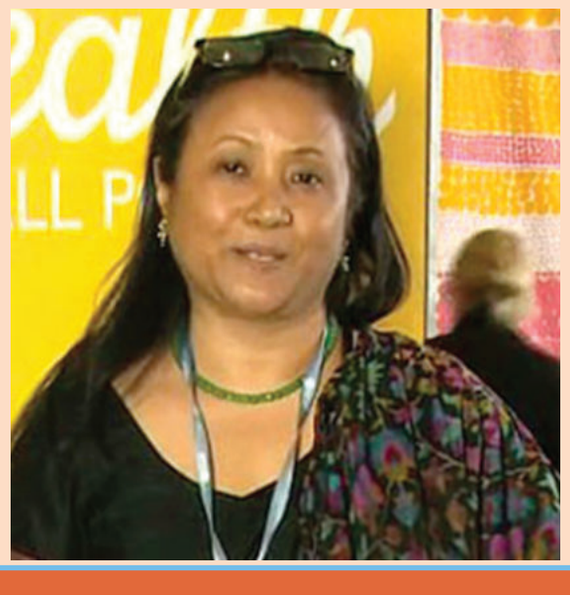

सत्ता किसकी है, यह अलग बात है, लेकिन कई बार सत्ता संघर्ष में स्थितियां जटिल हो जाती हैं, जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप–राज्यपाल नजीब जंग के बीच अस्थायी मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर हुआ मौजूदा संघर्ष तेजी से गंदा स्वरूप लेता जा रहा है. हालांकि, क़ानून के जानकार इस बात की तस्दीक करने में जुटे हैं कि संवैधानिक रूप से कौन ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच में नौकरशाह फंस गए हैं और असहाय नज़र आ रहे हैं. मुख्य सचिव केके शर्मा के दस दिनों के लिए छुट्टी पर जाने के बाद वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शकुंतला गैमलिन को उप–राज्यपाल ने कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त किया था. पहले तो मुख्यमंत्री ने नौकरशाहों को यह आदेश दिया कि कोई भी फाइल उनके पास होकर न जाए. गैमलिन ने गृह मंत्रालय से उनके ऊपर केजरीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों की शिकायत की है. इससे यह तो साफ़ हो गया है कि लड़ाई यहीं पर थमने नहीं जा रही है. मुख्यमंत्री ने नजीब जंग को कार्यवाहक मुख्य सचिव के लिए लोगों के नाम सुझाने की वजह से प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनिंदो मजूमदार का ट्रांसफर कर दिया और उनके कमरे के बाहर ताला लगा दिया. केजरीवाल और जंग दोनों दावा कर रहे हैं कि दोनों की लड़ाई से प्रशासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. कई वरिष्ठ नौकरशाह इस विवाद से बाहर आने का रास्ता तलाशने लगे हैं. परिणाम स्वरूप आईएएस और दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासनिक सेवा के 45 अधिकारियों ने अपने तबादले के लिए आवेदन कर दिया है तथा छह अधिकारी पहले ही छुट्टी पर चले गए हैं. कुछ दिल्ली के बाहर अपना तबादला कराना चाहते हैं. एक अफ़वाह यह उड़ रही है कि शर्मा ने भी अपनी छुट्टियां बढ़ाने का आग्रह किया है. ऐसा भी हो सकता है कि वह अपने पद पर वापस न लौटने की योजना बना रहे हों. ■

नियुक्तियों में तेजी

कई संस्थानों में शीर्ष स्तर पर रिक्तियां चिंता का विषय बन गई हैं. दरअसल, संसद में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए अपने हमले में इन रिक्तियों का ज़िक्र किया था. बीते सप्ताह एक स्तंभकार ने अपने आलेख में यह समझाया कि किस तरह पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज सेलेक्शन बोर्ड (पीईएसबी) को गुणवत्ता की कमी का सामना करना पड़ रहा है. इसके बाद से इस तरह की नियुक्तियों पर छिटपुट हलचल दिखाई दी है. जाहिर है, सरकार ट्राइ में राहुल खुल्लर के उत्तराधिकारी की नियुक्ति के मसले पर तेजी दिखा रही है. अभी तक इसके लिए सचिव स्तर के सात अधिकारियों के इंटरव्यू लिए जा चुके हैं, जिनमें आईटी सचिव आरएस शर्मा, आईबी सचिव बिमल जुल्का, वाणिज्य सचिव राजीव खेर, रक्षा सचिव आरके माथुर, स्पात सचिव राकेश सिंह और पूर्व संचार सचिव एमएफ फारूकी शामिल हैं. इस संबंध में निर्णय जल्दी आ सकता है. इसी तरह नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) की नियुक्ति भी जल्दी हो सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की वजह से हो रहा है. ■

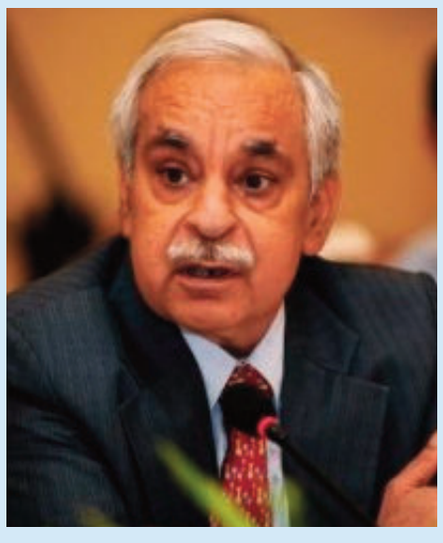

कला प्रेमियों को झटका

देश की अग्रणी सांस्कृतिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर सरकार के रुख को लेकर राजधानी के सांस्कृतिक हलकों में घबराहट दिखाई पड़ रही है. पिछले महीने मोदी सरकार ने देश के दस प्रमुख राष्ट्रीय सांस्कृतिक संगठनों में रिक्तियां भरने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की और संस्कृति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव केके मित्तल को ललित कला अकादमी में केंद्र सरकार के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया. इसकी वजह से यह संस्थान कम से कम तीन साल के लिए मंत्रालय के अंतर्गत आ गया है. कुदरती तौर पर कला–संस्कृति के जानकार एक नौकरशाह को इस कुर्सी पर बैठाने के सरकार के निर्णय से खुश नहीं हैं. दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक वेणु वासुदेवन को एक आईएएस अधिकारी होने के बावजूद सांस्कृतिक हलकों में नेशनल म्यूजियम का कायाकल्प करने की वजह से जाना जाता है. अचानक उनका तबादला खेल मंत्रालय में कर दिया गया. कई और बदलाव भी हुए हैं. यदि मित्तल की ललित कला अकादमी में नियुक्ति सरकार की ओर से कोई संकेत है, तो सरकार के इस निर्णय से राजधानी के कला–संस्कृति से जुड़े लोग खुश नहीं हैं. ■

dilipcherian@gmail..com

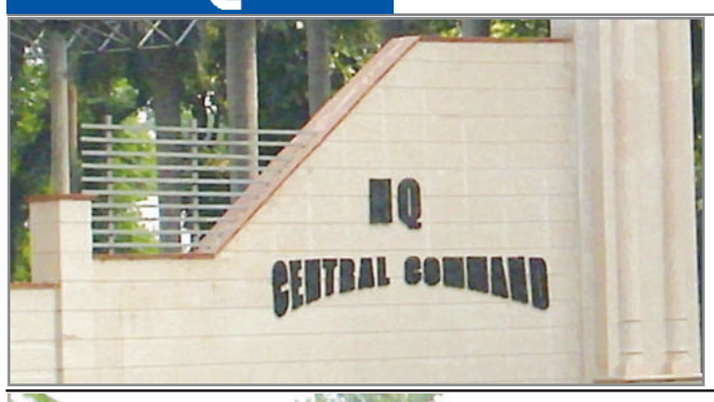

मध्य कमान मुख्यालय के पास 13 कैम्पिंग ग्राउंड थे. अब केवल सात कैम्पिंग ग्राउंड रह गए हैं, बाकी छह कैम्पिंग ग्राउंड लापता हो गए. जहां देखें, सेना की ज़मीन पर अवैध कब्जा दिखेगा. केवल लखनऊ ही नहीं, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, वाराणसी, फैजाबाद एवं इलाहाबाद यानी हर तरफ़ सेना की ज़मीनों पर नेता, माफिया, दलाल और धनपशु काबिज हैं. सेना की ज़मीन पर बिल्डिंग्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़े हैं. सेना के अंदरूनी क्षेत्र में कोठियों की लूट मची हुई है. लखनऊ में सेना के पास ट्रांस गोमती फायरिंग रेंज में 195 एकड़, अमौसी सेना क्षेत्र में 185 एकड़, कुकरैल फायरिंग रेंज में सौ एकड़, बख्शी का तालाब में 40 एकड़ और मोहनलालगंज क्षेत्र में 22 एकड़ ज़मीन है, लेकिन यह आंकड़ा केवल सेना के दस्तावेज़ों तक ही सीमित है. ज़मीनी असलियत भयावह है.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रक्षा मंत्री मनोहर परीकर को लिखा पत्र

विकास के काम में सेना डाल रही बाधा

- सेना ने कुकरैल बंधे पर सड़क और फ्लाईओवर बनाने के काम पर रोक लगा दी है.
- कहा, इस भाग में ट्रांस गोमती फायरिंग रेंज एवं कुकरैल फायरिंग रेंज का हिस्सा आता है.
- इन फायरिंग रेंज के आसपास घनी आबादी है और वर्षों से फायरिंग रेंज ऑपरेशनल नहीं है.
- लोक निर्माण विभाग ने वर्किंग परमिशन के तीन प्रस्ताव लखनऊ कमांड हेडक्वॉर्टर को भेजे.
- भूमि का स्वामित्व अपरिवर्तित रखते हुए केवल निर्माण की अनुमति मांगी.

प्रभात रंजन दीन

सेना की ज़मीनें अतिक्रमण का शिकार हो रही हैं, लेकिन उन ज़मीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की कोई कोशिश नहीं हो रही. थल सेना की मध्य कमान उत्तर प्रदेश के विकास के काम में बाधा डालने और बेमानी राजनीतिक पचड़े खड़ा करने में सक्रिय रहती है, लेकिन ज़रूरी मसलों पर उसका ध्यान नहीं रहता. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रक्षा मंत्री मनोहर परीकर को इस सिलसिले में पत्र लिखा है. ट्रांस गोमती फायरिंग रेंज एवं कुकरैल फायरिंग रेंज की बात कहकर सेना ने कुकरैल बंधे पर सड़क और फ्लाईओवर बनाने के काम पर रोक लगा दी है. जबकि ट्रांस गोमती फायरिंग रेंज एवं कुकरैल फायरिंग रेंज का आज कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है. उनके अधिकांश हिस्सों पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है कि सड़क और फ्लाईओवर बनाने की वर्किंग परमिशन शीघ्र दी जाए. मुख्यमंत्री ने इसे जनहित से जुड़ा मसला बताते हुए कहा है कि लखनऊ के कुकरैल बंधे पर निर्माणाधीन छह लेन मार्ग/उपरिगामी सेतु के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिए सेना शीघ्र वर्किंग परमिशन जारी करे. लखनऊ महानगर में कुकरैल बंधे के ऊपर छह लेन चौड़ी सड़क निर्माणाधीन है, जिसकी लंबाई 4.180 किलोमीटर है. सड़क के अतिरिक्त 1,020 मीटर लंबाई में फ्लाईओवर भी निर्माणाधीन है. इस सड़क के 2.55 किलोमीटर लंबाई में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, बाकी का काम सेना द्वारा आपत्ति किए जाने के कारण रुका पड़ा है.

मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को लिखा है कि इस मार्ग के निर्माण से लखनऊ महानगर की कई महत्वपूर्ण कालोनियों मसलन, खुर्रमनगर, विकास नगर, इंदिरा नगर की जनता को रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट जाने के लिए सुगम और सीधा मार्ग उपलब्ध हो जाएगा तथा शहर के ट्रैफिक जाम की समस्या से उन्हें मुक्ति मिल सकेगी. इस संबंध में मुख्यमंत्री ने अपने पूर्व के पत्र का हवाला भी दिया है, जिसके माध्यम से उन्होंने रक्षा मंत्री से लखनऊ शहर की यातायात समस्या के निराकरण के लिए सेना से अनापत्ति दिलाने का अनुरोध किया था. मुख्यमंत्री अखिलेश ने रक्षा मंत्री को अवगत कराया है कि सेना द्वारा अवशेष 1.630 किलोमीटर लंबाई में मार्ग निर्माण में यह आपत्ति जताई गई है कि इस भाग में ट्रांस गोमती फायरिंग रेंज एवं कुकरैल फायरिंग रेंज का हिस्सा आता है. इसी प्रकार फ्लाईओवर में भी सेना द्वारा ट्रांस गोमती फायरिंग रेंज का हिस्सा आने की बात कहकर आपत्ति दर्ज की गई है. जबकि इन दोनों ही फायरिंग रेंज के आसपास घनी आबादी है और वर्षों से फायरिंग रेंज ऑपरेशनल नहीं है. लोक निर्माण विभाग द्वारा 12 जून, 2013 को निर्माण कार्य की वर्किंग परमिशन के तीन प्रस्ताव लखनऊ स्थित कमांड हेडक्वॉर्टर को भेजते हुए अनुरोध किया गया था कि भूमि का स्वामित्व अपरिवर्तित रखते हुए केवल निर्माण की अनुमति प्रदान की जाए. पांच अगस्त, 2013 को सेना से एनओसी प्राप्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग एवं सेतु निगम के अधिकारियों की एक बैठक दिल्ली में हुई थी. इस बैठक में भी यही अनुरोध दोहराया गया था कि बिना भूमि हस्तांतरण किए निर्माण की ऑपरेशनल अनुमति प्रदान कर दी जाए. लेकिन, सेना ने प्रदेश सरकार के इस औपचारिक आग्रह पर कोई ध्यान ही नहीं दिया.

इसी क्रम में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव ने रक्षा मंत्रालय के सचिव एवं अपर सचिव को पत्र लिखकर ऑपरेशनल अनुमति के लिए औपचारिक अनुरोध किया था. प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन भी मध्य कमान के जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ (जीओसी-इन-सी) को पत्र लिखकर निर्माण की वर्किंग परमिशन के लिए अनुरोध कर चुके हैं. मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को इन सारी स्थितियों से अवगत कराते हुए कहा है कि सड़क या फ्लाईओवर बनाने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता भी नहीं है. सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित बंधे के ऊपर ही सड़क का निर्माण किया जाएगा. बाकी 330 मीटर लंबाई में फ्लाईओवर का निर्माण बंधे के बगल में नाले की ओर किया जाएगा, जिसमें सेना की अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होगी. लेकिन, सेना ने इस मसले को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है. विकास के काम में अड़चन डाले बैठी सेना को अपने कमान मुख्यालय क्षेत्र में चल रही आपत्तिजनक गतिविधियां, अवैध कब्जे, कोठियों की खरीद-बिक्री और कब्जेदारी का ग़ैर-क़ानूनी कारोबार नहीं दिखता. सेना का इंटेलिजेंस (खुफिया) महकमा इतना इंटेलिजेंट है कि उसे सड़क बनती हुई दिखती है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की कैंट स्थित आलीशान कोठी बिकती हुई नहीं दिखती और रातोंरात ट्रकों के काफिले पर घर का माल लदकर जाता भी नहीं दिखता. सेना क्षेत्र बाहरी अवांछित तत्वों का अड्डा बन गया है. सेना के लोगों ने ही बाहरी तत्वों को बसाने का धंधा चला रखा है. इन लोगों ने मध्य कमान की अचल संपत्ति का कबाड़ा कर दिया है.

मध्य कमान मुख्यालय के पास 13 कैम्पिंग ग्राउंड थे. अब केवल सात कैम्पिंग ग्राउंड रह गए हैं, बाकी छह कैम्पिंग ग्राउंड लापता हो गए. जहां देखें, सेना की ज़मीन पर अवैध कब्जा दिखेगा. केवल लखनऊ ही नहीं, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, वाराणसी, फैजाबाद एवं इलाहाबाद यानी हर तरफ़ सेना की ज़मीनों पर नेता, माफिया, दलाल और धनपशु काबिज हैं. सेना की ज़मीन पर बिल्डिंग्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़े हैं. सेना के अंदरूनी क्षेत्र में कोठियों की लूट मची हुई है. लखनऊ में सेना के पास ट्रांस गोमती फायरिंग रेंज में 195 एकड़, अमौसी सेना क्षेत्र में 185 एकड़, कुकरैल फायरिंग रेंज में सौ एकड़, बख्शी का तालाब में 40 एकड़ और मोहनलालगंज क्षेत्र में 22 एकड़ ज़मीन है, लेकिन यह आंकड़ा केवल सेना के दस्तावेज़ों तक ही सीमित है. ज़मीनी असलियत भयावह है. इनमें से अधिकांश ज़मीनों पर अवैध कब्जा है. सेना कहती है कि कब्जा है, जबकि यह सेना का भ्रष्टाचार है.

लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर सेना की फायरिंग रेंज के बड़े हिस्से की प्लॉटिंग हो गई और ज़मीनें बिक गईं. आवास विकास परिषद ने गोसाईंगंज थाने में प्रॉपर्टी डीलरों के ख़िलाफ़ मुक़दमा भी दर्ज कराया था, लेकिन दुस्साहस यह कि ज़मीन से आवास विकास परिषद के उस बोर्ड को उखाड़ फेंका गया, जिस पर लिखा था कि यह सेना की फायरिंग रेंज की ज़मीन है. ट्रांस गोमती फायरिंग रेंज की 90 एकड़ और अमौसी में पांच एकड़ ज़मीन पर भू-माफियाओं का कब्जा है. कुकरैल में तो सेना की 23 एकड़ ज़मीन पर बाकायदा बड़ी इमारतें और दुकानें बन चुकी हैं. उसी अतिक्रमित ट्रांस गोमती फायरिंग रेंज और कुकरैल फायरिंग रेंज का बहाना बनाकर सेना ने विकास के काम पर रोक लगा रखी है. छावनी से बाहर सेना की क़रीब छह सौ एकड़ ज़मीन प्रदेश सरकार से विवाद में फंसी हुई है. कहीं पर आवास विकास परिषद से लफड़ा है, तो कहीं सीधे सरकार से क़ानूनी भिड़ंत चल रही है. कानपुर में सेना की ज़मीन पर अलग-अलग इलाकों में छह बस्तियां बसी हुई हैं. कानपुर शहर के वार्ड नंबर एक में भज्जीपुरवा, लालकुर्ती, गोलाघाट, पचई का पुरवा जैसी कई बस्तियां बसी हुई हैं. बंगला नंबर 16 और बंगला नंबर 17 की ओर जाने वाले दो इलाकों में अवैध बस्तियां बसी हुई हैं, लेकिन उन्हें हटाने की किसी को फुर्सत नहीं है. कानपुर छावनी क्षेत्र में बना आलीशान स्टेटस क्लब सैन्य संपत्ति की अनियमितताओं का गवाह है. स्टेटस क्लब का स्टेटस भव्य होटल की तरह है. पंच सितारा सुविधाओं वाले दर्जनों कमरों, विशाल वातानुकूलित हॉल और क्लब के मालिक की इससे हो रही अंधाधुंध कमाई किसके बूते पर हो रही है? सैन्य क्षेत्र में यह क्लब कैसे अस्तित्व में आया और इस एवज में किसने क्या-क्या पाया, इसका जवाब कौन देगा?

गोरखपुर में गगहा बाज़ार स्थित सेना के कैम्पिंग ग्राउंड की 33 एकड़ ज़मीन में से क़रीब दस एकड़ ज़मीन पर कब्जा हो चुका है. गोरखपुर के ही सहजनवा, महराजगंज ज़िले के पास रनियापुर और नौतनवां में सेना की ज़मीनों पर अवैध कब्जे हैं. इलाहाबाद शहर में सेना के परेड ग्राउंड की क़रीब 50 एकड़ ज़मीन पर अवैध कब्जे हैं, यहां अवैध बस्तियां आबाद हैं. 32 चैथम लाइंस, 6 चैथम लाइंस और न्यू कैंट में भी सेना की ज़मीन पर अवैध कब्जा है. मेरठ छावनी क्षेत्र तो मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं सिविल कॉलोनी में तब्दील हो चुका है.

हक़ीक़त यह है कि मध्य कमान मुख्यालय सो रहा है. अफसर अराजक होकर अनापेक्षित काम में लगे हैं, घरों में झांक रहे हैं और आपराधिक अभित्रास (क्रिमिनल ट्रेसपास) जैसे कृत्यों में लगे हैं. दूसरी तरफ़, सेना के मध्य कमान की ज़मीनें हड़पी जा रही हैं, ग़ायब हो रही हैं. मध्य कमान मुख्यालय का सैन्य क्षेत्र नेताओं, दलालों और संदेहास्पद किस्म के बाहरी लोगों को दे दिए जाने के बावजूद हर तरफ़ चुप्पी सधी है. सैन्य क्षेत्र में मॉल बन चुके हैं और असैनिक इमारतें बन रही हैं. सैन्य क्षेत्र की प्लॉटिंग कर उसे आम लोगों के हाथों बेचा जा रहा है. शहीद स्थल तक को ध्वस्त करके वहां कॉलोनी बना दी गई. बीएन लहरी मार्ग स्थित सेना की ज़मीन पर शहीद स्थल बना था. शहीद सैनिकों की स्मृति में यहां स्तंभ बन चुका था, शिलालेख वगैरह भी लग गए थे. सौंदर्यीकरण का कुछ काम बाक़ी था, लेकिन अचानक काम थम गया. लोग यहां शहीदों को श्रद्धांजलि देने की बाट ही जोहते रह गए. अचानक एक दिन शहीद स्तंभ ध्वस्त कर दिया गया, शिलालेख वग़ैरह ग़ायब कर दिए गए और सेना की इस ज़मीन पर कॉलोनी शक्ल लेने लगी. फिर कुछ दिनों के बाद गेट पर गोमती एनक्लेव का बोर्ड लग गया, फ्लैट्स बन गए और लोगों को एलॉट भी हो गए. यह भारतीय सेना की मध्य कमान का गौरवपूर्ण दृश्य है! ■

मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को इन सारी स्थितियों से अवगत कराते हुए कहा है कि सड़क या फ्लाईओवर बनाने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता भी नहीं है. सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित बंधे के ऊपर ही सड़क का निर्माण किया जाएगा. बाकी 330 मीटर लंबाई में फ्लाईओवर का निर्माण बंधे के बगल में नाले की ओर किया जाएगा, जिसमें सेना की अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होगी.

feedback@chauthiduniya.com

> सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2009–10 से लेकर 2012–13 तक सबसे अधिक चंदा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोप से आया. इसमें भी सबसे अधिक पैसा अकेले दिल्ली राज्य में आता है. एनजीओ के पास जो रकम विदेशों से आ रही है, उन देशों में सबसे आगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है. उसके बाद जर्मनी और यूके का नंबर आता है. इन तीन देशों समेत दस पश्चिमी देश पिछले कई सालों से एनजीओ की दानदाता सूची में टॉप पर हैं.

एनजीओ पर शिकंजा

कितना सही, कितना ग़लत

> गृह मंत्रालय के मुताबिक, 16 अक्टूबर, 2014 को उक्त एनजीओ को नोटिस जारी करके कहा गया कि वे एक महीने के भीतर अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल कर बताएं कि उन्हें कितना विदेशी चंदा मिला, उस चंदे का क्या स्रोत है, किस उद्देश्य के लिए उसे हासिल किया गया और किस तरीके से विदेशी चंदे का इस्तेमाल किया गया? 10 हज़ार से अधिक एनजीओ में से मात्र 229 ने जवाब दिया. सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि शेष एनजीओ से जवाब नहीं मिला, इसलिए एफसीआरए के तहत जारी उनके पंजीकरण रद्द कर दिए गए. जिन 8,975 एनजीओ के पंजीकरण रद्द किए गए, उनमें से 510 ऐसे एनजीओ भी शामिल हैं, जिन्हें नोटिस भेजा गया था, लेकिन वह वापस लौट आया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

भारत में एनजीओ के प्रादुर्भाव के पीछे एक तर्क यह था कि चूंकि इतने बड़े देश में सरकार की प्रत्यक्ष मौजूदगी हर जगह नहीं हो सकती, इसलिए ग़ैर सरकारी संगठन सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मदद देने का काम करेंगे. यह सोच भारत जैसे विशाल देश के लिए सही भी है. कई सरकारी योजनाएं ऐसी हैं, जिन्हें ज़मीन पर प्रभावी रूप से उतारने के लिए सरकार के पास पर्याप्त मानव संसाधन एवं अन्य संसाधन उपलब्ध नहीं होते. खासकर, किसी कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक ईमानदार वाच–डॉग की ज़रूरत तो होती ही है. मीडिया ने चौथे खंभे के रूप में अपना रोल तो निभाया ही, इसी के साथ कई ऐसे मौक़े सामने आए, जब ये ग़ैर सरकारी संगठन भी आगे बढ़कर आए. मसलन, देश में सूचना का अधिकार क़ानून लागू कराने में किसान–मज़दूर शक्ति संगठन नामक एक संस्था की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता. उसी तरह हाल के वर्षों में मनरेगा जैसे कार्यक्रमों में जन–सुनवाई के ज़रिये भ्रष्टाचार के मामले सामने लाने में भी एनजीओ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में सिविल सोसायटी और स्वयंसेवी संस्थाओं ने भ्रष्ट तंत्र को उजागर भी किया है और जन–कल्याण, जन–जागरूकता जैसे काम भी किए हैं. लेकिन, इस पूरी तस्वीर का दूसरा पहलू भी है. इस वक्त देश में 25 लाख से भी अधिक एनजीओ रजिस्टर्ड हैं. अब इन लाखों–लाख संस्थाओं में किसने भारत के हित में काम किया और किसने विदेशी एजेंडे पर काम किया, इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल है. फिर भी, कई ऐसे संस्थान हैं, जिनकी गतिविधियां संदेहास्पद रही हैं. मसलन, फोर्ड फाउंडेशन, ग्रीनपीस जैसी संस्थाएं. इनके काम को लेकर काफी पहले से सवाल खड़े होते रहे हैं. कुछ समय पहले तक देश में चल रहे कई आंदोलनों में इनका पैसा, इनका एजेंडा होने की बात कही जा रही थी. शायद यही वजह है कि नई सरकार ने ऐसे हज़ारों एनजीओ और दानदाताओं पर लगाम कसने का निर्णय लिया. सरकार यह भी मानती है कि कई ऐसे एनजीओ हैं, जो पर्यावरण, आदिवासी अधिकार आदि के नाम पर विकास विरोधी माहौल बनाते हैं.

सरकार ने अपने ताजा निर्णय में विदेशी चंदा हासिल कर रहे हज़ारों ग़ैर सरकारी संगठनों पर कार्रवाई करने की बात कही है. सरकार ने तक़रीबन 9,000 एनजीओ के लाइसेंस विदेशी चंदा नियमन क़ानून (एफसीआरए) का उल्लंघन करने के संबंध में रद्द कर दिए हैं. एक आदेश में गृह मंत्रालय ने कहा कि साल 2009–10, 2010–11 और 2011–12 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल न करने वाले 10 हज़ार से अधिक एनजीओ को नोटिस जारी किए गए थे. गृह मंत्रालय के मुताबिक, 16 अक्टूबर, 2014 को उक्त एनजीओ को नोटिस जारी करके कहा गया कि वे एक महीने के भीतर अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल कर बताएं कि उन्हें कितना विदेशी चंदा मिला, उस चंदे का क्या स्रोत है, किस उद्देश्य के लिए उसे हासिल किया गया और किस तरीके से विदेशी चंदे का इस्तेमाल किया गया? 10 हज़ार से अधिक एनजीओ में से मात्र 229 ने जवाब दिया. सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि शेष एनजीओ से जवाब नहीं मिला, इसलिए एफसीआरए के तहत जारी उनके पंजीकरण रद्द कर दिए गए. जिन 8,975 एनजीओ के पंजीकरण रद्द किए गए, उनमें से 510 ऐसे एनजीओ भी शामिल हैं, जिन्हें नोटिस भेजा गया था, लेकिन वह वापस लौट आया.

दरअसल, कुछ समय पहले यह ख़बर आई थी कि ह्यूमैनिस्टिक इंस्टीट्यूट फॉर को–ऑपरेशन विद द डेवलपिंग कंट्रीज (हिवोस) ने गुजरात में अप्रैल 2008 से अगस्त 2012 तक कुछ एनजीओ को 13 लाख यूरो (तक़रीबन 10 करोड़) रुपये दिए, जिनमें से कुछ चर्चित ग़ैर–सरकारी संगठन, जैसे दिशा को दो लाख चौबीस हज़ार यूरो, गुजरात खेत विकास परिषद को दो लाख सात हज़ार यूरो, सफर को एक लाख चौरासी हज़ार यूरो, महिती को एक लाख चार हज़ार यूरो, स्वाति को पचासी हज़ार यूरो और उठान को तिरसठ हज़ार यूरो दिए गए. हिवोस दिल्ली एवं मुंबई स्थित कई एनजीओ को भी आर्थिक मदद करता है. मुंबई बेस्ड तीस्ता सीतलवाड़ द्वारा चलाया जा रहा एनजीओ और शबनम हाशमी के नेतृत्व में संचालित दिल्ली स्थित एनजीओ अनहद को भी हिवोस ने चार हज़ार यूरो दिए. सवाल यह है कि उक्त धनराशि क्यों दी गई? इस सवाल के जवाब में कई तर्क दिए जाते हैं. इनमें सही क्या है, ग़लत क्या है, यह तो जांच का विषय है, लेकिन इन सवालों की वजह से सरकार को इन संस्थाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का आधार तो मिल ही जाता है.

इसके अलावा आईबी ने भी सरकार को अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कई संस्थाएं (एनजीओ) देश विरोधी या कहें कि विकास विरोधी कार्यक्रम चला रही हैं, इनमें ग्रीन पीस जैसी संस्था का नाम प्रमुखता से लिया गया. सरकार ने ग्रीन पीस के

शीर्ष एनजीओ, जिनके लाइसेंस रद्द हुए

- वर्ल्ड विजन ऑफ इंडिया
- रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट
- एक्शन एड
- एसओएस चिल्ड्रेंस विलेज
- तिब्बतन चिल्ड्रेंस विलेज
- एक्शन इंडिया
- किसान सभा ट्रस्ट
- चिन्मय सेवा ट्रस्ट
- तरुण भारत संघ
- कबीर

शीर्ष दानदाता देश (2012–13, रुपये में)

अमेरिका	– 37,97,65,88,901
जर्मनी	– 10,89,56,14,405
ब्रिटेन	– 10,64,65,55,429
इटली	– 4,98,76,01,504
नीदरलैंड	– 3,81,40,77,774
स्विट्जरलैंड	– 3,64,00,62,151
स्पेन	– 3,38,31,89,304
कनाडा	– 3,01,47,26,972
ऑस्ट्रेलिया	– 2,24,98,13,688
फ्रांस	– 1,77,15,99,840

विदेशी चंदा पाने में बहुत पीछे हैं मुस्लिम संगठन

आम तौर पर यह माना जाता है और कहा भी जाता है कि देश के मुस्लिम संगठनों को दुनिया के विभिन्न मुस्लिम देशों से बहुत अधिक चंदा मिलता है, लेकिन यह सच नहीं है. अगर बात 2012–13 की करें, तो साफ़ होता है कि शीर्ष दस दानदाता देशों में एक भी मुस्लिम देश नहीं है. 2010–11 के दौरान भी यूएई, कतर और कुवैत जैसे देशों से आने वाला पैसा पश्चिमी देशों से आने वाले पैसों के मुकाबले नगण्य है. और, यह भी नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम देशों से आने वाले चंदे का सारा पैसा मुस्लिम संगठनों को ही जाता है. हां, यह ज़रूर है कि पश्चिमी देशों से मिलने वाले चंदे का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्रिश्चियन संस्थाओं को जाता है. सरकार ने जिन नौ हज़ार एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए हैं, उनमें भी अधिकतर क्रिश्चियन संस्थाएं हैं.

ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई भी की है. क़ानूनी तरीके से विदेशी योगदान नियमन क़ानून (एफसीआरए) के तहत देश में आने वाली धनराशि 1993–94 में 1,865 करोड़ रुपये से बढ़कर 2007–08 में 9,663 करोड़ रुपये यानी पांच गुनी से भी ज़्यादा हो गई. इस क़ानून के तहत पंजीकृत संस्थाओं की संख्या भी इस अवधि में 15,039 से बढ़कर 34,803 यानी दोगुनी से ज़्यादा हो गई. हालांकि, इनमें से 46 प्रतिशत संस्थाओं ने 2007–08 में अपना हिसाब गृह मंत्रालय को नहीं दिया. 2011 में भी यूपीए सरकार ने एक महीने में ही 4,139 एनजीओ पर विदेश से किसी प्रकार की सहायता राशि लेने संबंधी रोक लगाई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2009–10 से लेकर 2012–13 तक सबसे अधिक चंदा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोप से आया. इसमें भी सबसे अधिक पैसा अकेले दिल्ली राज्य में आता है. एनजीओ के पास जो रकम विदेशों से आ रही है, उन देशों में सबसे आगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है. उसके बाद जर्मनी और यूके का नंबर आता है. इन तीन देशों समेत दस पश्चिमी देश पिछले कई सालों से एनजीओ की दानदाता सूची में टॉप पर हैं. इनके अलावा भारतीय एनजीओ को कुछ अन्य देशों से भी मदद मिल रही है, जिनमें इटली, नीदरलैंड, स्पेन एवं स्विट्जरलैंड आदि हैं. इसके साथ ही कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यूएई भी भारतीय ग़ैर–सरकारी संगठनों के बड़े मददगारों में शामिल हैं. यह सही है कि इन देशों से मिलने वाली धनराशि ज़्यादातर क्रिश्चियन संस्थाओं के पास जाती है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम चलाते हैं. उन पर धर्म परिवर्तन कराने के भी आरोप लगते हैं, लेकिन उक्त आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह जांच का विषय है.

यूपीए सरकार के समय जब तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विरोध का मामला सामने आया था, तब आरोप लगे थे कि दुनिया के देशों और कॉरपोरेट के आपसी झगड़े की वजह से इस संयंत्र का विरोध हो रहा है. यह संयंत्र रूस की मदद से लगा है, इसलिए अमेरिका और फ्रांस की कंपनियां भारत में ग़ैर–सरकारी संगठनों के ज़रिये इसका विरोध करा रही हैं. इसी तरह महाराष्ट्र का जैतापुर परमाणु संयंत्र फ्रांस के सहयोग से लगना है, तो उसके विरोधी देश और कंपनियां संयंत्र के ख़िलाफ़ ग़ैर–सरकारी संगठनों के ज़रिये हंगामा करा रही हैं. यह भी ख़बर आई कि गुजरात में दंगा पीड़ितों की मदद के लिए बनी संस्था ने चंदे के पैसों में गबन किया है. इस सच्चाई से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि ज़्यादातर एनजीओ पैसों का दुरुपयोग करते हैं. आम लोगों के हितों के बहाने परियोजनाएं रोकने की अनेक घटनाएं हुई हैं. कहने का आशय यह है कि एनजीओ अच्छे–बुरे यानी दोनों तरह के कामों में शामिल रही हैं. इसलिए इस वक्त अगर सरकार ऐसे एनजीओ के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है, तो वह तथ्यों के आधार पर है और उसकी आलोचना नहीं की जा सकती. लेकिन, इसी के साथ एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या कुछ संस्थाओं–संगठनों पर लगे आरोपों की वजह से सारे एनजीओ को कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिए? जाहिर है, ऐसा करना सही नहीं होगा. सारे एनजीओ भ्रष्ट हैं, यह कहना भी सही नहीं है. ज़रूरत इस बात की है कि एनजीओ के संचालन से जुड़े नियम–क़ानून दुरुस्त किए जाएं, ताकि देश के भीतर अच्छे एनजीओ और भी बेहतर ढंग से काम कर सकें. और, जो ऐसा न करें, उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके.■

शीर्ष दस राज्य, जिन्हें सबसे अधिक विदेशी चंदा मिला (2012–13)

दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा.

कंपनियों की बेरहमी और शासन–प्रशासन की उपेक्षा के बीच विस्थापित किसानों आदिवासियों की पीड़ा और उनके संघर्ष पर विचार करते हुए करीब 150 साल पहले एक आदिवासी समुदाय के मुखिया द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति को संबोधित भाषण का बरबस स्मरण हो जाता है. 1855 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन पीयर्स ने सिएटल के मूल निवासियों के मुखिया के पास प्रस्ताव भेजा कि सरकार उनकी जमीन खरीदना चाहती है. राष्ट्रपति के दूत ने यह पेशकश मुखिया के सामने रखी. अपने समुदाय की मौजदगी में मुखिया ने जो जवाब दिया वह पत्र आज पर्यायवरणविदों के लिए आधार पत्र का रूप ले चुका है.

मध्य प्रदेश

आर-पार की लड़ाई की तैयारी में विस्थापित

सिंगरौली के निवास गांव में 18 मई को जे पी पावर प्लांट, डीबी पावर प्लांट और आर्यन पावर प्लांट के विस्थापित किसानों की महापंचायत और 19 मई को निगरी में जे पी पावर प्लांट के गेट पर किसानों का धरना था. सीधी से लगभग 35 किलोमीटर दूर निगरी जाते समय सड़क के दोनों किनारे सरई के ऊंचे-ऊंचे पेडों का जंगल और बीच-बीच में पक्षियों के चहचहाने की आवाज का सुखद एहसास बेहद टूटी सड़क पर रेंगती जीप में लगने वाले हिचकोलों की तकलीफ महसूस नहीं होने दे रहा था. टिकरी पहुंचते ही जे पी प्लांट की दो विशाल टंकियां और संयंत्र की इमारत दिखाई देती है. पावर प्लांट के गेट से आगे बढ़ने पर कुछ ही दूरी पर एक और ऊंचा टैंक दिखता है. स्थानीय कार्यकर्ता सचिन ने बताया कि यह जेपी का सीमेंट प्लांट है, जिसका निर्माण अवैध है. अवैध कैसे? यह पूछने पर कहा कि भूमि का अधिग्रहण पावर प्लांट के लिए हुआ था लेकिन जेपी ने यहां सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट भी लगा लिया.

संजय अस्थाना

मध्य प्रदेश इन दिनों तेजी से बदलाव की दौर से गुजर रहा है. 50 से ज्यादा पावर प्लान्ट स्थापित हो रहे हैं. कुछ लग चुके हैं, कुछ निर्माणाधीन हैं और कुछ प्रस्तावित हैं. विकास की यह तस्वीर आकडों और इंटरनेट पर देखी जा सकती है. यहां एक दूसरी तरह का बदलाव इससे कहीं तेज गति से हो रहा है. वह है, इन पावर प्लान्ट्स की वजह से अपना घर और खेत गंवा चुके किसानों और आदिवासियों की सोच में हो रहे बदलाव और उनकी सामाजिक–राजनीतिक सक्रियता का. 43 डिग्री सेल्सियस तापमान में सुबह आठ बजे से शाम 4 बजे तक खुले आसमान के नीचे तपती दोपहर में गर्म हवा को झेलते हुए जे पी पावर प्लान्ट के गेट पर धरने में बैठे पांच सौ से ज्यादा विस्थापित महिलाओं, पुरुषों और नौजवानों को मुठ्ठी भींचे, हाथ लहराते हुए. लड़ेंगे तो जीतेंगे, का नारा लगाते देख, उनकी इस बात पर यकीन होने लगता है कि उन्होंने अब आर–पार की लडाई का मन बना लिया है. यह वह बदलाव है जिसे देखने के लिए मध्य प्रदेश के विन्ध्य क्षेत्र में जाना होगा.

सिंगरौली के निवास गांव में 18 मई को जे पी पावर प्लांट, डीबी पावर प्लांट और आर्यन पावर प्लांट के विस्थापित किसानों की महापंचायत और 19 मई को निगरी में जे पी पावर प्लांट के गेट पर किसानों का धरना था. सीधी से लगभग 35 किलोमीटर दूर निगरी जाते समय सड़क के दोनों किनारे सरई के ऊंचे–ऊंचे पेडों का जंगल और बीच–बीच में पक्षियों के चहचहाने की आवाज का सुखद एहसास बेहद टूटी सड़क पर रेंगती जीप में लगने वाले हिचकोलों की तकलीफ महसूस नहीं होने दे रहा था. टिकरी पहुंचते ही जे पी प्लांट की दो विशाल टंकियां और संयंत्र की इमारत दिखाई देती है. पावर प्लांट के गेट से आगे बढ़ने पर कुछ ही दूरी पर एक और ऊंचा टैंक दिखता है. स्थानीय कार्यकर्ता सचिन ने बताया कि यह जेपी का सीमेंट प्लांट है, जिसका निर्माण अवैध है. अवैध कैसे? यह पूछने पर कहा कि भूमि का अधिग्रहण पावर प्लांट के लिए हुआ था लेकिन जेपी ने यहां सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट भी लगा लिया.

निवास स्थित हायर सेकेन्ड्री स्कूल के मैदान पर किसानों की महापंचायत थी. पंचायत के आयोजक टोको–रोको–ठोको क्रांति मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने तयशुदा समय प्रात: दस बजे माइक संभाल लिया. मंच पर विभिन्न किसान संगठनों, क्षेत्र में सक्रिय सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव तथा बहुजन समाज पार्टी के नेता भी मौजूद थे. सामने आस–पास के गांव के करीब तीन चार सौ किसान थे, जो धूप से बचने के लिए दो विशालकाय पेडों की छांव में बैठे थे.

सभा की शुरुआत में ही पंचायत की अध्यक्षता कर रहे उमेश तिवारी ने विस्थापितों की समस्याओं, कंपनी प्रबंधन के अन्याय और शासन–प्रशासन की उदासीनता का उल्लेख किया. जिसने जेपी प्लांट के विस्थापितों पर दायर फर्जी मुकदमें वापस लेने, रोजगार से निकाले गए 125 लोगों को वापस काम पर रखने, अनुबंध के अनुसार नौकरी देने का वायदा पूरा करने, आदिवासी गांव, मछुआरी टोला जाने वाले बंद रास्ते को पुन: खोलने जैसी मांगें शामिल हैं. उन्होंने बताया कि विस्थापितों के लिए कंपनी ने जो आवास कॉलोनी बनाई है वह अधिग्रहित भूमि पर ही प्लांट से सटी हुई है. वहां कोई बुनियादी सुविधायें नहीं हैं. हर वक्त इतना शोर होता है कि वहां चैन से रह पाना नामुमकिन है. जबकि साल 2002 की नीति के अनुसार वैकल्पिक कॉलोनी में विस्थापितों को आवास का मालिकाना हक मिलना चाहिए था. 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए डीबी पावर प्लांट द्वारा 2008 में किसानों से जमीन ली गई थी. लेकिन, आज तक न तो प्लांट लगा और न ही किसानों को उनकी जमीन वापस मिली. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव कामरेड बादल सरोज ने गोपद नदी पर जेपी प्लांट द्वारा बनाए गए डैम पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि शासन ने केवल 6 मीटर की इजाजत दी थी लेकिन कंपनी ने 11 मीटर ऊंचा बैराज बना लिया. उन्होंने कहा कि इस जल चोरी के खिलाफ संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि शासन डैम की ऊंचाई 6 मीटर तक नहीं करवा देता.

प्रदेश में किसानों के बीच गहरी पकड़ रखने वाले भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्काजी ने कहा कि सरकार किसानों को दो तरफा लूट रही है. एक तरफ तो अधिग्रहण के जरिए उनकी जमीन छीन रही है तो दूसरी तरफ उनकी बर्बाद फसल का मुआवजा नहीं दे रही है. किसानों से ऋण पर 14 फीसदी तक ब्याज वसूला जा रहा है. फसल की बर्बादी पर बीमा राशि के भुगतान में कोताही बरती जा रही है. खेत गिरवी रखने वाले साहूकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है. किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ सुनीलम ने किसानों के मन से कंपनी का और शासन का खौफ निकालने की कोशिश की.

महापंचायत की कार्रवाई चल रही थी तभी नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री और भूमि अधिकार के लिए संघर्ष का प्रतिरूप बन चुकी मेधा पाटकर पहुंची. अब तक पंचायत में शिरकत करने वालों की संख्या बढ़ कर एक हजार से अधिक हो चुकी थी. सुश्री पाटकर ने नारा दिया भूमि अधिग्रहण नहीं, भू–अधिकार चाहिए. मंच से दूर बैठी महिलाओं को उन्होंने मंच के शमियाने में बुलाया और कहा आप आंदोलन की ताकत हैं. बेखौफ होकर लड़िए. नारा दिया लड़ेंगे तो जीतेंगे. निहायत आत्मीय ढ़ंग से उन्होंने जल, जंगल जमीन पर उनके हक की बात की. कहा कंपनियों द्वारा की जा रही पानी चोरी के लिए लड़ना होगा. यह एक लंबी लड़ाई है. बड़े कॉरपोरेट और सरकार मिलकर देश की वन संपदा, जल संपदा और खनिज संपदा को लूट रहे हैं. एक के बाद एक कई उदाहरण देकर उन्होंने विस्थापितों में भरोसा पैदा करने की कोशिश की कि लड़ोगे तो जीतोगे. मध्य प्रदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहां प्रचुर प्राकृतिक संपदा है. यह संपदा ही यहां के किसानों–आदिवासियों के लिए अभिशाप बन गई है. आज हर तरफ लूट मची है. यहां किसानों और आदिवासियों को उनकी अपनी जमीन और जंगल से बेदखल किया जा रहा है. उन्होंने केंद्र और प्रदेश की मौजूदा सरकारों पर प्रहार करते हुए कहा कि विस्थापितों के लिए जमीन नहीं है और उद्योगपतियों को छूट है कि वे कहीं भी कोई भी भूमि ले सकते हैं. ऐसा कहीं किसी देश में नहीं होता. पानी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नदियों को यह कहकर बांधा जाता है कि बिजली मिलेगी. सिंगरौली में इतनी बिजली पैदा होती है, लेकिन यहां अंधेरा है. बांध तो बन जाते हैं लेकिन नदी गायब हो जाती है. जरूरत नदियों का अस्तित्व बचाने की है. पानी का नियोजन कैसे हो यह एक चुनौती है. आर्यन पावर प्लांट के विस्थापितों से सीधा संवाद करते हुए मेधा पाटकर ने उनसे अपनी कब्जे की अधिगृहित भूमि जोतने को कहा. उल्लेखनीय है कि सीधी जिले के भुमका में आर्यन पावर प्लांट के लिए भुमका एवं मूसामूड़ी के किसानों की जमीन बिना उनकी जानकारी के फर्जी ग्राम सभा के आधार पर वर्ष 2009 में अधिग्रहित की गई थी. किसानों ने भूमि का मुआवजा भी नहीं लिया गया है. इस सिलसिले में शासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सिंह ने कहा कि किसानों की विभिन्न समस्याओं व चुनौतियों से पार पाने के लिए स्थानीय स्तर पर चल रहे आंदोलनों को व्यापक बनाना होगा. उनके बीच एकजुटता और समन्वय जरूरी है. इस दिशा में किसान मंच ने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न किसान संगठनों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है. पिछले महीने दिल्ली में भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ हुई रैली इसकी एक शुरूआती कड़ी है. उन्होंने समाजवादियों और वामपंथियों से पूरी ताकत के साथ आगे आने की अपील की. प्रदेश में किसानों के बीच गहरी पकड़ रखने वाले भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्काजी ने कहा कि सरकार किसानों को दो तरफा लूट रही है. एक तरफ तो अधिग्रहण के जरिए उनकी जमीन छीन रही है तो दूसरी तरफ उनकी बर्बाद फसल का मुआवजा नहीं दे रही है. किसानों से ऋण पर 14 फीसदी तक ब्याज वसूला जा रहा है. फसल की बर्बादी पर बीमा राशि के भुगतान में कोताही बरती जा रही है. खेत गिरवी रखने वाले साहूकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है. किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ सुनीलम ने किसानों के मन से कंपनी का और शासन का खौफ निकालने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि मुकदमों और जेल से भयभीत होने की जरूरत नहीं. अहिंसक तरीके से आंदोलन जारी रखें. आंदोलन का मंत्र है मारेंगे नहीं, मानेंगे भी नहीं. यही भूमि अधिकार आंदोलन की ताकत है. पंचायत को सीपीआई के प्रदेश सचिव अरविन्द श्रीवास्तव, ईश्वरचन्द्र त्रिपाठी, राम लल्लू गुप्ता समेत एक दर्जन से अधिक वक्ताओं ने संबोधित किया.

कंपनियों की बेरहमी और शासन–प्रशासन की उपेक्षा के बीच विस्थापित किसानों आदिवासियों की पीड़ा और उनके संघर्ष पर विचार करते हुए करीब 150 साल पहले एक आदिवासी समुदाय के मुखिया द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति को संबोधित भाषण का बरबस स्मरण हो जाता है. 1855 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन पीयर्स ने सिएटल के मूल निवासियों के मुखिया के पास प्रस्ताव भेजा कि सरकार उनकी जमीन खरीदना चाहती है. राष्ट्रपति के दूत ने यह पेशकश मुखिया के सामने रखी. अपने समुदाय की मौजदगी में मुखिया ने जो जवाब दिया वह पत्र आज पर्यायवरणविदों के लिए आधार पत्र का रूप ले चुका है. मुखिया के भाषण में मूल निवासियों द्वारा जंगल–जमीन छोड़े जाने का दर्द ही नहीं बल्कि कुछ बुनियादी सवाल भी हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं मुखिया ने कहा आपने हमारी जमीन खरीदने की पेशकश की है. यह आपकी भलमनसाहत है. हम जानते हैं यदि हम नहीं देंगे तो आप बलपूर्वक लेंगे, लेकिन कोई हवा, धूप और पानी कैसे खरीद सकता है. आपके लिए यह सिर्फ भूमि है जिस पर आप फैक्ट्री लगायेंगे, गाड़ियां दौड़ायेंगे. आपके लिए यह सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा है, क्योंकि आपने कभी यहां के पेड़ों की छांव, धरती की तपिश, सुबह की धूप में चमकती ओस का नूर और जंगल से आती हवा की शीतलता को महसूस नहीं किया है. हमारे लिए यह धरती हमारी मां है यहां हमारे पूर्वज दफन हैं और हमारी नाल गड़ी है. हमारे लिए यह पवित्र है, हमारा जीवन है.

इसके एक साल बाद सीएटल के मुखिया और अमेरिकी सरकार के बीच अनुबंध हुआ जिसके तहत उनकी अधिकांश भूमि पर सरकार का कब्जा हो गया. दस साल बाद सरकार ने एक क़ानून बनाकर सीएटल में वहां के मूल निवासियों के रहने को गैरक़ानूनी करार दे दिया. कहानी आज भी वैसी ही है सिर्फ समय बदल गया है कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है. आश्चर्य मत करियेगा यदि विस्थापित किसान और आदिवासी उसे बदलकर एक नया इतिहास रच दें.■

feedback@chauthiduniya.com

अदालत ने बड़े पैमाने पर वनों के कटान पर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि आदिवासियों के तीखे विरोध के बावजूद इस परियोजना के लिए बहुत बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए, जो 1980 के वन संरक्षण क़ानून का सीधा उल्लंघन है. कनहर बांध परियोजना की धनराशि में हो रहे घोटाले को भी अदालत ने बेनकाब किया कि शुरुआत में परियोजना का कुल लागत आकलन 27.75 करोड़ रुपये किया गया, जो 1979 में अंतिम स्वीकृति देने तक 69.47 करोड़ रुपये हो गया. केंद्रीय जल आयोग की 106वीं बैठक में 14 अक्टूबर, 2010 में इस परियोजना की लागत 652.59 करोड़ रुपये आंकी गई, जो अब बढ़कर 2259 करोड़ रुपये हो गई है.

किसान : न खेत को पानी, न हाथ को काम

जगमोहन सिंह राजपूत

यह किसानों के लिए भयावह समय है. आज कोई उन्हें यह बताने की स्थिति में नहीं है कि अगले दो महीनों में जीवन व प्रकृति के सामान्य चक्र में कितनी बाधाएं और विविधताएं झेलनी पड़ेंगी. मौसम विभाग ही नहीं, विज्ञान एवं तकनीकी की भी अपनी सीमाएं हैं. किसानों का ही एकमात्र ऐसा वर्ग है, जो अन्य किसी के मुक़ाबले कम से कम आवश्यकताओं की पूर्ति करके जीवन जीने का आदी है, जो श्रम को धर्म मानता है, जो कभी परिवार के लिए रोटी की चिंता से मुक्त नहीं हो पाता. उसे सिंचाई के पानी के लिए आकाश की ओर देखना पड़ता है. जब हम आज़ाद हुए थे, तब किसान नेपथ्य में नहीं था. आज भी उस समय का नारा कुछ लोगों को याद है, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम. साठ वर्षों बाद भी अरबों रुपये की सिंचाई योजनाओं एवं परियोजनाओं के बावजूद केवल 35 प्रतिशत खेतों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है. ये सरकारी आंकड़े हैं, इनमें कितना वास्तविक रूप से सही है, यह अनुमान लगाना संभव नहीं है.

लगभग दो साल पहले महाराष्ट्र में एक बड़ा सिंचाई घोटाला उजागर हुआ था. तकनीकी तौर पर तत्कालीन उप-मुख्यमंत्री बेदाग आरोप-मुक्त हो गए. उन्होंने सिंचाई के लिए किसानों को जो उपक्रम सुझाया था, उसे न दोहराना संभव है और न याद करना उपयुक्त है. नेताओं की निगाह में किसानों की क्या स्थिति है, उसे वह प्रकरण पूरी तरह उजागर कर गया था. किसानों की याद अधिकांश राजनेताओं को केवल चुनाव के पहले आती है. चुनाव के कुछ पहले रणनीति बनती है कि कैसे उन्हें अपने पाले में लाया जाए. ठीक वैसे ही, जैसे एक साथ एक बाड़े में भेड़-बकरियों को लाया जाता है. क्या चारा डाला जाए. मुखियाओं को साधना, दो-तीन दिनों पहले नकदी बांटना, शराब की बोतलें उपलब्ध कराना, बाहुबलियों का इस्तेमाल आदि सारे उपाय अपनाए जाते हैं, जो चुनाव आयोग की सारी सख्ती पर भारी पड़ते हैं. जीवन की जटिलताओं से दूर और नेताओं के चुनावी तिकड़मों से अनभिज्ञ किसान, मज़दूर, कामगार जब एक बड़े आदमी को हाथ जोड़कर, झुककर, विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनकर अपने सामने रिरियाता देखता है, तब वह पिघल जाता है. मान लेता है कि यह सब कुछ ईमानदारी से कहा जा रहा है. राजनीति में कुटिलता जिस तेजी से बढ़ी है, उसे वह आज तक नहीं जान सका है.

विकासशील देशों के सामने संभवत: सबसे बड़ी समस्या विकास की अवधारणा के निर्धारण की रही है. स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधाओं ने इस पर विचार-विमर्श किया. इसका महत्वपूर्ण सूत्रपात तो 1909 में हिंद स्वराज के सामने आने से हुआ. जब चंपारण में गांधी जी ने जाकर स्थिति देखी, संघर्ष प्रारंभ कर उसका नेतृत्व किया, तब देश ही नहीं, विश्व भर ने जाना कि निलहे किसान किस तरह दासों सरीखा जीवन निम्नतम स्तर पर जीने को मजबूर थे. वे अपनी ज़मीन पर वही उगा सकते थे, जिसका आदेश सरकार दे. निरीहता की इससे बदतर स्थिति और क्या हो सकती थी? तब भी गांधी जी ने तत्कालीन समस्या के समाधान के साथ-साथ दीर्घकालीन व्यवस्था की आवश्यकता का महत्व समझा था. उन्होंने उन कठिन परिस्थितियों में वहां तीन प्राइमरी स्कूल खोले. अध्यापक गुजरात और स्वयंसेवक महाराष्ट्र से आएंगे, लेकिन उनके रहने-खाने का प्रबंध गांव के लोगों को ही करना होगा. यानी उस नारकीय जीवन से लोगों को, आगे की पीढ़ियों को निकालने के कारगर और स्थायी समाधान का एक ही स्रोत है, शिक्षा!

1922 में गांधी जी ने इसे दूसरे ढंग से कहा था, एक पत्र में कि स्वराज आने पर भी लोगों को प्रसन्नता नहीं मिलेगी, क्योंकि चार भार उन पर छा जाएंगे यथा अन्याय, अमीरों का त्रासद शोषण, प्रशासन का बोझ और चुनावों की खराबियां! आशा की किरण केवल शिक्षा ही होगी. उन्होंने बुनियादी तालीम की जो संकल्पना की थी, उसमें हाथ से काम करने को कितनी प्रमुखता दी गई थी, यह सभी जानते हैं. गांधी जी भारत को, भारत की संस्कृति एवं परंपरा को जानते थे. उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर सारे देश का भ्रमण किया था, भारत को जानने के लिए. वह भारत की कृषि, किसान एवं उसकी आशाओं-आकांक्षाओं से उसी के स्तर पर परिचित थे. वह भारत के गांवों की ग़रीबी आत्मसात कर चुके थे. उन्होंने अपना पहनावा बदला, ताकि भारत की असली तस्वीर कभी उनकी आंखों से ओझल न हो. उनके नामित उत्तराधिकारी पंडित जवाहर लाल नेहरू का लालन-पालन, विचार, दृष्टिकोण और सभी कुछ दूसरे ढंग का था. उन्होंने भारत के गांव के स्कूल में नहीं, बल्कि एक आयरिस गवर्नेस से प्रारंभिक शिक्षा पाई और फिर यूरोप में युवा हुए.

पांच अक्टूबर, 1945 को गांधी जी ने पंडित नेहरू को एक प्रसिद्ध पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने गांव को विकास योजनाओं का केंद्र बनाने की गुजारिश की थी. गांधी जी हमेशा इसी विचार के रहे, मगर नेहरू जी सोवियत संघ के कलेक्टिव फॉर्मिंग मॉडल से प्रभावित रहे. गांधी जी ने लिखा था, स्वतंत्र भारत में (हमें यह मानना पड़ेगा) लोग गांवों में रहेंगे, कस्बों में नहीं. झोंपड़ियों में, न कि महलों में. करोड़ों लोग शहरों एवं महलों में शांतिपूर्वक नहीं रह पाएंगे. ऐसे में वे असत्य और हिंसा का सहारा लेंगे. इसी पत्र में गांधी जी ने अपना विश्वास दोहराया कि सत्य व अहिंसा के बिना केवल मानवता का विनाश ही होगा. और, यह सत्य व अहिंसा गांव की सादगी में ही उपलब्ध होंगे. उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि मनुष्य को वास्तविक आवश्यकता पूर्ति से संतुष्ट और आत्मनिर्भर होना चाहिए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि वह यह नहीं कह रहे हैं कि भारत के गांव ऐसे ही बने रहेंगे, जैसे आज हैं. मेरे भी सपने हैं, जिनमें परिवर्तन के लिए स्थान है. पंडित नेहरू ने नौ अक्टूबर, 1945 को गांधी जी को पत्र का उत्तर लिखा. उन्होंने उसमें स्पष्ट कहा कि सामान्यत: गांव बौद्धिक एवं सांस्कृतिक पक्ष में पिछड़े हुए हैं. मैं नहीं समझता कि गांव में सत्य व अहिंसा का प्रतिपादन होता है. संकुचित दिमाग वाले लोगों के असत्य और हिंसक होने की अधिक संभावना है.

यह कहना अक्षरश: सच होगा कि कांग्रेस आज भी किसानों के प्रति यही दृष्टिकोण रखती है. यही दृष्टिकोण भारत की कृषि और किसानों की वर्तमान स्थिति के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार है. गांधी जी पंडित नेहरू के मोह को वस्तुपरकता की सीमा पर नहीं तौल पाए और पंडित नेहरू कलेक्टिव फॉर्मिंग के मोहजाल से नहीं निकल पाए. 1957 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन तक वह यह प्रयास करते रहे. वहीं चौधरी चरण सिंह ने साहस पूर्ण विरोध किया. वह किसान नेता के रूप में उभरे. अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी भारत के किसानों का पक्ष रखा. नेहरू जी की नहीं चली, मगर सरकार तो उन्हीं की थी और उसका अर्थ अत्यंत व्यापक व गहन होता है. सत्तर साल पहले के इन दो पत्रों में जो विरोधाभास स्पष्ट होता है, क्या उस पर पुनर्विचार का समय नहीं आया है? अब बड़े शहरों, बड़े कारखानों, उत्तराखंड जैसी आपदाओं, शहरीकरण, गांव उजड़ने, बेरोज़गारी, बढ़ती हिंसा और अविश्वास का अनुभव है हमारे पास. विकास का अनुभव भी है. किसान इसमें कहां है, कहां होगा, यह देश को तय करना है. पहले ही बहुत देर हो चुकी है. ■

(लेखक एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

कनहर बांध विवाद

एनजीटी के फ़ैसले का क्या असर होगा

चौथी दुनिया ब्यूरो

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में ग़ैर-क़ानूनी रूप से निर्मित कनहर बांध और अवैध तरीके से किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का मामला पिछले एक माह से गरमाया हुआ है. बीते 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रदर्शन कर रहे आदिवासी आंदोलनकारी अकलू चेरो पर चलाई गई गोली उसके सीने से आर-पार हो गई और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. 18 अप्रैल को एक बार फिर आदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा सात मई, 2015 को दिए गए फ़ैसले में कनहर बांध का मौजूदा काम पूरा करने की बात कही गई है, लेकिन नए निर्माण पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है. कनहर बांध निर्माण के ख़िलाफ़ यह याचिका ओडी सिंह एवं देबोदित्य सिन्हा द्वारा एनजीटी में दिसंबर 2014 में दायर की गई थी, जिसमें याचियों द्वारा पेश किए गए तथ्य न्यायालय ने सही करार दिए हैं. कनहर बांध परियोजना के लिए वन-अनुमति नहीं है. अदालत ने यह भी माना कि परियोजना चालकों के पास न तो 2006 का पर्यावरण अनुमति पत्र है और न 1980 का वन अनुमति पत्र. अदालत ने यह तथ्य भी स्थापित किया कि 2006 और 2014 में बांध परियोजना का काम शुरू नहीं हुआ था, इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत बिना पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति और पर्यावरण प्रभाव आकलन के नोटिफिकेशन के नहीं हो सकती.

सोनभद्र ज़िला प्रशासन द्वारा लगातार यह कहा जा रहा था कि बांध से प्रभावित होने वाले गांवों में आदिवासी की संख्या नाममात्र है. यह तथ्य भी अदालत द्वारा ग़लत ठहराया गया और कहा गया कि इस परियोजना से बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा, जिसमें सबसे बड़ी संख्या आदिवासियों की है. 25 गांवों के लगभग 7,500 परिवार विस्थापित होंगे, जिनके पुनर्वास की योजना बनाने की आवश्यकता पड़ेगी. अदालत ने अपने फ़ैसले में सबसे गहरी चिंता पर्यावरण के संदर्भ में जताई है, जिसमें कहा गया है कि कनहर नदी सोन नदी की एक मुख्य उप-नदी है, जो गंगा नदी की मुख्य उप-नदी है. रिहंद एवं बाणसागर जैसे कई बांधों के निर्माण और पानी की धारा में परिवर्तन के चलते सोन नदी का अस्तित्व भी आज काफी ख़तरे में है. बड़े पैमाने पर मछली की कई प्रजातियां लुप्त हो गई हैं और विदेशी मछली प्रजातियों ने उनकी जगह ले ली है. इस निर्माण के चलते नदी के बहाव, गति, गहराई, तल, पारिस्थितिकी और मछलियों के प्राकृतिक वास पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है.

अदालत ने बड़े पैमाने पर वनों के कटान पर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि आदिवासियों के तीखे विरोध के बावजूद इस परियोजना के लिए बहुत बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए, जो 1980 के वन संरक्षण क़ानून का सीधा उल्लंघन है. कनहर बांध परियोजना की धनराशि में हो रहे घोटाले को भी अदालत ने बेनकाब किया कि शुरुआत में परियोजना का कुल लागत आकलन 27.75 करोड़ रुपये किया गया, जो 1979 में अंतिम स्वीकृति देने तक 69.47 करोड़ रुपये हो गया. केंद्रीय जल आयोग की 106वीं बैठक में 14 अक्टूबर, 2010 में इस परियोजना की लागत 652.59 करोड़ रुपये आंकी गई, जो अब बढ़कर 2259 करोड़ रुपये हो गई है. उत्तर प्रदेश सरकार एवं सिंचाई विभाग द्वारा अदालत में बताया गया कि दुद्धी और राबर्ट्सगंज के इलाके सूखाग्रस्त हैं, इसलिए इस परियोजना की ज़रूरत है, जबकि इस क्षेत्र में बहुचर्चित रिहंद एक वृहद सिंचाई परियोजना का बांध है, लेकिन आज उसका उपयोग सिंचाई के लिए न करके ऊर्जा संयंत्रों के लिए किया जा रहा है. यही नहीं, जो गांव डूब क्षेत्र में आएंगे, उनकी पूरी सूची उपलब्ध नहीं कराई गई और संबद्ध परिवारों की सूची भी ग़लत उपलब्ध कराई गई. सरकार द्वारा इस जनहित याचिका को यह कहकर खारिज करने की अपील की गई कि याची द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक और रिट दायर की गई है, लेकिन अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि उसके यहां दायर याचिका का दायरा पर्यावरण क़ानूनों से संबंधित है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर मामला भूमि अधिग्रहण से संबंधित है. ये दोनों मामले अलग हैं, इसलिए हरित न्यायालय में वादियों द्वारा दायर याचिका खारिज नहीं की जा सकती.

हरित न्यायालय ने कहा कि ज़िला सोनभद्र में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास के चलते न तो लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ और न समृद्धि आई. अभी तक इस क्षेत्र की स्थिति काफी पिछड़ी हुई है. किसी भी परियोजना का ध्येय यह होना चाहिए कि वह लोगों को जीवन जीने की बेहतर सुविधाएं और बेहतर पर्यावरणीय सुविधाएं मुहैया कराए. सोनभद्र उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में सबसे बड़ा विकसित ज़िला है, उसे ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है, लेकिन वही सबसे पिछड़े ज़िले के रूप में भी जाना जाता है. नया निर्माण रुके, पर्यावरण एवं वन आकलन के सभी नियम पूरी तरह से लागू हों, इसके लिए हरित न्यायालय ने एक उच्चस्तरीय सरकारी कमेटी का गठन तो ज़रूर किया है, लेकिन उक्त कमेटी में किसी भी विशेषज्ञ, विशेषज्ञ संस्थान एवं जन-संगठनों को शामिल नहीं किया गया है. ऐसे में चिंता का विषय यह है कि इस बात की निगरानी कौन करेगा कि नया निर्माण नहीं होगा और सभी शर्तों का पालन किया जाएगा?

क्षेत्र में वनाधिकार क़ानून 2006 लागू है, लेकिन उसका कभी पालन नहीं होता है. ग्राम सभा से इस क़ानून के तहत अभी तक अनुमति का प्रस्ताव तक नहीं भेजा गया है. इससे बड़ा मसला भूमि अधिग्रहण की सही प्रक्रिया को लेकर अटका हुआ है. संसद द्वारा पारित 2013 का क़ानून लागू ही नहीं हुआ और उसके ऊपर 2015 का भू-अध्यादेश लाया जा रहा है, जो 2013 के क़ानून के कई प्रावधानों के विपरीत है. कनहर बांध से प्रभावित पांच ग्राम पंचायतों ने उच्च न्यायालय में भूमि अधिग्रहण क़ानून 2013 की धारा 24, उपधारा 2 के तहत एक याचिका भी दायर कर रखी है, जिसके तहत प्रावधान है कि अगर उक्त किसी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया और यदि अधिग्रहीत भूमि पांच साल के अंदर संबंधित परियोजना के लिए इस्तेमाल न की गई, तो वह भू-स्वामियों के कब्ज़े में वापस चली जाएगी. भू-अभिलेखों में भी अभी तक ग्राम समाज और आबादी की भूमि ग्रामीणों के खाते में ही दर्ज है, जो अधिग्रहीत नहीं है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन तमाम क़ानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके ऐसी किसी परियोजना पर जबरन अमल क्यों कर रही है, जो ग़ैर-संवैधानिक और पर्यावरण के लिए बेहद ख़तरनाक है? ■

feedback@chauthiduniya.com

अदालत के फ़ैसले से मजबूत आधार पाकर पहली बार धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे शारदा और ज्योर्ति (ज्योतिष) पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि आदि शंकराचार्य की ओर से स्थापित सिद्धांतों का पालन होना चाहिए. जनता का दायित्व है कि वह फर्जी शंकराचार्यों को खुद सबक सिखाए और उनका बहिष्कार करे. ग़ौरतलब है कि देश में शंकराचार्यों की केवल चार पीठें हैं और इस समय तीन संत उन चार पीठों पर आसीन हैं. स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने बताया कि हाल में प्रयाग एवं दिल्ली में संपन्न हुई धर्म संसदों में संत समाज ने फर्जी शंकराचार्यों के बहिष्कार की घोषणा की. उन्होंने कहा कि देश की जनता को धर्म संसद के निर्देशों का पालन करना चाहिए.

प्रोन्नति में आरक्षण की राजनीति

सुकांत

बिहार में यह चुनाव काल है और राजनीति वोट की जमा-पूंजी के लेखा-जोखा के साथ आगे बढ़ रही है. अलग-अलग सामाजिक समूहों के कार्ड बड़े सलीके से खेले जाते रहे हैं. चुनाव काल में इन सामाजिक समूहों के कार्ड खेलने में आसानी होती है, जहां राजनीतिक आकांक्षा की अभिव्यक्ति की अपनी सुनिश्चित शैली नहीं होती, वह सामान्य हो या आक्रामक. इस लिहाज से बिहार में दलित, महादलित एवं अति पिछड़ों के बीच राजनीति-राजनीति का खेल आसान रहा है और इसे मौजूदा हालत में रहने दिया जा रहा है. पिछले कई दशकों में मंडलवादी सामाजिक न्याय की राजनीति ने इन समूहों के राजनीतिकरण की प्रक्रिया तो तेज कर दी, पर इनमें आक्रामक राजनीति विकसित होने के उपाय नहीं किए गए. राजनेताओं एवं नौकरशाहों की एक जमात इन सामाजिक समूहों की मार्केटिंग तो करती रही, लेकिन इनके सशक्तिकरण का प्रयास नहीं किया गया. बिहार की हाल की कुछ घटनाएं और उनके मुतल्लिक राजनीतिक दलों के आचरण इसे गहरे तक रेखांकित करते हैं.

पटना उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति-जनजाति के सरकारी सेवकों को प्रोन्नति में आरक्षण के बिहार सरकार का निर्णय निरस्त कर दिया है. इतना ही नहीं, न्यायमूर्ति बी. नाथ की एकल पीठ ने इस बारे में राज्य सरकार की ओर से पेश आंकड़ों को भी सही नहीं माना है. इस बारे में सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप अनुसूचित जाति-जनजाति के पिछड़ेपन के आकलन का निर्देश दिया गया है. हालांकि, सरकार की दलील थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में अनुसूचित जाति-जनजाति के पिछड़ेपन और सेवा में उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का आकलन करके ही आरक्षण देने का फ़ैसला लिया गया था, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया और फ़ैसले को चुनौती देने वालों की इस दलील को लगभग स्वीकार कर लिया कि इन सामाजिक समूहों के लोग निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में सेवा में तैनात हैं. ग़ौरतलब है कि राज्य सरकार ने अगस्त, 2012 में प्रोन्नति में आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया था. वैसे तो बिहार में प्रोन्नति में आरक्षण की सबसे पहली व्यवस्था अभियांत्रिक सेवा में 2008 में की गई थी, लेकिन 2011 में पटना उच्च न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया था.

दरअसल, सरकार ने वरिष्ठ आईएएस केपी रमैया की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसे विभिन्न विभागों में एससी-एसटी अधिकारियों के प्रतिनिधित्व का आकलन करना था. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में हर विभाग के ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों का ब्यौरा सरकार को दिया था. उसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने प्रोन्नति में आरक्षण का आदेश जारी किया था, जिसे एकल पीठ ने खारिज कर दिया. पीठ ने पिछड़ेपन के आकलन और उसके निर्धारण की राज्य सरकार की पद्धति को ग़लत करार देते हुए कहा कि आरक्षण का लाभ क्रीमीलेयर के दायरे से बाहर के लोगों को मिलना चाहिए. अदालत ने कहा कि सरकार नए सिरे से पिछड़ेपन का आकलन करके आरक्षण लागू कर सकती है. अदालत अनुसार, इस निर्णय के पहले से जारी आरक्षण यथावत रहेंगे. चुनाव का समय होने के कारण उच्च न्यायालय के इस निर्णय से सरकार गहरे राजनीतिक दबाव में आ गई है. नतीजतन, इस निर्णय को चुनौती देने की तैयारी युद्ध स्तर पर की गई है. साथ ही, इस मसले पर भारत के अटॉर्नी जनरल से भी सलाह ली जा रही है. इन पंक्तियों के प्रकाशित होने तक सरकार की ओर से अपील दायर हो जाने की हरसूरत उम्मीद है.

इस अपील पर जो भी निर्णय आए और राज्य सरकार उसके आलोक में जो भी करे, लेकिन बिहार की चुनावी राजनीति में यह तो मसला बन ही रहा है. हाईकोर्ट के उक्त आदेश को सबसे पहले राजनीति का मुद्दा राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने बनाया. उन्होंने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ राज्य सरकार की निष्क्रियता पर चिंता जताते हुए मामले को सर्वोच्च न्यायालय ले जाने की मांग की. यह राजनीति ही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुरंत कहा कि अपील की तैयारी कर ली गई है, किसी के मांग करने से पहले. लालू प्रसाद के बयान और मुख्यमंत्री के कथन के साथ ही कुछ अन्य राजनीतिक दलों के भी बयान आए. बिहार सरकार ने भी आनन-फानन में सारी तैयारी की और राज्य के प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर अप्रत्याशित ढंग से मीडिया से मुखातिब हुए. उन्होंने सब कुछ साफ़ ही नहीं किया, बल्कि राजद प्रमुख के बयान का जवाब भी दिया कि यह सिंगल बेंच का फ़ैसला था. इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाईकोर्ट की डबल बेंच में ही अपील की जा सकती है. सरकार को इसकी सलाह दी गई है.

लेकिन, इस पूरे प्रकरण में भाजपा प्राय: खामोश ही रही. यह राजनीतिक शैली राज्य की सत्ता की भावी दावेदार भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकती है, ऐसा राजनीति के जानकारों का मानना है. जब बिहार में सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण का निर्णय लिया गया था, तो उन दिनों राज्य में राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार थी. इस या ऐसे सभी निर्णयों में भाजपा बराबर की हिस्सेदार है. विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनाव में जिन सामाजिक समूहों का आक्रामक राजनीतिक सहयोग भाजपा को सत्ता तक पहुंचा सकता है, उनमें आरक्षण को लेकर विरोध का भाव है. ऐसे में सत्ता के दरवाजे पर खड़ी कोई राजनीतिक पार्टी भला ऐसे अवसरों को क्यों खोना चाहेगी! कहने का आशय यह कि प्रोन्नति में आरक्षण के मसले पर भाजपा की ठंडी प्रतिक्रिया का राजनीतिक निहितार्थ वही है, जो राजद प्रमुख की सरकार को मुखर नसीहत और उस पर नीतीश सरकार की सक्रियता का है. दोनों तरफ़ अपनी-अपनी राजनीतिक रणनीति है.

राजनीति में दलित कार्ड महत्वपूर्ण घटक है और चुनाव काल में इसके क्या कहने! बिहार की दलित राजनीति का हाल-हाल तक रामविलास पासवान सबसे ज्ञात चेहरे रहे हैं. 2014 के संसदीय चुनाव के पहले तक वह जनता परिवार के साथ रहे, लेकिन अब एनडीए के साथ हैं और पानी पी-पीकर जनता परिवार (अपने पुराने राजनीतिक सहयात्री) को कोस रहे हैं. लेकिन हाल के महीने में बिहार की दलित राजनीति का सबसे लुभावना चेहरा जीतन राम मांझी का दिखने लगा है और फिलहाल उनकी भाजपा से काफी छनती है. यानी बिहार की दलित राजनीति के दिग्गज चेहरे भाजपा के साथ हैं और इस मोर्चे पर जनता परिवार के घटक राजद और जद (यू) कमजोर ही नहीं, निरुपाय-से हैं. इस राजनीतिक निरुपायता से निपटने की कोशिश में ही राजद प्रमुख कभी जीतन राम मांझी की ओर देखते हैं और नीतीश कुमार दलित-महादलित से जुड़े मसले पर तुरंत सक्रिय हो जाते हैं.

राजद प्रमुख उन दिनों भी जीतन राम मांझी की प्रशंसा करते रहे थे, जिन दिनों नीतीश कुमार अपने मांझी विरोधी अभियान को अधिकाधिक धारदार बना रहे थे. लालू प्रसाद अब भी जीतन राम मांझी के प्रति कठोर कतई नहीं दिखना चाहते हैं. उनके इस रुख को राजद की भावी राजनीति की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. जीतन राम मांझी ने भी राजद प्रमुख से बैर-भाव का कभी प्रदर्शन नहीं किया. वह बार-बार कहते हैं कि लालू जी यदि नीतीश कुमार से अलग हो जाएं, तो हम उनके साथ जा सकते हैं. यानी दोनों नेता (लालू-मांझी) एक पतली पगडंडी खुली छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन, नीतीश कुमार के पास इस मोर्चे पर विकल्प बड़े सीमित बच रहे हैं. हालांकि, उन्होंने अपने शासनकाल में महादलित-दलित उत्थान के कार्यक्रमों को गंभीरता से लागू करके अपना एक सुनिश्चित सामाजिक समर्थक आधार बनाया था. यह सामाजिक समूह गत संसदीय चुनाव तक उनके साथ दिखा है. एससी-एसटी सरकारी सेवकों को प्रोन्नति में आरक्षण के सवाल पर उच्च न्यायालय से राज्य सरकार को यदि आने वाले कुछ हफ्तों में राहत मिलती है, तो वह नीतीश कुमार की राजनीति को नई ताकत देगी. लेकिन, यह कहना तो संभव नहीं है कि अदालत क्या करेगी.■

feedback@chauthiduniya.com

शंकराचार्य पद पर विवाद जारी

माधवाश्रम महाराज को हिमालयी जनता की ओर से जबरदस्त समर्थन-सम्मान हासिल है. उनका साफ़-साफ़ कहना है कि जिसे पिया मानै, वही सुहागिन. इस तरह देखा जाए, तो ज्योर्तिपीठ पर तीन-तीन शंकराचार्यों की दावेदारी जनता में लगातार भ्रम पैदा कर रही है. इस पूरे विवाद के इतिहास पर नज़र डालने पर पता चलता है कि बहुत पहले से इस पीठ पर स्वरूपानंद आसीन चले आ रहे हैं. शुरू से कांग्रेस के नेहरू परिवार से उनका लगाव होने के कारण वह विश्व हिंदू परिषद की आंख की किरकिरी बन गए.

राजकुमार शर्मा

देश में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित शंकराचार्य का पद विभिन्न पीठों पर आसीन संतों के आपसी मतभेद के कारण इन दिनों विवादों में है. इलाहाबाद के एक सिविल न्यायालय से ज्योर्तिपीठ पर चर्चित संत स्वरूपानंद सरस्वती के पक्ष में फ़ैसला आने के बाद भी यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अदालत के फ़ैसले पर प्रतिवादी एवं विहिप समर्थित संत वासुदेवानंद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह अंतिम फ़ैसला नहीं है, इसे चुनौती दी जाएगी. वासुदेवानंद द्वारा जन समर्थन के बल पर खुद के पीठाधीश्वर होने की बात कहने से विवाद थमता नज़र नहीं आ रहा है.

इन दो संतों के विवाद के बीच मौक़े का फ़ायदा उठाते हुए स्थानीय संत माधवाश्रम महाराज ने स्वयं को शंकराचार्य घोषित कर दिया है. माधवाश्रम महाराज को हिमालयी जनता की ओर से जबरदस्त समर्थन-सम्मान हासिल है. उनका साफ़-साफ़ कहना है कि जिसे पिया मानै, वही सुहागिन. इस तरह देखा जाए, तो ज्योर्तिपीठ पर तीन-तीन शंकराचार्यों की दावेदारी जनता में लगातार भ्रम पैदा कर रही है. इस पूरे विवाद के इतिहास पर नज़र डालने पर पता चलता है कि बहुत पहले से इस पीठ पर स्वरूपानंद आसीन चले आ रहे हैं. शुरू से कांग्रेस के नेहरू परिवार से उनका लगाव होने के कारण वह विश्व हिंदू परिषद की आंख की किरकिरी बन गए.

विहिप ने सनातन धर्म की इस सर्वाधिक मान्य पीठ पर वासुदेवानंद को समर्थन देकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया. दरअसल, सारा विवाद हिमालय स्थित ज्योर्तिपीठ को लेकर है, जो मोक्ष धाम बद्रीनाथ के पास स्थित है, जहां पूरे देश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और इस पीठ की आमदनी करोड़ों रुपये सालाना है. इस पीठ को ज्ञानपीठ की मान्यता भी प्राप्त है. इसी स्थल पर तप के दौरान आदि शंकराचार्य को ज्ञान-ज्योति मिली थी. हिमालय की कोख में प्राकृतिक वैभव के कारण यह पीठ जप-तप-सिद्धि के लिहाज से आदि शंकराचार्य की नज़र में भी श्रेष्ठ थी, इसलिए उन्होंने यहीं अपनी साधना का समय व्यतीत किया था.

अदालत के फ़ैसले से मजबूत आधार पाकर पहली बार धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे शारदा और ज्योर्ति (ज्योतिष) पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि आदि शंकराचार्य की ओर से स्थापित सिद्धांतों का पालन होना चाहिए. जनता का दायित्व है कि वह फर्जी शंकराचार्यों को खुद सबक सिखाए और उनका बहिष्कार करे. ग़ौरतलब है कि देश में शंकराचार्यों की केवल चार पीठें हैं और इस समय तीन संत उन चार पीठों पर आसीन हैं. स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने बताया कि हाल में प्रयाग एवं दिल्ली में संपन्न हुई धर्म संसदों में संत समाज ने फर्जी शंकराचार्यों के बहिष्कार की घोषणा की. उन्होंने कहा कि देश की जनता को धर्म संसद के निर्देशों का पालन करना चाहिए. आदि शंकराचार्य ने धर्म के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए उत्तर में ज्योर्ति मठ, दक्षिण में शृंगेरी मठ, पश्चिम में शारदा मठ और पूर्व में गोवर्धन मठ की स्थापना की थी. शारदा और ज्योर्तिपीठ पर वह स्वयं (स्वरूपानंद सरस्वती) आसीन हैं. दक्षिण की शृंगेरी पीठ पर स्वामी भारती पीठ और पूर्व की पुरी पीठ पर स्वामी निच्छलानंद सरस्वती आसीन हैं. उन्होंने कहा कि चार पीठों के इन तीन संतों के अलावा देश में और कोई शंकराचार्य नहीं है. यह सनातन धर्म के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि कई लोगों ने स्वयं को शंकराचार्य घोषित कर रखा है. देश का संत समाज चाहता है कि सनातन जगत में फैला यह भ्रम मिटना चाहिए. उन्होंने कहा कि अदालत का फ़ैसला आने के बाद बहुत कुछ साफ़ हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ राजनेताओं की गंदी चाल के चलते यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि शंकराचार्य पद की एक महत्ता है और उसका उल्लेख स्वयं आदि शंकराचार्य ने मठाम्नाय महानुशासन में किया है. देश में कोई भी व्यक्ति स्वयं को शंकराचार्य घोषित नहीं कर सकता.■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि उसका एजेंडा क्या है? कांग्रेस बात तो सही करती रही, लेकिन उसने काम ग़लत किए और आज उसी का नतीज़ा वह झेल रही है. भारतीय जनता पार्टी इस सबके लिए दुःखी होती भी नहीं दिख रही है. अगर भाजपा यह कहे कि अमीरों को और अमीर होने दो, व्यवसायी समुदाय को आगे बढ़ने दो, क्योंकि इससे ग़रीबों का भला होगा, तो आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए.

यही स्थिति रही, तो अमीर और अमीर होते जाएंगे

विश्व युद्ध से पहले अमेरिका की आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसे जानना बेहद दिलचस्प होगा. विश्व युद्ध से पहले अमेरिका की आय और संपदा वहां के चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सिमटी हुई थी. दूसरी तरफ़ बहुसंख्यक लोग इससे वंचित थे. विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिकी नागरिकों के मन में यह धारणा व्याप्त हुई कि यह सब ग़लत है. ऐसे लोग, जो अपना जीवन जीने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें अपनी आय के ज़रिये आनंद उठाने का मौक़ा मिलना चाहिए. वे इस योग्य बन सकें, ताकि एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें. उस हिसाब से लोगों पर कर लगने चाहिए, ताकि कर उन पर बोझ न बन सके. उस समय एक विचार सामने आया कि जो लोग अमीर हैं, उन पर ज़्यादा और जो लोग ग़रीब हैं, उन पर औसत कर लगाया जाए.

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में कमोबेश इसी तरह की व्यवस्था लागू हुई. यह व्यवस्था सत्तर के दशक तक क़ायम रही, लेकिन उसके बाद इसमें काफ़ी उलट-फेर हो गया. जब रोनाल्ड रीगन सत्ता में आए, तो उन्होंने यह पूरी व्यवस्था ही बदल कर रख दी. उसके बाद पिछले पैंतीस वर्षों में अमेरिका में जो हुआ, वह सबके सामने है. बीते पैंतीस वर्षों के दौरान अमेरिका में धनी लोग और अधिक धनी हुए, वहीं दूसरी तरफ़ कामगार तबके लगातार संघर्ष कर रहे हैं. नतीजतन, अमेरिका की महज़ एक फ़ीसद आबादी ही देश की ताक़त, संपदा, धन और अपनी आय का आनंद उठा रही है. वहीं देश की बाकी जनता अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है. इस ग़ैर-बराबरी के ख़िलाफ़ अब अमेरिका में भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है.

रिपब्लिकन तो घोषित तौर पर अमीरों की पार्टी है और डेमोक्रेट्स चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं. ओबामा काफ़ी प्रयासों के बाद भी इस समस्या का समाधान निकाल पाने में नाक़ाम साबित हो रहे हैं. इसके बरअक्स हम लोग यह सोच रहे हैं कि हम भारत में कुछ अच्छा कर सकते हैं, वह भी भाजपा की सरकार में. भाजपा शुरू से ही प्रो-रिच पार्टी रही है, प्रो-ट्रेड और प्रो-इंडस्ट्री पार्टी रही है. अर्थशास्त्री भी बता रहे हैं कि भारत में महज़ एक फ़ीसद आबादी का नौ फ़ीसद आय पर नियंत्रण है. इस एक में से दशमलव एक फ़ीसद लोग ही

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में कमोबेश इसी तरह की व्यवस्था लागू हुई. यह व्यवस्था सत्तर के दशक तक क़ायम रही, लेकिन उसके बाद इसमें काफ़ी उलट-फेर हो गया. जब रोनाल्ड रीगन सत्ता में आए, तो उन्होंने यह पूरी व्यवस्था ही बदल कर रख दी. उसके बाद पिछले पैंतीस वर्षों में अमेरिका में जो हुआ, वह सबके सामने है. बीते पैंतीस वर्षों के दौरान अमेरिका में धनी लोग और अधिक धनी हुए, वहीं दूसरी तरफ़ कामगार तबके लगातार संघर्ष कर रहे हैं. नतीजतन, अमेरिका की महज़ एक फ़ीसद आबादी ही देश की ताक़त, संपदा, धन और अपनी आय का आनंद उठा रही है. वहीं देश की बाकी जनता अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है.

इस नौ फ़ीसद आय के नब्बे फ़ीसद हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं. भारत में आर्थिक ताक़त और धन का संकेंद्रण (जमाव) अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है. यदि नई सरकार भी प्रो-इंडस्ट्री रही, तो मध्य वर्ग वहीं रह जाएगा, जहां अभी है. यानी नौकरी के लिए संघर्ष, बसों एवं ट्रेनों में धक्के खाते हुए यात्रा करना, बग़ैर क़र्ज़ के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा न दिला पाना और बिना क़र्ज़ लिए अच्छे ढंग से इलाज़ न करा पाना आदि. ऐसे में जीवन स्तर सुधारने की बात तो ही भूल जाइए.

अगर यह स्थिति बनती है, तो अमीर और अमीर होते जाएंगे. यहां सवाल यह है कि क्या हम लोग एक बार फिर से पूंजीवाद के युग में आ गए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि उसका एजेंडा क्या है? कांग्रेस बात तो सही करती रही, लेकिन उसने काम ग़लत किए और आज उसी का नतीज़ा वह झेल रही है. भारतीय जनता पार्टी इस सबके लिए दुःखी होती भी नहीं दिख रही है. अगर भाजपा यह कहे कि अमीरों को और अमीर होने दो, व्यवसायी समुदाय को आगे बढ़ने दो, क्योंकि इससे ग़रीबों का भला होगा, तो आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए. दरअसल, यह दलील कई त्रुटियों से भरी हुई है. जब अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता है, तो मैं नहीं समझता कि भारत ऐसा कर पाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक औघड़ लीक से हटकर-6

औघड़ों के घराने और दिनचर्या

औघड़ों के दो घराने प्रसिद्ध हैं-हिमाली और गिरवाली. भगवान शंकर का निवास स्थान होने से हिमालय को अघोर मत का उद्गम माना गया है. औघड़ों में यह सामान्य धारणा है कि उनके मत के प्रवर्तक गोरखनाथ थे. यह हिमाली घराना है. हिमाली नामकरण का एक कारण यह भी हो सकता है कि तंत्र-प्रधान तिब्बत में इस संप्रदाय का जन्म हुआ हो और बौद्ध धर्म की अवनति होने पर इस मत के प्रचारक वहीं से मैदानों की ओर अग्रसर हुए हों, जिससे इन साधकों को हिमाली कहा गया हो. गोरक्ष देश नेपाल में गोरखनाथ का प्रभाव अत्यधिक था. कालांतर में इस मत वाले ही अघोर उपासना करते हुए मैदानों में आए. ये हिमालय प्रदेश से आ रहे थे, इसलिए हिमाली कहलाए.

अवधूत मत के दूसरे मान्य आचार्य दत्तात्रेय अत्रि मुनि एवं अनुसूया के पुत्र बताए जाते हैं. इनको विष्णु का अवतार माना गया है. विंध्यगिरि के दक्षिण भाग में इनका क्षेत्र है. त्रिपुरा रहस्य तथा अन्य तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार, परशुराम आप ही से शिक्षा लेकर आत्मकाली की उपासना कर सिद्धि को प्राप्त हुए थे. कील के आरंभ में प्रभासपत्तन के निकट यादवों ने परस्पर लड़ते हुए अपने कुल का संहार कर डाला था. सौराष्ट्र (गुजरात) के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत के निकट ही यह क्षेत्र है. इस क्षेत्र में भयंकर संहार होने के कारण यह एक महाश्मशान है, जहां सोमनाथ निवास करते हैं. अवधूत संत गिरनार शिखर पर श्रीदत्त की पादुका तथा कमंडलु तीर्थ है. अनेक साधक आज भी यहां आकर श्रीदत्त का संपर्क पाते हैं. मान्यता है कि यहीं बाबा किनाराम को अघोरी वेश में श्रीदत्त ने दीक्षा दी थी. भगवान राम का दावा है कि उन्हें भी यहीं श्रीदत्त का साक्षात्कार हुआ था. गिरनार के श्रीदत्त स्थान की परंपरा के औघड़ गिरनारी कहलाते हैं.

अघोर साधक प्रातःकाल सोकर उठते ही पृथ्वी को अपने हाथ से स्पर्श करता है, क्योंकि पृथ्वी जननी है.

सूकर, मछली, मनुष्य, गिद्ध और कौए के मांस को महामांस कहा जाता है. इनका सेवन विरल अवसरों पर कार्यानुरूप ही करना उचित है. इसके अतिरिक्त जिह्वा से योनि को चाटना, भैरवी के होंठ चूमना, कपाल-पात्र में योगिनियों के साथ आसव पीना आदि का विधान है. साधक के लिए भैरवी की गोद पृथ्वी की तरह है, क्योंकि वह साधक की साधना के रहस्यों का उत्पत्ति-स्थल है और वही उसका भविष्य भी बनाती है. इतना माहात्म्य होने पर भी साधक को भैरवी का मानसिक चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानसिक साधना करने से बहुत बड़ा अपराध होता है. उससे चित्त की एकाग्रता भंग होती है.

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह कर ना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

इस क्रिया से क्रांति की आभा का उसके शरीर में प्रवेश होता है. उठकर बैठने पर वह कुछ मंत्रों को बड़बड़ाता है. अघोरियों को वाणी पर बड़ा निग्रह रखना होता है. कुछ काल तक मनन न हो, वही अघोर पूजा है. लोक-संग्रह के लिए माला फेरने या ध्यान करने का निषेध नहीं है. अमरी का सेवन यह प्राय: हर समय करता है. वज्री का सेवन सदा न हो, तो चौबीस घंटों में कम से कम एक बार उसका सेवन अवश्य करता है. स्नान का बंधन बिल्कुल नहीं है. रज-वीर्य का सेवन विहित है. अपने होंठ या मुख का प्रक्षालन करके जिस प्रकार लोग उस पर हाथ घुमाया करते हैं, उसी प्रकार गुदा और लिंग का प्रक्षालन करके औघड़ उस पर बराबर हाथ घुमाता है, क्योंकि इन्हीं इंद्रियों से कुंडलिनी का प्रथम मार्ग प्रशस्त होता है.

अघोर साधक यदि गृहस्थ है, तो अपनी प्रिया के होंठों को चूमना उसके लिए अनिवार्य होता है. अपनी भैरवी शक्ति की योनि का भी जिह्वा से सेवन करने से साधक को सिद्धियां मिलती हैं. यह साधना गृहस्थ साधकों के लिए सुलभ है. विरक्त साधु के लिए यह आवश्यक है कि वह मनुष्यों के समाज से अपना डेरा सदैव दूर रखे, क्योंकि रात्रि समय उसके इष्ट मिलन का है. रात्रि को गृहस्थ को गृह छोड़कर चल देना चाहिए. श्मशान-साधना एकांत का पर्याय है और इसका लक्ष्य चित्त की एकाग्रता है. इसी दृष्टि से पंच श्मशान का ग्रहण है: (1) गांव के बाहर का पीपल का वृक्ष, (2) मूंज की खाट, (3) वेश्या का बिस्तर, (4) अपनी पत्नी के सहवास का बिस्तर और (5) श्मशान. जो सफलता श्मशान में है, वही अन्य वर्णित स्थानों में भी. निश्चिंत चिंतन से अघोर साधक अपनी क्रियाओं का संतुलन बनाता है. ये सभी स्थल निश्चिंत चिंतन के लिए उपयुक्त हैं. वीर्यपात ही जीव की बलि या चिंगारी उत्पन्न करता है.

अघोर साधक प्रात:काल सोकर उठते ही पृथ्वी को अपने हाथ से स्पर्श करता है, क्योंकि पृथ्वी जननी है. इस क्रिया से क्रांति की आभा का उसके शरीर में प्रवेश होता है. उठकर बैठने पर वह कुछ मंत्रों को बड़बड़ाता है. अघोरियों को वाणी पर बड़ा निग्रह रखना होता है. कुछ काल तक मनन न हो, वही अघोर पूजा है. लोक-संग्रह के लिए माला फेरने या ध्यान करने का निषेध नहीं है.

सूकर, मछली, मनुष्य, गिद्ध और कौए के मांस को महामांस कहा जाता है. इनका सेवन विरल अवसरों पर कार्यानुरूप ही करना उचित है. इसके अतिरिक्त जिह्वा से योनि को चाटना, भैरवी के होंठ चूमना, कपाल-पात्र में योगिनियों के साथ आसव पीना आदि का विधान है. साधक के लिए भैरवी की गोद पृथ्वी की तरह है, क्योंकि वह साधक की साधना के रहस्यों का उत्पत्ति-स्थल है और वही उसका भविष्य भी बनाती है. इतना माहात्म्य होने पर भी साधक को भैरवी का मानसिक चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानसिक साधना करने से बहुत बड़ा अपराध होता है. उससे चित्त की एकाग्रता भंग होती है. साधक लंगोटी पहनते हैं, क्योंकि लाल रंग रज का प्रतीक है और उस लंगोटी को धारण करने वाला अहर्निश लिंग और उस तत्व के प्रतीक का संपर्क बनाए रखता है. साधना काल में नीले और काले वस्त्र का उपयोग इसलिए साधक को करना चाहिए कि वह उसकी विद्या और अघोर क्रिया की सुरक्षा का साधन है.

भग बिच लिंग, लिंग बिच पारा, जो राखे, सो गुरु हमारा. यह औघड़ आचार्यों का प्रधान मत है. अघोराचार्य ऐसे साधना-संपन्न व्यक्तियों को अपना स्नेह देने में जरा भी नहीं हिचकिचाते. उक्त पद में परम उत्तेजना की स्थिति पाकर भी सहज बने रहने की ओर संकेत है. वस्तु के अभाव में उसके त्यागी सभी हो सकते हैं, किंतु भोग में योग की साधना केवल उच्च भावापन्न व्यक्तियों का ही काम है. औघड़ उसे कहते हैं, जो समवर्ती साधना की कोटि में पहुंचा हुआ आदमी होता है. समदर्शी तो सबमें समान दरसता है, लेकिन समवर्ती सबमें समान बरतता है. जो सबमें समान बरतने वाला होता है, उसके यहां किसी जाति या धर्म का कोई बंधन नहीं होता. औघड़ों में औघर की परिभाषा है-और घर. ये सब लोग नहीं, ये सब घर नहीं, और ही घर. भगवान शिव को औघड़ कहा जाता है. ये बहुत जल्द द्रवित होते हैं, क्योंकि इनका हृदय बहुत ही स्वच्छ रहता है, किसी के साथ कोई दुराव नहीं होता. औघड़ का पंथ नहीं है, यह पद है. इसलिए इस पद पर जो भी पहुंच जाता है, वह किसी भी पंथ का या धर्म का अनुयायी हो, औघड़ हो जाता है. हिंदुओं में इन्हें औघड़ कहते हैं, तो मुसलमानों में औलिया या मलंग. ■

(औघड़ भगवान राम से बातचीत के आधार पर, सात दिसंबर, 1980)

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

प्रधानमंत्री जी, देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं

पिछली सरकारों के रिपोर्ट कार्ड देखें, तो लगता है कि इस देश में स्वर्ग आ चुका है, पर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में रहने वाले जब अपने शहर की सीमा से बाहर निकलते हैं, तो सच्चाई आसानी से उनके सामने आ जाती है. किसी भी सरकार ने देश के गांव में पैदा होने वाले कच्चे माल को आधार बनाकर उद्योग-धंधे लगाने के बारे में सोचा ही नहीं. दरअसल, यह रास्ता बाज़ार की तरफ़ नहीं जाता है, देश के लोगों की तरफ़ जाता है.

राजनीति शायद मदारी का खेल हो गई है. भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही किसी भी प्रश्न को गंभीरता से लेने की जगह उसे वाद-विवाद में उलझाने की वृत्ति का शिकार हो गई हैं. पहले कांग्रेस की बात करें. राहुल गांधी सारे देश में घूम-घूमकर नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ भाषण दे रहे हैं. लेकिन, वह यह नहीं समझना चाहते कि पिछले दस सालों में, पिछले 20 सालों में या पिछले तीस सालों में इस देश में किसी भी सरकार ने किसान को औद्योगिक विकास का केंद्र माना ही नहीं. किसानों को ज़िंदा रहने लायक सुविधाएं देने की बातें ज़रूर कीं, लेकिन ज़िंदा रहने लायक सुविधाएं दी नहीं. देश में अभी तक कुछ प्रदेशों को छोड़ दें, बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, जहां गांव से आसानी के साथ कस्बे या ज़िले तक जाया ही नहीं जा सकता. हालत यह है कि अगर गर्भवती औरत ब्लॉक के अस्पताल में जाने के लिए बैलगाड़ी से निकले या तांगे से निकले, तो रास्ते में ही प्रसव कर दे, क्योंकि अधबनी-अधकच्ची सड़कनुमा गलियां बिल्कुल ऐसी ही हैं. कोई भी प्रदेश इसका अपवाद नहीं है. बिजली की

मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री समझदार आदमी हैं, विचारशील आदमी हैं और सबसे बड़ी चीज यह कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट नहीं हैं. इस व्यवस्था में भ्रष्ट तंत्र का प्रतीक माने जाने वाले कई सारे लोग उनके मंत्रिमंडल में हैं, वह अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री कहीं से भ्रष्ट नहीं हैं. इसीलिए अभी तक कहीं पर भी भ्रष्टाचार का कोई बड़ा या छोटा मुद्दा सामने नहीं आया है. लेकिन, इसका यह मतलब नहीं है कि आप देश के विकास का सार्थक नक्शा देश के सामने न रखें और उसमें लोगों को शामिल न करें.

स्थिति हमें मालूम है, पानी की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, लेकिन बातें हम बड़ी-बड़ी करते हैं.

पिछली सरकारों के रिपोर्ट कार्ड देखें, तो लगता है कि इस देश में स्वर्ग आ चुका है, पर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में रहने वाले जब अपने शहर की सीमा से बाहर निकलते हैं, तो सच्चाई आसानी से उनके सामने आ जाती है. किसी भी सरकार ने देश के गांव में पैदा होने वाले कच्चे माल को आधार बनाकर उद्योग-धंधे लगाने के बारे में सोचा ही नहीं. दरअसल, यह रास्ता बाज़ार की तरफ़ नहीं जाता है, देश के लोगों की तरफ़ जाता है. लेकिन, जबसे हमने यह तय किया है कि इस देश में बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था आएगी, उसी दिन से विकास के दायरे से ग़रीब ख़त्म हो गया, खेतिहर मज़दूर ख़त्म हो गया या विकास के दायरे से बाहर फेंक दिया गया और छोटा एवं मझोला किसान इसी प्रक्रिया में विकास के दायरे से बाहर चला गया. बेरोज़गारी, कुशिक्षा, चिकित्सा का अभाव आदि सारी चीजें देश के बड़े हिस्से में हैं, लेकिन कभी भी उनसे लड़ने की कोई बात किसी सरकार ने नहीं की. अब राहुल गांधी अगर इस बात को समझ कर देश में घूमते, तो हो सकता है कि उनके प्रति लोगों का विश्वास जगता. लेकिन, राहुल गांधी अपनी सरकारों द्वारा किए हुए कार्यों को सही ठहरा रहे हैं और नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोल रहे हैं. जबकि राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी उन्हीं की सरकारों द्वारा बनाई हुई नीतियों का पालन कर रहे हैं.

हमें यह लगा था कि भारतीय जनता पार्टी आई है, तो वह सांप्रदायिकता के मोर्चे पर भले ही कुछ न करे, लेकिन विकास के मोर्चे पर अवश्य कुछ करेगी. भारतीय जनता पार्टी में दीन दयाल उपाध्याय जैसों ने दर्शन दिया था और उसके अब तक तीन सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी गांवों के विकास का महत्व समझते थे, पर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस की बाज़ार आधार नीतियों का समर्थन कर रही है और उन्हें एक तेज दिमाग के साथ लागू भी कर रही है तथा इस पूरी प्रक्रिया में दीन दयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की सोच बाहर है यानी देश का गांव बाहर है, अंतिम आदमी बाहर है. योजना कोई भले ही अन्त्योदय के नाम से चल रही हो, लेकिन वह विकास के दायरे में नहीं है. यहां तक कि हिंदुस्तान के गांवों की ज़रूरतों की फेहरिस्त में भी गांव नहीं है. किसी भी विभाग की प्राथमिकता में गांव को पानी, बिजली, अस्पताल, सड़क, स्कूल नहीं हैं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार आदर्श रूप में राहुल गांधी की पार्टी द्वारा लागू की गई नीतियों के सार्थक उत्तराधिकारी नज़र आते हैं.

पिछली सरकार भी ग़रीबों से, उनकी भूख से, उनके दर्द से, उनकी तकलीफों से बंदूकों के ज़रिये लड़ना चाहती थी और मौजूदा सरकार भी ग़रीबों के दर्द, उनकी तकलीफों, उनके आंसुओं से बंदूकों के ज़रिये ही लड़ना चाहती है. लगता ऐसा है कि नरेंद्र मोदी का देश को लेकर देखा गया सपना, जिसे उन्होंने अपने भाषणों में बार-बार लोगों के सामने रखा है, उसे नरेंद्र मोदी के साथी अथवा उनके द्वारा चुने हुए अफसर या तो समझते नहीं हैं या उसमें विश्वास नहीं रखते. मेरा मानना है कि वे समझते अवश्य हैं, विश्वास नहीं रखते. इसीलिए उस सपने को पूरा करने की दिशा में एक क़दम भी अब तक बढ़ना नहीं हो पाया है. इस न बढ़ने के पीछे वित्त मंत्री अरुण जेटली का बजट है. प्रधानमंत्री सिर्फ़ निर्देश बिंदु बता सकता है, उसमें रंग भरना, उसका खाका बनाना और उसका संपूर्ण चित्र उभारना वित्त मंत्री का काम होता है, पर वित्त मंत्री का बजट कहता है कि नरेंद्र मोदी द्वारा चुनाव के दौरान दिए गए सारे भाषण और प्रधानमंत्री बनने के बाद सारी दुनिया में दिए हुए भाषण कहीं पर भी लागू हुई नीतियों से कहीं दूर खड़े हैं. और, शायद इसीलिए इस देश में एक भावना फैलने लगी है कि प्रधानमंत्री बातें करते हैं बहुत, अच्छी बातें करते हैं, पर उन बातों को धरती पर उतारने का कोई भी नक्शा अभी सामने नहीं आया है.

प्रचार के ज़रिये दोबारा कांठ की हांडी को चूल्हे पर चढ़ाने की कोशिश हो रही है. इस प्रचार ने ही नरेंद्र मोदी सरकार को केंद्र की गद्दी पर बैठाया, ऐसा एक बड़ा वर्ग मानता है. लेकिन, अगर सिर्फ़ प्रचार बैठाता, तो कांग्रेस भी प्रचार कर सकती थी. लेकिन, चूंकि कांग्रेस ने पिछले दस सालों में जिन आर्थिक नीतियों को लागू किया, वे उसे वोट देने वाले तबके के एक बड़े हिस्से की ज़िंदगी में कोई बदलाव ला पाने में सफल नहीं रहीं. इसलिए वह प्रचार कूड़े के ढेर में चला गया और नरेंद्र मोदी को लोगों ने अपनी आशाओं को हक़ीक़त का जामा पहनाने वाले व्यक्ति के रूप में देखा. लेकिन, अब जबकि एक वर्ष बीत चुका है और अब भी अगर हम बार-बार यहीं कहें कि अभी तो सिर्फ़ एक साल हुआ है, अभी एक साल और देखें, फिर एक साल और देखें. हमने पिछले साठ साल इसी तरह से गुज़ार दिए हैं.

मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री समझदार आदमी हैं, विचारशील आदमी हैं और सबसे बड़ी चीज यह कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट नहीं हैं. इस व्यवस्था में भ्रष्ट तंत्र का प्रतीक माने जाने वाले कई सारे लोग उनके मंत्रिमंडल में हैं, वह अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री कहीं से भ्रष्ट नहीं हैं. इसीलिए अभी तक कहीं पर भी भ्रष्टाचार का कोई बड़ा या छोटा मुद्दा सामने नहीं आया है. लेकिन, इसका यह मतलब नहीं है कि आप देश के विकास का सार्थक नक्शा देश के सामने न रखें और उसमें लोगों को शामिल न करें. इतनी बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं की ताकत देश के निर्माण में, देश के विकास

हमें यह लगा था कि भारतीय जनता पार्टी आई है, तो वह सांप्रदायिकता के मोर्चे पर भले ही कुछ न करे, लेकिन विकास के मोर्चे पर अवश्य कुछ करेगी. भारतीय जनता पार्टी में दीन दयाल उपाध्याय जैसों ने दर्शन दिया था और उसके अब तक तीन सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी गांवों के विकास का महत्व समझते थे, पर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस की बाज़ार आधार नीतियों का समर्थन कर रही है और उन्हें एक तेज दिमाग के साथ लागू भी कर रही है तथा इस पूरी प्रक्रिया में दीन दयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की सोच बाहर है यानी देश का गांव बाहर है, अंतिम आदमी बाहर है.

में अभी नहीं लग पाई है, क्योंकि संघ से जुड़े सारे कार्यकर्ताओं में जिस तरह का उत्साह विकास के कामों या लोगों को शामिल करने की रणनीति के तहत होना चाहिए, वह कहीं नज़र नहीं आ रहा है.

हम सिर्फ़ यह आशा कर सकते हैं और हमें यह आशा करनी चाहिए कि मौजूदा सरकार कांग्रेस की सरकार से बेहतर काम करेगी. अब एक साल बीतने के बाद समय कम है. हम नहीं समझ पाए, हम नहीं देख पाए, हम किन अफसरों को लगाएं और किन सचिवों के ऊपर भरोसा करें, अब इन सारी भाषाओं का मतलब रह नहीं गया है. इसलिए एक साल ख़त्म होने के बाद अब हर महीने प्रधानमंत्री जी को अपने मंत्रिमंडल और अपने अधिकारियों की वह समीक्षा करनी चाहिए, जिसका परिणाम लोगों के दु:ख और तकलीफ को दूर करने में निकले, न कि कैसे प्रचार हो, किस तरह लोगों को एक सपने की जगह दूसरा सपना दिखाया जाए. ऐसे काम पहले हुए हैं. शायद अब उनका एक ऐसा पड़ाव आ गया है, जिसके आगे कोई रास्ता नहीं है. अब प्रधानमंत्री इस देश के उन बहुसंख्यक लोगों का सपना पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ें, जिन्होंने उन्हें इतना बड़ा बहुमत दिया है. यह आशा तो हम कर ही सकते हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

राजनीतिक दल: विपक्ष में कुछ, सत्ता में कुछ और

बांग्लादेश सीमा बिल पर बनी सर्वसम्मति यह साबित करती है कि विपक्ष को उसका श्रेय देकर और किसी बिल को एक सर्वदलीय उपलब्धि के तौर पर पेश करके उनका समर्थन हासिल किया जा सकता है. सुषमा स्वराज भाजपा के गिने-चुने अच्छे सांसदों में से एक हैं. इस संबंध में अरुण जेटली का भी नाम लिया जा सकता है. कांग्रेस के अहम को शांत करके स्वराज ने सरकार के लिए कुछ अंक अर्जित किए. इन सबके बावजूद यह नहीं भूलना चाहिए कि उच्च सदन (राज्यसभा) जनता द्वारा चुनकर आए निचले सदन (लोकसभा) की आवाज़ दबा रहा है.

मेघनाद देसाई

ब्रिटेन में 1960 के दशक में किसी राजनीतिक दल के सत्ता में रहते हुए अलग और विपक्ष में रहते हुए कुछ अलग रुख को जेकेल एंड हाइड पॉलिटिक्स कहा जाता था. इसका भाव यह था कि सत्ता में रहते हुए पार्टियां तर्कसंगत तरीके से व्यवहार करती हैं और विपक्ष में अतार्किक ढंग से. अगर आप चाहें, तो इसे उलट भी सकते हैं. इसका मतलब यह था कि राजनीतिक दल संसदीय व्यवहार में अनैतिक थे. इसका मतलब यह भी है कि सत्ता और विपक्ष के मामले में राजनीतिक दलों में बहुत कम फ़र्क़ होता है. लेकिन, इसके बावजूद वे यह दिखाते हैं कि वे एक-दूसरे से बहुत अलग हैं. कुछ इसी तरह की परेशानी में भाजपा (एनडीए) सरकार उलझी हुई है. वह यह सोच रही थी कि विपक्ष ख़त्म हो चुका है. उसे यह विश्वास नहीं था कि लोकसभा में 10 प्रतिशत से भी कम सीटें हासिल करके कांग्रेस इतने प्रभावी तरीके से सरकार के विधेयकों को रोक सकेगी. भाजपा ने यूपीए सरकार के समय यही नीति अपना रखी थी. यह अलग बात है कि उसे इतनी सफलता नहीं मिली थी. उस समय यूपीए के लिए अनिर्णय की स्थिति विपक्ष के अवरोध से बड़ी समस्या थी. मिसाल के तौर पर तेलंगाना बिल और लोकपाल बिल को लिया जा सकता है.

भाजपा बहुत खुशकिस्मत है कि वह संसद के शीतकालीन सत्र में इंश्योरेंस बिल और माइनिंग बिल पास कराने में कामयाब रही, लेकिन भूमि अधिग्रहण बिल फंसा रह गया. हालांकि, यह अप्रत्याशित नहीं है. इससे यह भी साबित होता है कि सरकार में शामिल सांसद अनुभवहीन हैं. ऐसा लगता है कि संसदीय प्रक्रिया की छोटी-सी पुस्तिका किसी ने ध्यान से पढ़ी ही नहीं है. वे इसी बात से खुश हो जाते हैं कि अगर राज्यसभा किसी बिल पर बाधा उत्पन्न करती है, तो उसे संसद के संयुक्त सत्र में पास कराया जा सकता है. लेकिन, दूसरे पक्ष के पास अधिक अनुभव है. उसे मालूम है कि राज्यसभा में भी वह किसी बिल पर बाधा तो उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वोट के ज़रिये रोक नहीं सकता. एक बड़ी हैरान करने वाली बात वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) बिल के संबंध में नज़र आई. जहां तक भूमि अधिग्रहण बिल का सवाल है, तो यह कहा जा सकता है कि उसने 2013 के बिल पर अपनी सहमति दी थी. ज़ाहिर है, उस समय भाजपा विपक्ष में थी. सत्ता में आने के बाद वह अब अलग पार्टी बन गई है. इसके बावजूद, मेरे ख्याल से नए बिल में जो बदलाव किए गए हैं, वे वास्तविक हैं. बहरहाल, राज्यसभा में कांग्रेस को जीएसटी बिल पारित होने देना चाहिए. उसका विरोध उस

भाजपा बहुत खुशकिस्मत है कि वह संसद के शीतकालीन सत्र में इंश्योरेंस बिल और माइनिंग बिल पास कराने में कामयाब रही, लेकिन भूमि अधिग्रहण बिल फंसा रह गया. हालांकि, यह अप्रत्याशित नहीं है. इससे यह भी साबित होता है कि सरकार में शामिल सांसद अनुभवहीन हैं. ऐसा लगता है कि संसदीय प्रक्रिया की छोटी-सी पुस्तिका किसी ने ध्यान से पढ़ी ही नहीं है. वे इसी बात से खुश हो जाते हैं कि अगर राज्यसभा किसी बिल पर बाधा उत्पन्न करती है, तो उसे संसद के संयुक्त सत्र में पास कराया जा सकता है.

विचार-विमर्श की प्रक्रिया के विपरीत है, जो इस बिल के संबंध में अपनाई गई थी. चूंकि राहुल गांधी एक नए अवतार में अपना राजनीतिक करियर सुधार रहे हैं, इसलिए कांग्रेस अधिक आक्रामक दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे विपक्ष को फ़ायदे से अधिक देश को नुक़सान हो रहा है.

बांग्लादेश सीमा बिल पर बनी सर्वसम्मति यह साबित करती है कि विपक्ष को उसका श्रेय देकर और किसी बिल को एक सर्वदलीय उपलब्धि के तौर पर पेश करके उनका समर्थन हासिल किया जा सकता है. सुषमा स्वराज भाजपा के गिने-चुने अच्छे सांसदों में से एक हैं. इस संबंध में अरुण जेटली का भी नाम लिया जा सकता है. कांग्रेस के अहम को शांत करके स्वराज ने सरकार के लिए कुछ अंक अर्जित किए. इन सबके बावजूद यह नहीं भूलना चाहिए कि उच्च सदन (राज्यसभा) जनता द्वारा चुनकर आए निचले सदन (लोकसभा) की आवाज़ दबा रहा है. ब्रिटेन में चूंकि उच्च सदन को जनता नहीं चुनती, इसलिए हम अपनी सीमाएं जानते हैं. राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, जो संघीय तत्व का प्रतिनिधित्व करता है. लेकिन, दोनों सदनों के चुनाव के चक्र में समन्वय नहीं है. लिहाज़ा, जो लोग पुराने जनादेश (राज्यसभा) से चुनकर आएंगे, वे नए जनादेश (लोकसभा) की इच्छाओं को रोक देंगे. अब दोनों सदनों के चुनाव में सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ किया जाएगा या नहीं, यह किसी के अनुमान से परे नहीं है. फ़िलहाल जो बड़ा मुद्दा है, वह यह है कि संख्या और प्रतिशत दोनों लिहाज़ से शहरीकरण में वृद्धि हो रही है. शहरी क्षेत्र को उसकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है. इसके बावजूद राजनेता यह दिखावा कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी अधिक है. बहरहाल, यह तो राजनीति है, लेकिन इस बीच भाजपा के सीखने के ग्राफ में इजाफ़ा ज़रूर हुआ है. ■

feedback@chauthiduniya.com

वर्ष 1985 में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी. बाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया. उन्हें 16 साल सियालकोट, कोटलखपत और मियांवाली जेल सहित विभिन्न जेलों में रखा गया था. वहां कौशिक को दमा और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ गए. चुपके से वह भारत में अपने परिवार के लिए पत्र भेजने में कामयाब रहे. उसमें उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य की स्थिति और पाकिस्तान की जेलों में अपने ऊपर होने वाले यातनाओं के बारे में उस पत्र में लिखा.

हाइपो-ग्लाइसीमिया के मरीज रखें खास ख्याल

चौथी दुनिया ब्यूरो

खून में शुगर की अधिकता की बीमारी को मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं ये सभी जानते हैं लेकिन खून में शुगर की कमी भी एक तरह की बीमारी है इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. खून में शुगर की कमी को हाइपो–ग्लाइसीमिया कहते हैं. जिसे आम तौर लो–शुगर के नाम से भी जना जाता है. हाइपो–ग्लाइसीमिया सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है खासकर उन लोगों में जो मधुमेह के मरीज़ है. ध्यान देने वाली बात है की हाइपो–ग्लाइसीमिया या लो शुगर से डायबिटिक लोगों को अधिक सावधान रहने की जरूरत होती है क्योंकि वह शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए लिए दवाई या इन्सुलिन लेते हैं. यदि सही मात्रा में या डॉक्टर के निर्देशानुसार दवाई और इन्सुलिन न ली जाये तो हाइपोग्लाइसीमिया होने का खतरा रहता है जो कि बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है. ऐसी स्थिति में सिरदर्द, चक्कर आना, कमजोरी, थकान, आंखों के सामने अंधेरा छाना आदि समस्याएं होने लगती हैं और गंभीर मामलों में मरीज़ बेहोश भी हो सकता है.

हाइपो–ग्लाइसीमिया के कारण

हाइपो–ग्लाइसीमिया के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं. डायबिटीज के रोगियों में इंसुलिन या डायबिटीज की अन्य दवाओं की सही खुराक ना लेना, खाना खाने में अनियमितता यानि लंबे समय तक भूखे रहना, कम खाना या संतुलित आहार न लेना, लो शुगर के सबसे आम कारण हैं. कम खाने की वजह से शरीर में कार्बोहाइट्रेट की मात्रा कम होती है, इस वजह से रक्त में शुगर का स्तर कम हो जाता है. इसके अलावा आमतौर पर सामान्य दिनचर्या से ज्यादा भागदौड़ करना, खाने के बीच ज्यादा समय का अंतर होना, अधिक मात्रा में शराब का सेवन करना और उपवास के दौरान सावधानी न बरतने पर भी हाइपो–ग्लाइसीमिया का शिकार होने की आशंका होती है. विशेष रूप से खाली पेट शराब पीने से भी अचानक खून में ग्लूकोज का स्तर कम होने की संभावना रहती है. मधुमेह के मरीजों में शराब के कारण दुष्परिणाम होने की संभावना अन्य की अपेक्षा ज्यादा होती है. कुछ दवाओं के सेवन से भी खून में ग्लूकोज कम होने का खतरा होता है. खाली पेट व्यायाम करने से हाइपोग्लाइसीमिया की समस्या पैदा हो सकती है. हाइपोग्लाइसीमिया होने की सबसे बड़ी वजह लापरवाही या जागरूकता का अभाव है.

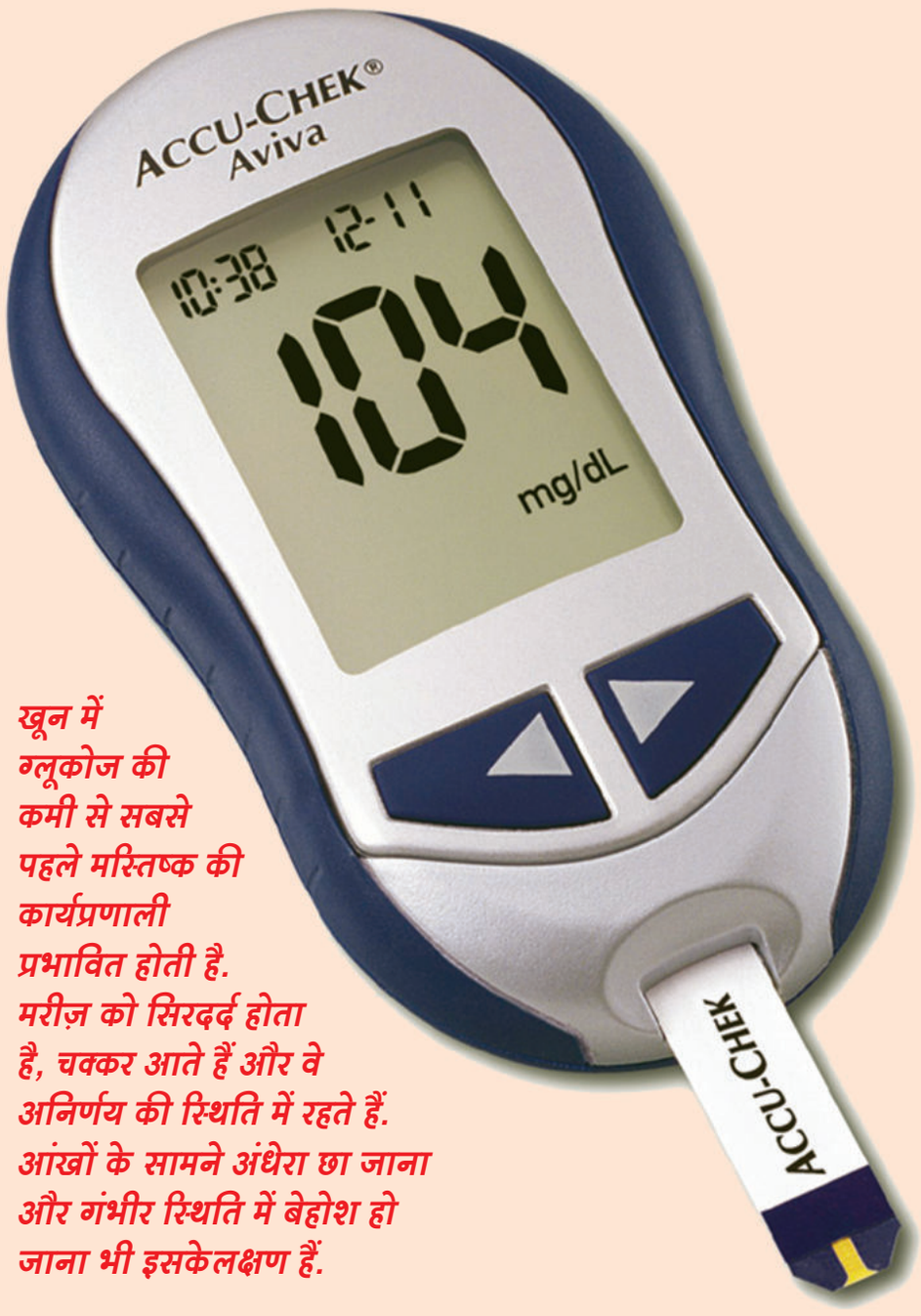

खून में ग्लूकोज की कमी से सबसे पहले मस्तिष्क की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है. मरीज़ को सिरदर्द होता है, चक्कर आते हैं और वे अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं. आंखों के सामने अंधेरा छा जाना और गंभीर स्थिति में बेहोश हो जाना भी इसके लक्षण हैं.

लक्षण

खून में ग्लूकोज या आम भाषा में शुगर का स्तर कम होना शरीर के लिए तनाव जैसी स्थिति पैदा कर देता है. इसकी वजह से अत्यधिक पसीना आता है, हाथों में कंपन्न होता है, भूख लगती है और बेचैनी महसूस होती है. हृदयगति बढ़ जाती है, और दिल के तेजी से धड़कने की वजह से मरीज घबराहट महसूस करते हैं. खून में ग्लूकोज की कमी से सबसे पहले मस्तिष्क की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है. मरीज़ को सिरदर्द होता है, चक्कर आते हैं और वे अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं. आंखों के सामने अंधेरा छा जाना और गंभीर स्थिति में बेहोश हो जाना भी इसके लक्षण हैं. समय से समुचित उपचार न होने पर गंभीर मामलों में मौत भी हो सकती है.

बचाव

हाइपो–ग्लाइसीमिया से कुछ सावधानियां बरत कर कई हद तक बचा जा सकता है. नियमित रूप से और नियमित अंतराल पर खून में ग्लूकोज(ब्लड शुगर) की जांच करानी चाहिए. डायबिटीज के मरीजों को डायबिटीज की दवाओं अथवा इंसुलिन को ब्लड शुगर के स्तर के अनुसार डॉक्टर की सलाह के अनुसार निर्धारित करना चाहिए. मधुमेह के कुछ मरीज भूख से ज्यादा भोजन कर लेते हैं और फिर मनमर्जी से दवा या इंसुलिन की मात्रा बढ़ा लेते हैं, जिससे शुगर के अनियंत्रित होने की आशंका बढ़ जाती है. साथ ही मधुमेह रोगियों को ब्लड शुगर के स्तर में की कमी से बचने के लिए थोड़ी–थोड़ी मात्रा में दिन में कई बार हल्का खाना खाते रहना चाहिए. मधुमेह के मरीजों को हमेशा अपने पास खाने की कोई मीठी चीज़ या ग्लूकोस के बिस्किट रखने चाहिए. गर्भवती महिलाएं खासकर वो जो मधुमेह से ग्रस्त हों, उन्हें उपवास नहीं करना चाहिए. इसके अलावा खाली पेट व्यायाम नहीं करना चाहिए और व्यायाम करने से पूर्व पानी ज़रूर पीना चाहिए. हाइपो–ग्लाइसीमिया के लक्षण महसूस होते ही तुरंत शुगर या ग्लूकोज का सेवन करें. हाइपोग्लाइसीमिया का पता लगाने के लिए खून की जांच होती है.हाइपो–ग्लाइसीमिया का अगर अतिशीघ्र निदान और उपचार नहीं हो, तो इलाज में देरी होना मौत का कारण बन सकती है. यदि मरीज होश में हो, तो उसे पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज, चीनी का घोल या शर्बत, दिया जाना चाहिए. यदि मरीज बेहोश हो गया है, तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए. आमतौर पर ऐसी हालत में ग्लूकोज का घोल ड्रिप के जरिये चढ़ाया जाता है. हाइपो–ग्लाइसीमिया से बचाव के लिए जरूरी है कि इस बीमारी के बारे में ठीक से समझना और सावधानी बरतना जरूरी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

रविन्द्र कौशिक

एक था टाइगर

> रविन्द्र कौशिक साल 1975 में मजह 23 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान भेजा गया. उन्हें नबी अहमद शाकिर नाम दिया गया. वो अपनी पहचान की बदौलत कराची विश्वविद्यालय में दाखिला पाने में कामयाब रहे, उन्होंने वहां से एलएलबी की शिक्षा हासिल की. इसके बाद वह आगे चलकर पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गए और एक कमीशन अधिकारी बन गए. बाद में वह सेना में मेजर बना दिए गए. उन्होंने वहां एक स्थानीय लड़की अमानत से शादी की औक एक बेटे के पिता भी बन गए.

चौथी दुनिया ब्यूरो

रविन्द्र कौशिक का जन्म राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर नामक जिले में हुआ. वे एक प्रसिद्ध थिएटर कलाकार थे और अपनी योग्यता राष्ट्रीय स्तर नाटक सभा लखनऊ में प्रदर्शित कर चुके हैं जिसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कुछ अधिकारियों ने भी देखा. रॉ के अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया और उन्हें भारत के लिए पाकिस्तान में खुफिया एजेंट के रूप में नौकरी का प्रस्ताव रखा गया. 23 वर्ष की आयु में उन्हें मिशन पाकिस्तान के इिश तैयार किया गया. रॉ ने उन्हें भर्ती करने के बाद दिल्ली में दो साल का गहन प्रशिक्षण दिया. उन्हें इस्लाम की धार्मिक शिक्षा दी गयी और पाकिस्तान के बारे में छोटी से बड़ी जानकारी दी गई और वहां की भौगोलिक और राजनीतिक जानकारियों से परिचित कराया गया. उन्हें उर्दू पढ़ायी गयी. वह पाकिस्तान की सीमा से सटे गंगानगर के निवासी होने की वजह से पाकिस्तान के बड़े हिस्से में बोली जाने वाली पंजाबी भाषा में निपुण थे.

उन्हें साल 1975 में मजह 23 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान भेजा गया. उन्हें नबी अहमद शाकिर नाम दिया गया. वो अपनी पहचान की बदौलत कराची विश्वविद्यालय में दाखिला पाने में कामयाब रहे, उन्होंने वहां से एलएलबी की शिक्षा हासिल की. इसके बाद वह आगे चलकर पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गए और एक कमीशन अधिकारी बन गए. बाद में वह सेना में मेजर बना दिए गए. उन्होंने वहां एक स्थानीय लड़की अमानत से शादी की औक एक बेटे के पिता भी बन गए. साल 1979 से 1989 के

दरम्यान उन्होंने जो सूचनायें रॉ को भेजीं वे भारतीय रक्षा बलों के लिए बहुत मददगार थी. उन्हें भारत के तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चव्हाण ने ब्लैक टाइगर का खिताब दिया था. कुछ जानकारों का कहना है कि उन्हें यह खिताब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था.

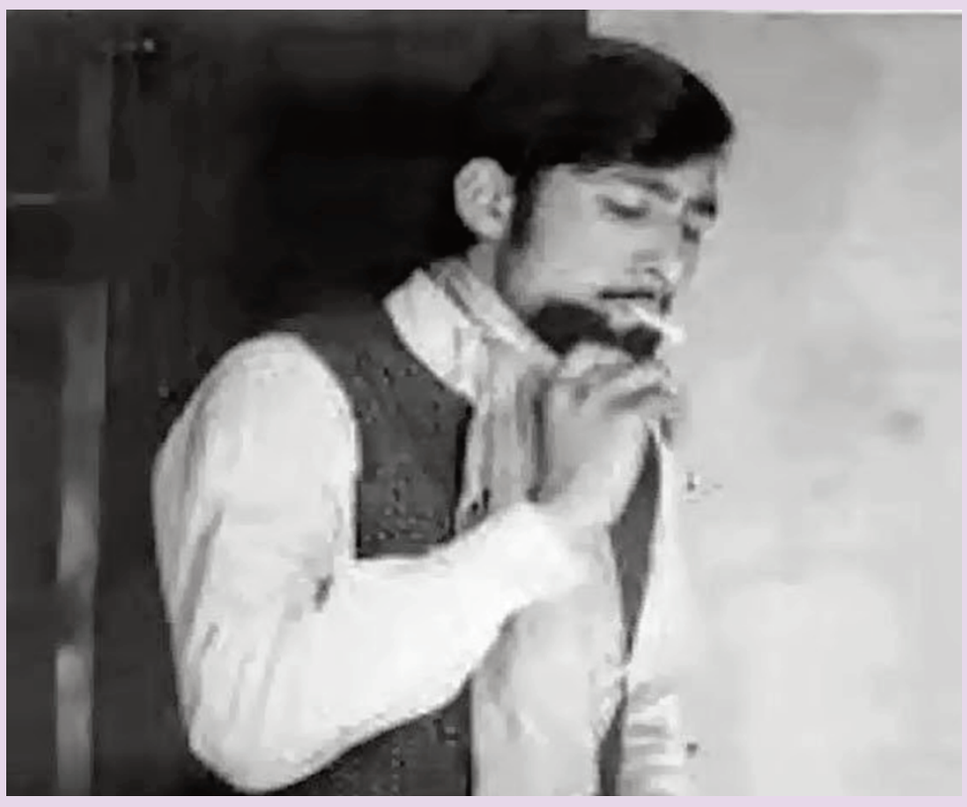

उन्होंन बहुत विपरीत परिस्थितियों में अपने परिवार से दूर पाकिस्तान में अपने जीवन के 26 साल बिताए. युद्ध के दौरान रविन्द्र कौशिक द्वारा प्रदान की गई गुप्त जानकारियों का उपयोग कर भारत पाकिस्तान से हमेशा एक कदम आगे रहा. कई अवसरों पर पाकिस्तान भारत की सीमाओं के पार युद्ध छेड़ना चाहता था लेकिन रविन्द्र कौशिक द्वारा समय पर दी गई गुप्त जानकारियों की बदौलत इसे नाकाम कर दिया गया. सितंबर 1983 में, भारतीय खुफिया एजेंसियों को ब्लैक टाइगर के साथ संपर्क में बनाने के लिए एक एजेंट इनायत मसीह को पाकिस्तान भेजा था. लेकिन उस एजेंट को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने पकड़ लिया और रविंदर कौशिक की असली पहचान का पता चला गया. कौशिक को सियालकोट के एक पूछताछ केंद्र में दो साल तक प्रताड़ित किया गया औक यातनायें दी गईं. वर्ष 1985 में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी. बाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया. उन्हें 16 साल सियालकोट, कोटलखपत और मियांवाली जेल सहित विभिन्न जेलों में रखा गया था. वहां कौशिक को दमा और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ गए. चुपके से वह भारत में अपने परिवार के लिए पत्र भेजने में कामयाब रहे. उसमें उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य की स्थिति और पाकिस्तान की जेलों में अपने ऊपर होने वाले यातनाओं के बारे में उस पत्र में लिखा. लेकिन भारत सरकार ने उनकी खोज नहीं की.

उन्होंने अपने एक पत्र में पूछा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने का यही ईनाम मिलता है? नवंबर 2001 को उन्होंने मुल्तान सेंट्रल जेल में फेफड़े, तपेदिक और दिल की बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया. उन्हें जेल के पीछे कब्रिस्तान में दफनाया गया था. रवींद्र के परिवार ने दावा किया की वर्ष 2012 में प्रदर्शित मशहूर बॉलीवुड फिल्म एक था टाइगर की शीर्षक लाइन रवींद्र के जीवन पर आधारित थी. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

मोदी का विदेश दौरा

बेहतर व्यापारिक संबंधों की ओर एक क़दम

शफीक आलम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन एशियाई देशों की यात्रा चीन के शहर शियान से शुरू हुई. हालांकि, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक सहयोग बढ़ाना था, लेकिन दोनों देशों के बीच दशकों से चले आ रहे सीमा विवाद को लेकर परस्पर अविश्वास की भावना से यह यात्रा बची नहीं रह सकी. इस यात्रा की शुरुआत से पहले ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक आलेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की यात्रा से परहेज़ करने के लिए कहा. इस आलेख में यह भी कहा गया कि भारतीय लोग कमतर होते हैं. भारत ने भी जवाब में चीन द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर से पाकिस्तान के दक्षिण में स्थिति गवादर बंदरगाह तक व्यापार गलियारा बनाने की योजना पर अपनी आपत्ति जताई. यात्रा के दौरान एक और विवाद उस समय पैदा हुआ, जब चीन के सरकारी टीवी चैनल ने नरेंद्र मोदी की यात्रा की ख़बरें दिखाते समय भारत के नक्शे से जम्मू–कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को गायब कर दिया.

दरअसल, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना था. चूंकि अब द्विपक्षीय व्यापार के मामले में चीन भारत का सबसे बड़ा साझीदार है. वर्ष 2014 में दोनों देशों के बीच तक़रीबन 70 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था. इसमें भारत का व्यापार घाटा 40 अरब डॉलर के आसपास है. इसका मतलब यह कि भारत खरीदता अधिक और बेचता कम है. वर्ष 2001 में यह घाटा केवल एक अरब डॉलर था और अब यह 40 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. इससे व्यापार घाटे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का एक उद्देश्य इस व्यापार घाटे को कम करना भी था. पहले से ही अख़बारों में रिपोर्ट्स आ रही थीं कि भारत दोनों देशों के बीच के व्यापार की खाई कम करने का प्रयास करेगा. लिहाज़ा यात्रा से ठीक पहले ही चीनी सरकारी अख़बार के विवादित आलेख के ज़रिये भारत को दबाव में लाने की एक कोशिश की गई. इसका एक और कारण यह हो सकता है कि चीन की इच्छा के विपरीत भारत दक्षिण चीन सागर में जापान, अमेरिका और वियतनाम से सहयोग कर रहा है.

बहरहाल, इन शुरुआती विवादों के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा शुरू हुई, तो जिस गर्मजोशी से चीनी राष्ट्रपति शिन जिंगपिंग का भारत में स्वागत हुआ था, उसी गर्मजोशी का सुबूत देते हुए उन्होंने मोदी का स्वागत किया. सबसे पहले फ़रवरी महीने में राष्ट्रपति शी ने भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाक़ात के लिए प्रोटोकॉल तोड़ा और इस यात्रा के दौरान भी वह प्रोटोकॉल तोड़ते हुए बीजिंग से बाहर अपने गृह प्रांत शान्शी में भारतीय प्रधानमंत्री से मिलने गए. कोई चीनी नेता किसी विदेशी नेता के लिए विरले ही ऐसा करता है.

दरअसल, दो देशों के बीच संबंध केवल सरकारों के बीच के अच्छे संबंध से नहीं बनते. उसमें उन दो देशों के लोगों के बीच भी कुछ आदान–प्रदान होना ज़रूरी है. नरेंद्र मोदी इस बात को न केवल अच्छी तरह से जानते हैं, बल्कि उन्होंने अपने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान इसका सफल प्रयोग भी किया है. लिहाज़ा चीन और भारत के लोगों के बीच की दूरी कम करने के लिए उन्होंने अपनी यात्रा से पहले चाइना का ट्वीटर कहलाने वाले वेबो (देखें बॉक्स) पर अपना प्रोफाइल बनाया. यात्रा की शुरुआत राजधानी बीजिंग और शंघाई के बजाय शान्शी प्रांत की राजधानी शियान से की. शियान से यात्रा की शुरुआत प्रतीकात्मक थी. इसके पीछे एक मंशा यह थी कि चीन और भारत के बीच पीपुल टू पीपुल संबंध बनाए जाएं और दूसरा यह कि प्राचीन सिल्क रोड यहीं से शुरू होती थी और भारत चीन से अच्छे व्यापारिक एवं राजनीतिक संबंध बनाना चाहता है. नरेंद्र मोदी यहां बौद्ध मंदिर वाइल्ड गूस पगौडा एवं ऐतिहासिक टेराकोटा वारियर देखने गए और उनकी तस्वीरें ट्वीट कीं. उसके बाद व्यापार और दूसरे मुद्दों पर बातचीत के लिए आगे बढ़े.

आपसी सहयोग के समझौते

यात्रा के दूसरे दिन बीजिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रधानमंत्री ली कीचियांग के बीच बातचीत के दौरान 10 अरब डॉलर के 24 समझौतों पर सहमति बनी. इनमें चेन्नई एवं चेंगडु में वाणिज्य दूतावास खोलने, स्किल डेवलपमेंट एवं वोकेशनल एजुकेशन में सहयोग, रेलवे विकास, विदेश मंत्रालय एवं सेंट्रल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी के बीच समन्वय, एजुकेशनल एक्सचेंज, ख़नन क्षेत्र, दूरदर्शन एवं सीसीटीवी के बीच प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग, पर्यटन को बढ़ावा, भू–विज्ञान एवं अंतरिक्ष में सहयोग, डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर एवं नीति आयोग, योग कॉलेज की स्थापना, भूकंप विज्ञान के विकास में सहयोग, औरंगाबाद एवं दुनहुआंग के बीच सिस्टर सिटीज और कर्नाटक एवं शिचुआन के बीच सिस्टर स्टेट संबंध, भारत–चीन थिंक टैंक की स्थापना आदि अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. इन समझौतों से जहां पीपुल टू पीपुल संबंध स्थापित करने में मदद मिलेगी, वहीं मोदी के स्मार्ट सिटी और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों को भी बढ़ावा मिलेगा.

इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने बीजिंग की सिंधुआ यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि चीन के नागरिकों को भारत आने के लिए अब ई–वीजा मिलेगा. मोदी और कीचियांग की बीच बैठक में दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद पर जल्द वार्ता शुरू करने और सुलझाने पर जोर दिया गया. ज़ाहिर है, इस मुद्दे पर भारत और चीन के बीच एक युद्ध हो चुका है. लेकिन, अब परिस्थिति ऐसी नहीं है कि भारत या चीन युद्ध के बारे में सोच सकें. हां, चीन की तरफ़ से अक्सर भारतीय सीमा में अतिक्रमण होता रहता है, लेकिन युद्ध की स्थिति कभी नहीं बनी. ज़ाहिर है, चीनी वस्तुओं के लिए जहां भारत के बहुत बड़ा बाज़ार है, वहीं इस क्षेत्र का एक शक्तिशाली परमाणु हथियार संपन्न देश भी है. चीन भी समझता है कि भारत के साथ अच्छे संबंध उसके हित में हैं.

मोदी की चीन यात्रा के आख़िरी दिन शंघाई में भारत और चीन के बीच 22 अरब डॉलर के आर्थिक एवं व्यापारिक समझौते हुए, जिनमें अक्षय ऊर्जा, वित्तीय क्षेत्र और बंदरगाहों के विकास में सहयोग आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं. जहां तक भारतीय कंपनियों का सवाल है, तो उनमें आईसीआईसीआई बैंक, अडानी ग्रुप, भारती एयरटेल, इन्फ़ोसिस लिमिटेड आदि शामिल हैं और चीनी कंपनियों में त्रिना सोलर, मिन्यंग विंड पॉवर, गोल्डन कांकोर्ड आदि शामिल हैं. अब सवाल यह उठता है कि भारत चीन को क्या बेच सकता है, क्योंकि इसके बिना चीन के साथ इतने बड़े व्यापार घाटे को कम नहीं किया जा सकता. भारत अभी शहरीकरण और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रांति लाने की योजना बना रहा है, तो चीन पहले से ही दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है. ऐसे में यह कहा जा सकता है कि भारत इन्फॉर्मेशन सेक्टर में चीन की मदद कर सकता है और चीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत की मदद कर सकता है.

मंगोलिया और दक्षिण कोरिया

अपनी विदेश यात्रा के अगले चरण में प्रधानमंत्री मोदी मंगोलिया गए. मंगोलिया में उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक अरब डॉलर का क़र्ज़ देने की घोषणा की. दरअसल, मंगोलिया चीन और एशियाई रूस के बीच बसा हुआ एक ग़रीब देश है. अफ्रीका के पिछड़े देशों की तरह यहां भी पूंजी निवेश की संभावनाएं मौजूद हैं. प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक अरब डॉलर का क़र्ज़ उसी दिशा में एक क़दम है. यह दौरा भारत और मंगोलिया के बीच राजनयिक संबंधों के 66 साल पूरे होने और मंगोलिया के लोकतंत्र की गोल्डन जुबली के संबंध में भी किया गया था. लेकिन, सरकार की विदेश नीति में महाराष्ट्र की सियासत आड़े आ गई. महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने इस क़र्ज़ को हलके में नहीं लिया है. शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में यह सवाल उठाया गया है कि प्रधानमंत्री यही दरियादिली राज्य के सूखा प्रभावित किसानों के लिए क्यों नहीं दिखा रहे हैं? दक्षिण कोरिया भी एशिया के विकास की कहानी में एक बहुत अहम अध्याय है. एशियाई अर्थव्यवस्था में इस देश को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. इसलिए अपनी यात्रा के आख़िरी चरण में प्रधानमंत्री ने इस देश का दौरा किया. प्रधानमंत्री मोदी की दो दिनों की यात्रा के दौरान छह समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. इसके अलावा उन्होंने दक्षिण कोरियाई कंपनियों ह्युंदै, सैमसंग, पोस्को और एलगी के सीईओ से भी मुलाक़ात की.

कुल मिलाकर देखा जाए, तो मोदी का यह दौरा जहां चीन और भारत के बीच का व्यापार घाटा कम करने, उनके मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत और स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर था, वहीं इसमें एक और भू–राजनीतिक खेल भी साफ़ दिखाई दे रहा है. मोदी की नीति यह है कि इस क्षेत्र के सभी पक्षों के साथ मिलकर काम किया जाए. मिसाल के तौर पर जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया चीन के आर्थिक विकास से चिंतित हैं. जापान और अमेरिका द्वारा दक्षिण चीन सागर में चलाए जा रहे कार्यक्रम, जिसमें भारत और वियतनाम भी शामिल हैं, से चीन खुश नहीं है. मोदी इन सभी देशों से व्यापार करना चाह रहे हैं. फ़िलहाल वह अपनी नीति में सफल दिख रहे हैं, लेकिन इन सभी समझौतों का अभी ज़मीनी हकीक़त बनना बाकी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

यात्रा और विवाद

प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं पर जहां एक तरफ़ लोग उनकी प्रशंसा करते दिखे, वहीं ऐसे भी लोग थे, जो उनका मज़ाक बनाते दिखाई दिए. उनके प्रशंसकों का मानना है कि मोदी की यात्राओं की वजह से विदेशों में भारत का सम्मान बढ़ा है. भारत दुनिया के बड़े देशों से आंख में आंख मिलाकर अपनी शर्तों पर समझौते कर सकता है. वहीं उनके आलोचक उनकी एक साल में 18 विदेश यात्राओं का मज़ाक उड़ा रहे हैं. फ़िलहाल इस यात्रा के दौरान चीन और दक्षिण कोरिया में दिए गए उनके दो भाषणों पर विवाद उठ खड़ा हुआ है. शंघाई में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि पहले एक भारतीय के रूप में जन्म लेने पर आपको शर्म आती थी और अब इस देश का प्रतिनिधित्व करते हुए आप गौरवांवित महसूस करते हैं. इसे लेकर ट्वीटर पर मोदीइन्सल्टइंडिया ट्रेंड करने लगा. साथ में चीनी टीवी कार्यक्रम में भारत के नक्शे से जम्मू–कश्मीर एवं अरुणाचल का गायब होना और चीनी अख़बार द्वारा प्रधानमंत्री को अरुणाचल का दौरा करने से परहेज़ की सलाह इस यात्रा के दूसरे विवाद थे. ■

मोदी का वेबो एकाउंट और सेल्फी

चीन के लोगों से प्रत्यक्ष रूप से संवाद स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चीन यात्रा से पहले वहां ट्वीटर की तरह इस्तेमाल होने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट वेबो पर अपना प्रोफाइल बनाया. इस प्रोफाइल के बनने के महज़ छह दिनों के अंदर उनके 46 हज़ार से अधिक फॉलोवर बन गए. एक रिपोर्ट के मुताबिक, किसी दूसरे विदेशी नेता को वेबो पर इतनी जल्दी इतना लोकप्रिय होते नहीं देखा गया. बहरहाल, इस साइट पर जहां उनके और भारत के प्रशंसक मिले, वहीं उनकी और भारत की आलोचना करने वाले भी मौजूद थे. वेबो पर उनकी पहली पोस्ट को 47 हज़ार बार फॉरवर्ड किया गया और 25 हज़ार लोगों ने उस पर अपने कमेंट दिए थे. मोदी अपनी सेल्फी के लिए भी जाने जाते हैं. उनकी सेल्फी 2014 के आम चुनाव के दौरान विवादों में घिर गई थी. आम तौर पर अपनी हर यात्रा में मोदी सेल्फी लेना नहीं भूलते हैं. इस यात्रा के दौरान भी उन्होंने चीनी प्रधानमंत्री ली कीचियांग के साथ बीजिंग में एक सेल्फी ट्वीटर पर पोस्ट की थी, जिस पर अमेरिकी अख़बार वाल स्ट्रीट जर्नल ने दुनिया की सबसे ताक़तवर सेल्फी की हेडिंग के साथ एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी. ■

स्वामी जी बोले कि मैं यहां धर्म प्रचार के लिए आया हूं न कि धर्म परिवर्तन के लिए. मैं अमेरिकी धर्म–प्रचारकों को यह संदेश देने आया हूं कि वे धर्म परिवर्तन के अभियान को बंद कर प्रत्येक धर्म के लोगों को बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करें. यही धर्म की सार्थकता है. यही सभी धर्मों का मकसद भी है. हिंदू संस्कृति विश्व बंधुत्व का संदेश देती है, मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानती है. वह प्रोफेसर उनकी बातों से अभिभूत हो गए और बोले, स्वामी जी, कृपया इस बारे में और विस्तार से कहिए.

शाश्वत साई चेतना

चौथी दुनिया ब्यूरो

भक्ति ही ईश्वर या सदगुरु–पूजन का मूल मंत्र है. श्री शिरडी साई बाबा के अनुसार श्रद्धा एवं सबूरी भक्ति मार्ग के दो आवश्यक गुण हैं. भक्ति परंपरा के इतिहास को पढ़ने पर यह अहसास होता है कि एक शरीरधारी सदगुरु के प्रति दृढ़ आस्था रखना सम्भवत: ज्यादा सहज है, बल्कि उन सदगुरुओं के प्रति जो कि शरीर छोड़ चुके हैं. श्री सदगुरु अदृश्य एवं सूक्ष्म क्रिया–कलापों के साथ प्रत्यक्ष रूप में भी जनकल्याण के लिए अपने असंख्य कर्म करते रहते हैं. एक शरीरधारी सदगुरु को भक्तगण अपनी इन्द्रियों के माध्यम से पारस्परिक रूप में तथा प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं और छू सकते हैं जो कि सदगुरु की निश्चल प्रतिमा, फोटो या चित्र आदि के द्वारा संभव नहीं है. जिन भक्तों ने सदगुरु के मानवीय शरीर–धारण की अवधि में उनके साथ(चाहे वह शारीरिक रूप में उनसे कहीं दूरे हों) एक सूक्ष्म मानसिक प्रक्रिया द्वारा आध्यात्मिक संयोग स्थापित कर लिया, उनके लिए सदगुरु के शरीर छोड़ने के बाद भी इस प्रकार का सूक्ष्म मानसिक सम्पर्क बना रहता है. वो भक्त जो सदगुरु के साथ रहते हुए भी इस प्रकार की प्रगति नहीं कर पाए थे, या तो जो सदगुरु के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाए थे, ऐसे भक्तों के लिए सदगुरु के शरीर छोड़ने के बाद उनके प्रति उसी प्रकार का श्रद्धा–भाव बनाए रखना कठिन था. इस कारण उनके गुरु ध्यान और एकाग्रता एवं एकनिष्ठता में क्रमश: ह्रास होने की संभावना रहती है. सदगुरु के समक्ष भक्तगण एक प्रकार की सूक्ष्म मन: स्थिति को प्राप्त करते हैं, जिसको हम अन्य भाषा में आध्यात्मिक पोषण या आध्यात्मिक पुष्टिकरण भी कह सकते हैं. सदगुरु के महाप्रयाण के पश्चात उनकी समाधि का पूजन भक्तगण केवल उसके कलात्मक सौंदर्य के कारण ही नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं कि उस समाधि के नीचे उन सदगुरु का शरीर है, जिनको कि वे प्यार करते हैं.

अब जरा हम अपने सदगुरु श्री शिरडी साई बाबा का उदाहरण लें. अपना शरीर छोड़ने के पहले बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में अपने भक्तों को कुछ आश्वासन दिए थे जो कि बाबा के ग्यारह वचनों के रूप में प्रसिद्ध हैं. उनके ग्यारह वचनों का सार तथ्य यह है कि बाबा अपनी समाधि से भी अपने पुराने एवं नए सभी भक्तों की रक्षा एवं मार्गदर्शन करेंगे.

जो भक्त सदगुरु के महाप्रयाण के बाद जन्म लेते हैं, उनकी स्थिति कुछ और है. सदगुरु से सम्बन्धित अनुभव–प्राप्त उन पुराने भक्तों से या तो फिर उनसे सम्बन्धित विभिन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं, दूरदर्शन के कार्यक्रम आदि से सदगुरु के दिव्य गुणों के बारे में उन्हें जो जानकारी प्राप्त होती है, उससे प्रभावित होकर वे भक्त बन जाते हैं. आजकल तो इस प्रकार की सूचनाएं इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है. अत: जब वो सदगुरु के अनुगामी या अनुयायी बन जाते हैं, तो फिर

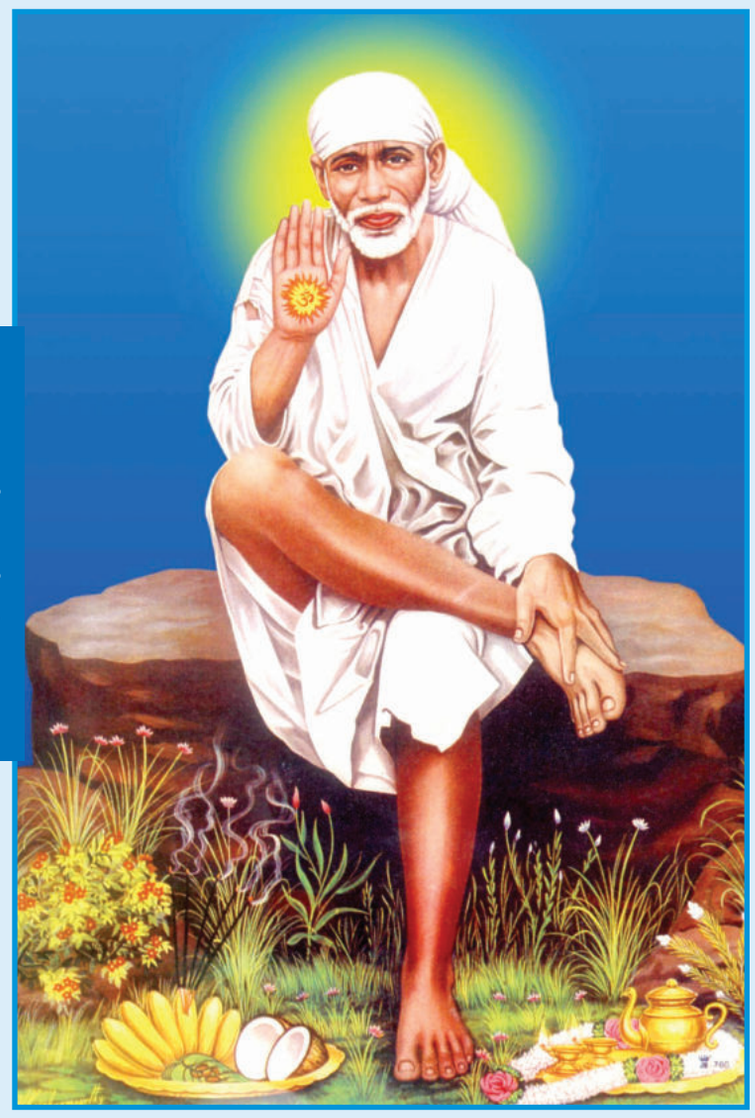

वो (भक्तगण) अपने गुरु से संबन्धित साहित्य पढ़ने लगते हैं, उससे सम्बन्धित प्रश्न करने लगते हैं और अन्य भक्तों के साथ आपसी अनुभवों का आदान–प्रदान भी करने लगत हैं. जब वे सदगुरु की दिव्य संवेदनशीलता और अन्य ईश्वरीय गुणों से प्रभावित हो जाते हैं, तब वे उनकी पूजा भी करनी शुरू कर देते हैं. इस प्रकार करते–करते वे क्रमश: सदगुरु के साथ एक प्रकार का सूक्ष्म मानसिक एवं भावात्मक सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं. वे यह भी अनुभव करने लगते हैं कि सदगुरु आध्यात्मिक प्रगति में उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनको सांसारिक कठिनाईयों से बचाते भी रहते हैं.

हालांकि कुछ लोग यह मानते हैं कि केवल एक शरीरधारी सदगुरु ही अपने भक्तों का दिशा–निर्देश कर सकते हैं एवं उनकी रक्षा कर सकते हैं और जब एक बार वे अपना शरीर छोड़ देते हैं तो वे अपने भक्तों को सक्रिय रूप से सहायता नहीं पहुंचा सकते. इसीलिए जिन्हें वे जीवित सदगुरु कहते हैं केवल उन्हीं का अनुसरण करने पर ही बल देते हैं.

अब जरा हम अपने सदगुरु श्री शिरडी साई बाबा का उदाहरण लें. अपना शरीर छोड़ने के पहले बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में अपने भक्तों को कुछ आश्वासन दिए थे जो कि बाबा के ग्यारह वचनों के रूप में प्रसिद्ध हैं. उनके ग्यारह वचनों का सार तथ्य यह है कि बाबा अपनी समाधि से भी अपने पुराने एवं नए सभी भक्तों की रक्षा एवं मार्गदर्शन करेंगे. एक बार जब बाबा भाव सामधि में थे तो उन्होंने उस आनन्दमयी अवस्था में कुछ भक्तों के समकक्ष यह भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में शिरडी में इतनी संख्या में बड़े और छोटे लोग कतार लगाए उनकी समाधि पर आएंगे कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है. उन्होंने यह भी कहा था कि वे गुली गुली(गली गली) में रहेंगे. अब हम यह देखें कि बाबा कि भविष्यवाणी उनकी महासमाधि के नब्बे वर्षों बाद भी कैसे सिद्ध हुई है. पिछले नब्बे वर्षों और पिछले बीस वर्षों में जिस प्रकार बाबा के नाम की ख्याति और भक्तों की संख्या में वृद्धि हुई है, वह अपने में ही चमत्कार हैं. बाबा के नाम से देश भर में हजारों की संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ है और विभिन्न प्रकार के लोग कल्याणकारी (जैसे चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक एवं धार्मिक) गतिविधियों में अपार वृद्धि हुई है. बाबा के नाम एवं उनकी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में पुस्तकों पत्रिकाओं, स्मारिकाओं आदि की इतनी अधिक संख्या में रचना हुई है कि उनका यहां पर उल्लेख कर पाना संभव नहीं है. संपूर्ण विश्व में बाबा के न केवल सैकड़ों नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है बल्कि बहुत से अन्य मंदिरों के परिसर में भी उनकी प्रतिमाएं विधिवत स्थापित की जा रही हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दु:ख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

निरर्थक सिद्ध होती राज्यसभा

संविधान निर्माताओं ने दूरदर्शी सोच की दृष्टि से लोकसभा के उच्च सदन राज्यसभा का गठन किया था. लोकसभा में तो जाति व धर्म के बल पर एक अपराधी भी चुनकर आ सकता है, लेकिन राज्यसभा में समाज के साहित्यकारों, कलाकरों, वैज्ञानिकों व अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों के मनोनयन की परंपरा थी. अब सब उलट हो गया है. अब राज्यसभा चुनाव हार चुके तिकड़मी और सौ–पचास करोड़ खर्च करने की सामर्थ्य रखने वालों का संकुल रह गई है. सदन में हो हल्ला मचाना और सरकार द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में अड़ंगा लगाना ही उनका काम रह गया है.

–राजकिशोर पांडेय, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

विलंटन फाउंडेशन को चंदा

कवर स्टोरी–मुलायम, अमर, सुब्रत और चंदा(18 मई–24 मई 2015) पढ़ा. काफी विचारोत्तेजक है. प्रभातरंजन दीन ने अपने लेख में अमर सिंह द्वारा क्लिंटन फाउंडेशन को लाखों डॉलर का चंदा दिए जाने और जिन बातों का जिक्र किया है. वह अमर सिंह पर संदेह पैदा करते हैं. यह भी सच है कि आज के दौर कई नेता लाखों करोड़ों दबाएं बैठे हैं जो देश की गरीब जनता का है. क्लिंटन फाउंडेशन को चंदा देने वालों में जो लोग शामिल हैं. उन सभी की सम्पत्तियों की जांच होनी चाहिए, अगर उनके पास आय से अधिक संपत्ति पाई जाए, तो उन सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

–सोमनाथ साहू, बक्सर, बिहार.

मराठवाड़ा का दुख

आलेख–मराठवाड़ा के गिरमिटिया मजदूर, पलायन की अंतहीन दास्तां(18 मई–24 मई 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. लेखक ने अपने आलेख के माध्यम से मराठवाड़ा की जो सच्चाई सामने लाने की कोशिश की है. वह काबिले तारीफ है. महाराष्ट्र का मराठवाड़ा इलाका कई साल से सुखे की मार झेल रहा है और वहां का किसान मजदूरी के लिए पलायन को मजबूर है. महाराष्ट्र में कई सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी ने मराठावाड़ा की सुध नहीं ली. इस आलेख को पढ़कर वहां के लोगों के दर्द के बारे में पता चलता है. वहां पर स्कूल नहीं है अगर हैं भी तो वह कब बंद होंगे कभ खुलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं. पानी की सुविधा नहीं, सड़के नहीं है और लोगों को फसल के नुकसान का मुवावजा नहीं मिलता है. इस सवाल का वहां के कलेक्टरों का जवाब न देना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं. सरकार को चाहिए कि मराठवाड़ा क्षेत्र के लोगों के तकलीफ को समझे और वहां के लोगों की मदद करे ताकि वहां के लोग खुशी का जीवन जी सकें.

–रोहित सिंह, पालम, दिल्ली.

यह बयान गलत है

जब तोप मुकाबिल हो– जफर सरेशवाला का जहरीला बयान(18 मई–24 मई 2015) पढ़ा. काफी विचारोत्तेजक है. संतोष भारतीय ने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने साथियों को समझाएं या उन्हें अपने से अलग करें. जफर सरेशवाला ने सलमान खान की सजा पर जो बयान दिया था, वह बेहद शर्मनाक है. सलमान खान के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि सलमान खान को सजा इसलिए हुई, क्योंकि सलमान खान मुसलमान हैं. यह बयान कोई कट्टरपंथी नेता देता तो यह बात समझ में आती. लेकिन यह बात ज़फर सरेशवाला कह रहे हैं. इसका मतलब है कि या तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति से ऐसा कह रहे हैं या फिर वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुसीबत में डालने के लिए यह बात कह रहे हैं. जफर सरेशवाला को मोदी समर्थक के रूप में जाना जाता है. अगर वह ऐसा बयान दें तो देश में गलत संदेश जाएगा जो देश के लिए ठीक नहीं है. इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ऐसे बयानों पर रोक लगानी चाहिए या ऐसे लोगों तत्काल अपने से दूर करना चाहिए.

–राजनारायण यादव, दरभंगा, बिहार.

विपक्ष के साथ संवाद होना चाहिए

आलेख–टकराव से सरकार को फायदा नहीं होगा(18 मई–24 मई 2015) पढ़ा. कमल मोरारका ने सही कहा है कि टकराव से सरकार को फायदा नहीं होगा. सरकार संसद में विपक्ष के साथ खुला संवाद करने में नाकाम रही है, उसे विपक्ष के साथ खुला संवाद करना चाहिए. पहले भी पूर्ण बहुमत की सरकारे रही हैं, लेकिन वह हमेशा विपक्ष के साथ खुला संवाद करती थीं. संसद में विपक्ष के साथ टकराव के कारण कई सारे महत्वपूर्ण विधेयक संसद में अटके पड़े हैं. अगर संसद में विपक्ष के साथ टकराव बना रहा तो सरकार को महत्वपूर्ण विधेयक पास कराने में दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है. और सरकार के विकास की गति पर रोक लग सकती है. इसलिए सरकार को विपक्ष के संवाद स्थापति करना चाहिए.

–अमरेन्द्र कुमार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

निष्पक्ष समाचार पत्र

चौथी दुनिया समाचार पत्र में प्रकाशित सभी खबरें तथ्यों पर आधारित और निष्पक्ष होती हैं. चौथी दुनिया समाचर पत्र पढ़कर सबसे अधिक खुशी होती है कि साप्ताहिक होने के बावजूद भी इसमें पूरे सप्ताह की खबरें पढ़ने को मिल जाती है. इस समाचार की खबर पढ़ने के बाद पूरी खबर पढ़ने का मन करता है और दूसरे समाचार पत्रों के साथ ऐसा नहीं है. इसमें हमेशा नए विषय पर आधारित कवर स्टोरी पढ़ने को मिलती है. समाचार पत्र में प्रकाशित कवर स्टोरी में हमेशा नई जानकारी होती है. आशा है कि चौथी दुनिया समाचार पत्र ऐसे ही अपना अभियान जारी रखेगा.

–रुपेश मौर्या, रायबरेली, उत्तर प्रदेश.

धर्म का सार

चौथी दुनिया ब्यूरो

यह उन दिनों की बात है, जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे. वहां कई महत्वपूर्ण जगहों पर उन्होंने व्याख्यान दिए. उनके व्याख्यानों का वहां जबर्दस्त असर हुआ. लोग स्वामी जी को सुनने और उनसे धर्म के विषय में अधिक अधिक से जानने को उत्सुक हो उठे. उनके धर्म संबंधी विचारों से प्रभावित होकर एक दिन एक अमेरिकी प्रोफेसर उनके पास पहुंचे. उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम कर कहा कि स्वामी जी, आप मुझे अपने हिंदू धर्म में दीक्षित करने की कृपा करें.

इस पर स्वामी जी बोले कि मैं यहां धर्म प्रचार के लिए आया हूं न कि धर्म परिवर्तन के लिए. मैं अमेरिकी धर्म–प्रचारकों को यह संदेश देने आया हूं कि वे धर्म परिवर्तन के अभियान को बंद कर प्रत्येक धर्म के लोगों को बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करें. यही धर्म की सार्थकता है. यही सभी धर्मों का मकसद भी है. हिंदू संस्कृति विश्व बंधुत्व का संदेश देती है, मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानती है. वह प्रोफेसर उनकी बातों से अभिभूत हो गए और बोले, स्वामी जी, कृपया इस बारे में और विस्तार से कहिए.

प्रोफेसर की यह बात सुनकर स्वामी जी ने कहा, महाशय, इस पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का आगमन हुआ था. उस समय कहीं कोई धर्म, जाति या भाषा न थी. मानव ने अपनी सुविधानुसार अपनी–अपनी भाषाओं, धर्म तथा जाति का निर्माण किया और अपने मुख्य उद्देश्य से भटक गया. यही कारण है कि समाज में तरह–तरह की विसंगतियां आ गई हैं. लोग आपस में विभाजित नजर आते हैं. इसलिए मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि तुम अपना धर्म पालन करते हुए अच्छे ईसाई बनो. हर धर्म का सार मानवता के गुणों को विकसित करने में है इसलिए तुम भारत के ऋषियों–मुनियों के शाश्वत संदेशों का लाभ उठाओ और उन्हें अपने जीवन में उतारो. वह प्रोफेसर मंत्रमुग्ध यह सब सुन रहे थे. स्वामी जी के प्रति उनकी आस्था और बढ़ गई. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर–11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन–201301

कविता में अभियान, गद्य में शासन

अनंत विजय

केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के एक साल पूरे होने वाले हैं. सरकार के साल भर के कामकाज का आकलन हो रहा है. तमाम तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता मापी जा रही है. नतीजे कहीं कम, कहीं ज़्यादा, तो कहीं स्थिर नज़र आ रहे हैं. सरकार की नीतियां कसौटी पर कसी जा रही हैं और उसके नतीजों पर बहस हो रही है. सरकार ने भी अपनी साल भर की उपलब्धियों को लेकर जनता के सामने जाने की रणनीति का खुलासा कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मथुरा रैली से उसका आगाज होगा. देश भर में हर ज़िला मुख्यालय पर पार्टी के प्रवक्ता प्रेस कांफ्रेंस करेंगे. यह मोदी का अपना स्टाइल है, जिसे विराट या भव्य कहा जा सकता है. अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के पूरा होने और न होने के इस कोलाहल के बीच एक चीज जो नरेंद्र मोदी को लेकर कायम है, वह है, उन पर लिखी जानी वाली किताबें. चुनाव से पहले शुरू हुआ यह सिलसिला अब भी कायम है और नियमित अंतराल पर नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखकर किताबें लिखी जा रही हैं. पहले लोकसभा चुनाव को लेकर कई किताबें आईं, परंतु उन सबके केंद्र में नरेंद्र मोदी ही थे, परिधि पर राहुल गांधी और अन्य दलों के नेता. नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कई लेखकों ने उनके व्यक्तित्व को अपनी लेखनी के माध्यम से खोलने का प्रयास किया. कई गंभीर कोशिशें हुईं, तो कुछ स्वयंभू लेखकों ने इसे अवसर की तरह भुनाने के लिए किताबें लिखीं, जिनका कोई स्थायी महत्व नहीं है.

पाठकों को याद होगा कि जब नब्बे के दशक के अंतिम वर्षों में लालू यादव अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे, तो लालू चालीसा से लेकर ग्रंथावलियां तक लिखी गईं. चालीसा लिखने वाले एक सज्जन तो राज्यसभा तक पहुंच गए. मोदी पर लिखने वाले कई लेखकों की मंशा भी वहीं पहुंचने की है, लिहाजा वे भक्तिभाव से लेखन कर रहे हैं. हो सकता है कि इस तरह के लेखन से उन्हें लाभ मिल जाए, लेकिन साहित्य या राजनीतिशास्त्र को वे कोई स्थायी महत्व की पुस्तक नहीं दे पाएंगे. किताबों की इस भीड़ के बीच लंबे समय तक पत्रकार रहे लेंस प्राइस की किताब– द मोदी इफेक्ट, इनसाइड नरेंद्र मोदीज़ कैंपेन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया प्रकाशित हुई. लेंस प्राइस का लंबा अंतराल बीबीसी में राजनीतिक संवाददाता के तौर पर गुज़रा. बाद में उन्होंने ब्रिटेन की लेबर पार्टी का कम्युनिकेशन विभाग संभाला और लगभग साल–डेढ़ साल उसके प्रमुख भी रहे. ब्रिटेन के 10, डाउनिंग स्ट्रीट में भी उन्होंने दो साल बिताए. इसके पहले भी लेंस प्राइस की किताबें–स्पिन डॉक्टर्स डायरी और टाइम एंड फेट खासी चर्चित रही हैं. अपनी किताब–द मोदी इफेक्ट में लेंस प्राइस ने पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की रणनीतियों को उनके क़रीबियों के माध्यम से परखने की कोशिश की है. इस किताब के लिए लेंस प्राइस ने नरेंद्र मोदी से लंबी बातचीत की और उनके मन, मिजाज और व्यक्तित्व को समझा. चुनावी रणनीति पर मोदी के अलावा उनकी टीम के सदस्यों से भी बात की गई. मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी दिनचर्या जानने से लेकर लाल किले पर उनका भाषण सुनने और उसे अनुभव करने के लिए लेखक अपने अनुवादक के साथ मौजूद थे. इस पूरी किताब में लेंस प्राइस वस्तुनिष्ठ होकर उनका मूल्यांकन करते हैं.

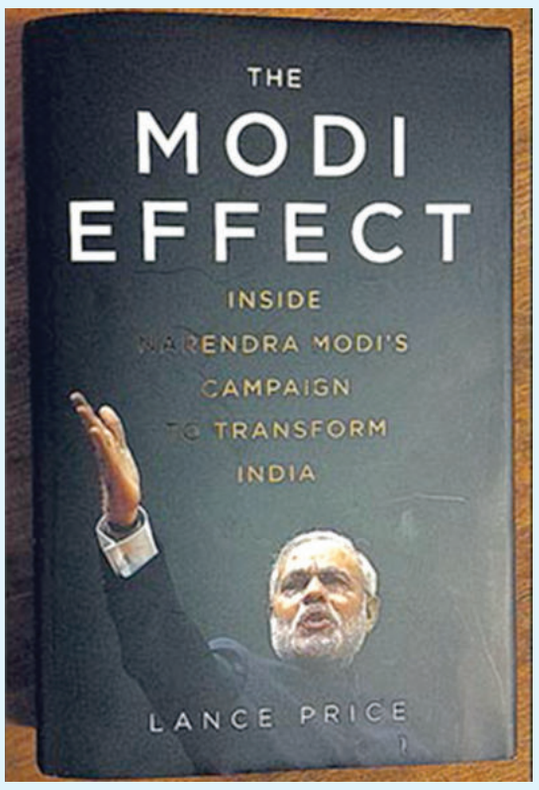

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कई लेखकों ने उनके व्यक्तित्व को अपनी लेखनी के माध्यम से खोलने का प्रयास किया. कई गंभीर कोशिशें हुईं, तो कुछ स्वयंभू लेखकों ने इसे अवसर की तरह भुनाने के लिए किताबें लिखीं, जिनका कोई स्थायी महत्व नहीं है. जब नब्बे के दशक के अंतिम वर्षों में लालू यादव अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे, तो लालू चालीसा से लेकर ग्रंथावलियां तक लिखी गईं. चालीसा लिखने वाले एक सज्जन तो राज्यसभा तक पहुंच गए. मोदी पर लिखने वाले कई लेखकों की मंशा भी वहीं पहुंचने की है, लिहाजा वे भक्तिभाव से लेखन कर रहे हैं.

हाल के दिनों में जिन भारतीय पत्रकारों या लेखकों ने नरेंद्र मोदी या उनकी रणनीति पर लिखा, उनमें से कुछ अपवादों को छोड़कर, सबने भक्तिभाव से लिखा. इस मायने में लेंस प्राइस की किताब थोड़ी अलग है. लेंस प्राइस ने अपनी इस किताब में पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी की रणनीति के रेशों को उघाड़ने की बहुत हद तक कामयाब कोशिश की है. किस तरह से नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया से लेकर मीडिया का चुनावी इस्तेमाल कर ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की. नरेंद्र मोदी से अपनी पहली मुलाकात में लेखक शुरू में यह दंभ भरता है कि वह किसी के भी प्रभाव में नहीं आता है. इस क्रम में वह अपने लंदन के प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने और विश्व के बड़े नेताओं से मिलने का ज़िक्र करके अपने तर्कों को मजबूत भी करने की कोशिश करते हैं. बड़ी शख्सियतों पर किताब लिखने में एक तकनीक का इस्तेमाल बहुधा लेखक करते हैं, जिसे नेम ड्रापिंग कहते हैं. लेंस प्राइस ने भी अपनी इस पूरी किताब में 10, डाउनिंग स्ट्रीट के अपने कार्यकाल में मिले नेताओं का जमकर नेम ड्रापिंग किया है. जैसे मोदी से हुई अपनी पहली मुलाकात का ज़िक्र करते हुए लेंस प्राइस दक्षिण अफ्रीका के करिश्माई नेता नेल्सन मंडेला के साथ अपनी दस मिनट की मुलाकात का ज़िक्र करते हैं.

मोदी के व्यक्तित्व के बारे में लिखते हुए लेंस प्राइस ने कहा है कि वह हर स्थिति को अपने कंट्रोल में रखते हैं, चाहे कोई मुलाकात ही क्यों न हो. लेंस कहते हैं कि मोदी इंपोजिंग भी हैं और उनकी आंखें सामने वाले को अंदर तक भेदने की क्षमता रखती हैं. लेंस प्राइस ने उनके चुनावी जुमलों को भी अपनी इस किताब में सफलता और असफलता के नज़रिये से देखने की कोशिश की है, जैसे छप्पन इंच की छाती पर लिखते हुए वह मोदी की लंबाई, उनकी चौड़ाई आदि का वर्णन करते हैं. यहां वह कहते हैं कि मोदी का सीना भले ही छप्पन इंच का न हो, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तित्व के साथ इस भारतीय मुहावरे को मिलाकर इस तरह पेश किया, ताकि एक मजबूत और दमदार नेता की छवि को बढ़ावा मिल सके. लेंस प्राइस नरेंद्र मोदी के अपने व्यक्तित्व को सहेज–संवार कर रखने की क्षमता से भी प्रभावित हैं. लेंस प्राइस की पहले यह धारणा थी कि मोदी अपने बारे में मनपसंद तरीके से लिखी चीजें पढ़ते हैं. पहली मुलाकात में नरेंद्र मोदी लेखक से यह कहते हैं कि वह जितनी चाहें, आलोचना कर सकते हैं, तो वह चकित रह जाते हैं.

लेंस प्राइस ने लिखा है कि मोदी का भाग्य और भगवान में काफी यकीन है. एक विदेशी लेखक के लिए यह अचंभा हो सकता है या फिर उसे यह बात उल्लेखनीय लग सकती है. लेंस प्राइस का दावा है कि उन्होंने यह किताब लिखने से पहले मोदी के बारे में काफी शोध किया था, लेकिन जब वह उनके धार्मिक होने का उल्लेख प्रमुखता से करते हैं, तो उनके उक्त दावे पर संदेह भी होता है. लेंस प्राइस लिखते हैं कि मोदी ने उनसे कहा, हम अपने धर्म में विश्वास रखते हैं, भाग्य पर यकीन करते हैं. म्हारो भाग्य विधाता जैसे शब्द लेखक से मोदी ने कहे. मोदी ने लेखक से कहा कि उनका भाग्य पर यकीन है. इस वजह से आज तक उन्होंने बुलेटप्रूफ जैकेट नहीं पहनी. लेखक ने मोदी के टेक सैवी होने को भी बहुत प्रमुखता दी है. इसी तरह एक बातचीत में मोदी ने नेता को परिभाषित करते हुए कहा, अच्छा नेता वह होता है, जिसमें सबको साथ लेकर चलने की क्षमता होती है. एक नेता के तौर पर मेरा मानना है कि आपको हर किसी से एक इंसान के तौर पर हाथ मिलाने के लिए उपलब्ध रहना चाहिए. लेकिन, इसका यह मतलब नहीं है कि एक नेता को सबको खुश रखना चाहिए. इतना अवश्य होना चाहिए कि नेता को खुद में, खुद के कर्मों में भरोसा होना चाहिए. इस

लेंस कहते हैं कि मोदी इंपोजिंग भी हैं और उनकी आंखें सामने वाले को अंदर तक भेदने की क्षमता रखती हैं. लेंस प्राइस ने उनके चुनावी जुमलों को भी अपनी इस किताब में सफलता और असफलता के नज़रिये से देखने की कोशिश की है, जैसे छप्पन इंच की छाती पर लिखते हुए वह मोदी की लंबाई, उनकी चौड़ाई आदि का वर्णन करते हैं. यहां वह कहते हैं कि मोदी का सीना भले ही छप्पन इंच का न हो, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तित्व के साथ इस भारतीय मुहावरे को मिलाकर इस तरह पेश किया, ताकि एक मजबूत और दमदार नेता की छवि को बढ़ावा मिल सके. लेंस प्राइस नरेंद्र मोदी के अपने व्यक्तित्व को सहेज–संवार कर रखने की क्षमता से भी प्रभावित हैं.

तरह की कई बातें किताब में हैं, जो मोदी का दर्शन समझने में मददगार साबित होती हैं. लेंस प्राइस ने मोदी की इस बात के लिए भी तारीफ़ की है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस के हर हमले को एक संभावना के तौर पर लिया और उसे इस तरह आगे बढ़ाया कि उसका फ़ायदा मिल सके. जैसे कांग्रेस के नेता मणि शंकर अय्यर के चायवाला की टिप्पणी को मोदी ने अपने चुनावी नारे की तरह इस्तेमाल कर लिया. चाय पर चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत हुई. यह अलहदा बात है कि चाय पर चर्चा कार्यक्रम तकनीकी दिक्कतों की वजह से तीन बार ही संभव हो सका, लेकिन उसके बाद थ्री डी एवं होलोग्राम तकनीक का इस्तेमाल कर उसे और व्यापक फलक प्रदान किया गया. कुल मिलाकर, अगर हम लेंस प्राइस की इस किताब का मूल्यांकन करें, तो पाते हैं कि यह पढ़ने में आनंद देती है, उस दौर की कई घटनाओं को एक नई दृष्टि से समझने का आधार भी देती है. मोदी का व्यक्तित्व या फिर उनकी लोकसभा चुनाव में अभूतपूर्व सफलता को समझने के लिए यह किताब संकेत तो करती है, लेकिन यह इतना बड़ा विषय है कि इसे साढ़े तीन सौ पृष्ठों में समेटना मुमकिन नहीं है. मोदी सरकार के साल भर पूरे होने के मौक़े पर उनके व्यक्तित्व और कामकाज के तरीके को समझने के लिए लेंस प्राइस ने एक अच्छा आधार दिया है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

एक राजनेता का कवि मन

वरुण गांधी ने एक साक्षात्कार में कहा, मेरा अंतिम लक्ष्य स्थिरता पाना है. राजनीति और कविता पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, मुझे अपने जीवन में कुछ रिक्ति महसूस हुई. लगा कि मुझे और गहराई में जाना चाहिए, इसलिए मैंने कविताओं की ओर रुख किया. राजनीति आपके अंदर खालीपन पैदा कर सकती है.

मोनिशा भटनागर

राजनेता वरुण गांधी का दूसरा कविता संग्रह–स्टिलनेस हाल में ही प्रकाशित हुआ है. वरुण भारतीय जनता पार्टी के महासचिव एवं सांसद हैं. यह कविता संग्रह मशहूर पब्लिशिंग हाउस हार्पर कोलिंस ने प्रकाशित किया. आज से 15 साल पहले वरुण का पहला कविता संग्रह अदरनेस ऑफ सेल्फ शीर्षक से बाजार में आया था और खासा चर्चित रहा था. स्टिलनेस में शामिल कविताएं प्रभावशाली, मार्मिक हैं और उनमें गहराई है. एक राजनीतिज्ञ का काव्यात्मक पक्ष गूढ़ कविताओं के साथ बहुत सरल भाषा में और खूबसूरती के साथ उभर कर सामने आया है. बड़ी कुशलता के साथ लिखी गईं इन गंभीर कविताओं को बेहतरीन फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो पाठक को एक अजीब–सी शांति का एहसास कराता है. इस कविता संग्रह में शामिल कविताएं उदासी से आशा की ओर ले जाती हैं और उसका रास्ता सु–झाती हैं. इस कविता संग्रह में मूल रूप से स्वयं की तलाश की कोशिश नज़र आती है. एक बानगी देखिए:–

Most life dances
Between hope and desperation
As time grows out of

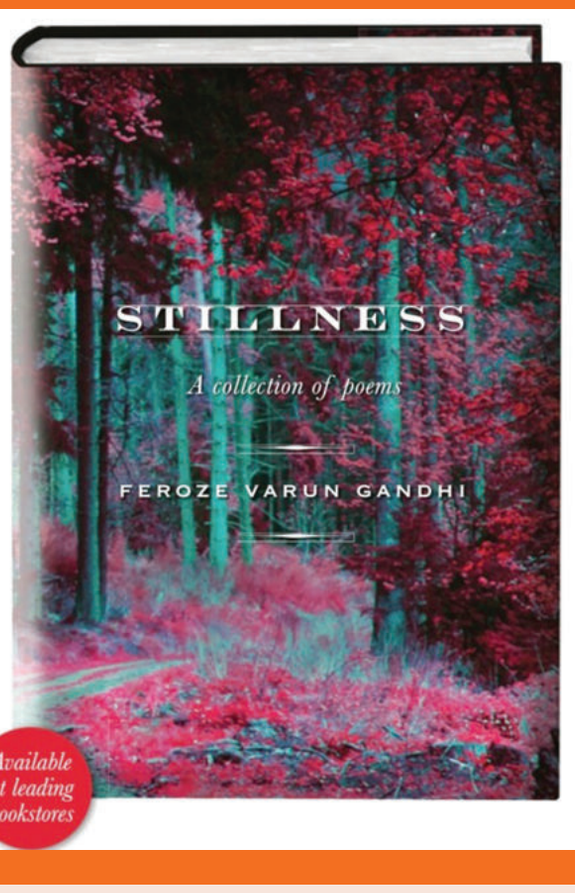

समीक्ष्य कृति: स्टिलनेस (अंग्रेजी)

रचनाकार: फिरोज वरुण गांधी

प्रकाशक : हार्पर कोलिंस

मूल्य : 399 रुपये

The labyrinth of perpetual disso-lution

(अधिकांशत: जीवन आशा और निराशा के बीच चलता रहता है. बिल्कुल वैसे ही, जिस तरह समय लगातार विघटन की भूलभुलैया से गुज़रता रहता है.)

उक्त कविताएं पाठक को उसके अंदर की दुनिया में पहुंचा देती हैं और उसकी आत्मचिंतन और आत्मान्वेषण की भावना को जगा देती हैं. इसलिए स्टिलनेस (स्थिरता) इस कविता संग्रह का सबसे उपयुक्त शीर्षक है. वरुण गांधी ने एक साक्षात्कार में कहा, मेरा अंतिम लक्ष्य स्थिरता पाना है. राजनीति और कविता पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, मुझे अपने जीवन में कुछ रिक्ति महसूस हुई. लगा कि मुझे और गहराई में जाना चाहिए, इसलिए मैंने कविताओं की ओर रुख किया. राजनीति आपके अंदर खालीपन पैदा कर सकती है.

संग्रह की कविताओं में खालीपन बड़े असरदार तरीके से उभर कर सामने आया है, इसलिए ये कविताएं व्यक्तिगत और आत्मीय दिखाई पड़ती हैं. वरुण ने इस कविता संग्रह को अपनी नानी को समर्पित किया है, जिनसे उन्हें बेहद लगाव है, जिसे इन कविताओं का पाठक भी बखूबी महसूस करेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक्सटर्नल मैमोरी के लिए 32 जीबी तक माइक्रोएसडी कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा इसमें डुअल एलईडी फ्लैश के साथ 2.0 मेगापिक्सल रियर और1.3 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मौजूद है.

सुजुकी : दो सुपरबाइक लॉन्च

जीएसएक्स-एस 1000 और जीएसएक्स- एस 1000 एफ में जीएसएक्स-आर 1000 का शानदार इंजन लगा हुआ है. जापान बाइक कंपनी सुजुकी ने 150 सीसी और इससे अधिक क्षमता वाली बाइक के सेगमेंट पर फोकस करना शुरू कर दिया है.

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दो नई मोटरसाइकिल जीएसक्स–एस 1000 और जीएसक्स– एस 1000 एफ लॉन्च की है. दोनों मोटरसाइकिलें शार्प स्टाइलिंग और पावर से लैस हैं. जीएसएक्स–एस उन लोगों के लिए सटीक है जो स्ट्रीट बाइक चाहते हैं. जीएसएक्स–एस 1000 और जीएसएक्स–एस 1000 एफ में जीएसक्स–आर 1000 का शानदार इंजन लगा हुआ है. जापान बाइक कंपनी सुजुकी ने 150 सीसी और इससे अधिक क्षमता वाली बाइक के सेगमेंट पर फोकस करना शुरू कर दिया है. एस1000 और एस1000एफ बाइक की पावर की बात करें तो यह 999सीसी, 4स्ट्रोक, 4 सिलेंडर, लिक्वड कूल्ड, डीओएचसी इंजन के साथ दौड़ती हैं. यह 6 गियरबॉक्स के साथ काम करती हैं. नई बाइक तीन आकर्षक रंग मेटैलिक ट्राइटोन ब्लू, ग्लास स्पार्केल ब्लैक और मेटैलिक मैट फाइब्रॉयन ग्रे में उपलब्ध होंगी. दोनों बाइक की कीमतें 12,25,000 और 12,70,000 रुपये रखी गई हैं. ■

गूगल का जोलो और नेक्सियन लैपटॉप

गूगल इंडिया ने भारत में दो बेहद सस्ते क्रोमबुक लैपटॉप लॉन्च किए हैं. दोनों लैपटॉप गूगल के क्रोम ओएस के लेटेस्ट वर्जन पर काम करते हैं. गूगल ने इन दोंनो क्रोमबुक नोटबुक्स को ओईएम(OEM) जोलो और नेक्सियन के साथ मिलकर तैयार किया है.

दोनों ही लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन लगभग एक जैसे हैं. दोनों ही लैपटॉप (नेक्सियन एयर क्रोमबुक और जोलो क्रोमबुक) में 11.6 इंच का टीएफटी स्क्रीन है. नेक्सियन का रेजोल्यूशन जोलो के मुकाबले थोड़ा अधिक है. नेक्सियन का डिस्प्ले 1366x768 पिक्सल का रेजोल्यूशन देता है जबकि जोलो क्रोमबुक का डिस्प्ले 1366x468 पिक्सल का रेजोल्यूशन देता है. कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें ब्लूटुथ 4.0, एक एचडीएमआई पोर्ट, दो एक्सएमओ यूएसबी 2.0 पोर्ट दिया गया है. वीडियो चैट के लिए 1 मेगापिक्सल वेब कैमरा भी दिया गया है. इसमें 1.8 गीगाहर्ट्ज कॉर्टेक्स 17 रॉकचिप क्वॉडकोर प्रोसेसर और 2 जीबी डीडीआर3 रैम की सुविधा दी गई है. इसमें 4200 एमएएच की बैटरी है. दोनों की कीमत गूगल ने सिर्फ 12,999 रुपये रखी है. ■

स्पाइस ने मी-एफएक्स2 स्मार्टफोन लॉन्च किया

स्पाइस ने स्पाइस मी– एफएक्स1 के बाद अपना दूसरा फायरफॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला स्मार्टफोन मी– एफएक्स2 (MI-FX2) लॉन्च किया है. यह फोन स्पाइस की ई–कॉमर्स साइट पर 2,799 रुपये में उपलब्ध है. मी– एफएक्स2 अपने पिछले स्मार्टफोन मी– एफएक्स1 से बहुत अलग नहीं है. मी– एफएक्स2 फोन में 480 x 320 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला 3.5 इंच का डिसप्ले है. यह फोन 1 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, 256 एमबी रैम और 512 एमबी इंटरनल मैमोरी और डुअल सिम सपोर्ट के साथ है. एक्सटर्नल मैमोरी के लिए 32 जीबी तक माइक्रोएसडी कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा इसमें डुअल एलईडी फ्लैश के साथ 2.0 मेगापिक्सल रियर और1.3 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मौजूद है.

कनेक्टिविटी के मामले में इसमें 3जी, ब्लूटुथ, वाईफाई और जीपीएस की सुविधा दी गई है. फोन की बैटरी1100 एमएएच की है. ■

फुजिफिल्म का एक्स–टी10 कैमरा

फुजिफिल्म ने एक्सं–टी10 नाम का एक नया डिजिटल कैमरा लॉन्च किया है. इस कैमरे के लेंस इंटरचेंजेबल हैं. फुजिफिल्म एक्सप–टी10 से आप 16 मेगापिक्समल की तस्वीरें खीच सकते हैं. इसमें एक्स –ट्रांस इमेज सेंसर भी दिया गया है. इस सेंसर की वजह से ऑटोफोकस मोड में तस्वीरें क्लिक करना काफी बेहतर हो जाता है. कंपनी ने इस कैमरे में ईएक्स आर प्रोसेसर 2 सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है. कैमरे की बैटरी काफी अच्छी क्वालटी की है. एक बार फुल रिजार्च होने के बाद इससे 350 फोटो क्लिक्स किए जा सकते हैं. सामान्या कैमरों के 6400 आईएसओ के मुकाबले इस कैमरे में 51200 लेवल का आईएसओ दिया गया है, जिससे अल्ट्रा हाइ सेंसिटिव तस्वीरें खींची जा सकती हैं. इसमें टेंपर्ड ग्लास का बना एलसीडी मॉनीटर दिया गया है, जिसमें तस्वीरों को क्लिक करने के साथ ही देखा जा सकता है. वीडियो मोड का इस्तेमाल करने पर आप 36 एमबीपीस के एफएचडी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाईफाई सपोर्ट दिया गया है तथा इसे आप स्मार्टफोन एवं टैबलेट से कनेक्ट कर सकते हैं. रिमोर्ट एप्लीकेशन के द्वारा इसका इस्तेमाल आसान हो जाता है. बिना लेंस के इस कैमरे का मूल्य लगभग 51000 रुपये है, जबकि XC 16-50mm F3.5-5.6 lens और XF 18-55mm F2.8-4 लेंस के साथ इसकी कीमत लगभग 57,000 रुपये तथा लगभग 70,000 रुपये रखी गई है. ■

टाटा की जेनएक्स नैनो लॉन्च

टाटा मोटर्स ने जेनएक्स नैनो लॉन्च कर दी है. टाटा की यह कार ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से लेकर ब्लूटुथ कनेक्टिविटी तक तमाम आधुनिक फीचर्स से लैस है. नई टाटा जेनएक्स नैनो में बड़ा कैबिन, थोड़ा अपडेटिड इंजिन और बड़ा फ्यूल टैंक है. साथ ही एक्सटिरियर में थोड़ा बदलाव किया गया. माइलेज की बात करें तो मैनुअल वैरिएंट्स 25.3 किलोमीटर प्रति लीटर और एएमटी वैरिएंट्स 21.9 किलोमीटर प्रति लीटर का है. नए फीचर्स नई नैनो में स्मोक हैडलैंप, अलॉय व्हील, स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट पावर विंडोज, चार स्पीकर वाला एंफीस्ट्रीम सिस्टम है. इसके अलावा फाइव स्पीड गियर बॉक्स, नया इंस्ट्रूमेंट पैनल, टेल गेट और 90–110 लीटर का बूट स्पेस और शानदार एयर कंडीशनर है.

जेनएक्स नैनो एक्सई (मैनुअल)– 1.99 लाख रुपये

जेनएक्स नैनो एक्सएम (मैनुअल)–2.29 लाख रुपये

जेनएक्स नैनो ईजी शिफ्ट एक्सएम (ऑटोमैटिक)–2.69 लाख रुपये

जेनएक्स नैनो ईजी शिफ्ट एक्सट (ऑटोमैटिक)–2.89 लाख रुपये

अजिंक्य रहाणे
टीम इंडिया की अभेद दीवार

छोटे से करियर में क्रिकेट के बड़े-बड़े दिग्गज रहाणे की बल्लेबाजी के मुरीद हो गए हैं. रहाणे ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक केवल 14 टेस्ट और 54 एकदिवसीय मैच खेले हैं. वह टेस्ट मैचों 44.87 की औसत से 1077 रन और 54 एक दिवसीय मैचों में 31 की औसत से 1584 रन बना चुके हैं. जिसमें तीन टेस्ट और दो एकदिवसीय शतक शामिल हैं. उन्हें प्रारंभ से साल 2012 में खेले गए आईपीएल के पांचवें सीजन तक टी-20 फॉर्मेट का कुशल खिलाड़ी नहीं समझा जाता था, लेकिन उन्होंने पांचवें सीजन में इस मिथक को तोड़ते हुए राजस्थान रॉयल्स के लिए 16 मैचों में 560 रन बनाए.

नवीन चौहान

अजिंक्य का मतलब होता है अभेद. यानि जिसे भेदा न जा सके. 26 साल के अजिंक्य रहाणे अपने नाम के अनुरूप एक अभेद बल्लेबाज के रूप में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं. द वॉल के नाम से विख्यात पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ को अपना आदर्श मानने वाले रहाणे भारतीय टीम के ऐसे बल्लेबाज हैं, जो किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी करने में सक्षम हैं. वह कभी ओपनिंग करते हैं, तो कभी मिडल ऑर्डर में खेलते हैं. इसी वजह से कई बार उनकी तुलना वीवीएस लक्ष्मण से भी की जाती है.

आईपीएल के आठवें सीजन में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए अजिंक्य रहाणे ने 13 लीग मैचों में लगभग 50 की औसत से 498 रन बनाये. इस शानदार प्रदर्शन की वजह से राजस्थान रॉयल्स के कोच राहुल द्रविड़ भी रहाणे की बल्लेबाज़ी के कायल हो गए. द्रविड ने रहाणे की तारीफ करते हुए कहा कि वह पिछले एक साल से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने विदेशों में टेस्ट श्रृंखलाओं में भी लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. रहाणे के मुरीदों में केवल उनके साथ खेल चुके राहुल द्रविड़ ही नहीं हैं, बल्कि पूर्व भारतीय कप्तान अजीत वाडेकर भी इस सूची में शामिल हैं, उन्होंने पिछले महीने सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन के मौके पर मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में अजिंक्य की तारीफ करते हुए कहा था कि ऐसे तो आईपीएल में तकनीकी रूप से सही बल्ललेबाज देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसे में मेरे जेहन में एक ही बल्लेबाज का नाम आता है और वह है अजिंक्य रहाणे का. उसे पता है कि टी-20 क्रिकेट कैसे खेलना है साथ ही उसका डिफेंस भी बहुत अच्छा है. वाडेकर ने कहा कि प्रतिभाशाली होने के साथ-साथ उसका मिजाज भी सकारात्मक है. उसका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर बहुत लंबा होगा. वहीं द्रविड़ को लगता है कि वर्तमान समय के बल्लेबाज उनकी पीढ़ी के बल्लेबाजों से बेहतर है. ये बल्लेबाज अनुभव के साथ बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उनके पास हमसे बेहतर हासिल करने की क्षमता है. रहाणे उसी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन भी रहाणे को तकनीकी दृष्टि से सबसे उम्दा भारतीय बल्लेबाज़ मानते हैं. वॉन का कहना है कि टीम इंडिया में शानदार बल्लेबाज़ों की कमी नहीं है, लेकिन इनमें अजिंक्य की तकनीक सबसे बेहतरीन है. वह दुनिया के किसी भी बेहतरीन स्पिन या तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण का सामना कर सकता है.

छोटे से करियर में क्रिकेट के बड़े-बड़े दिग्गज उनकी बल्लेबाजी के मुरीद हो गए हैं. रहाणे ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में अबतक केवल 14 टेस्ट और 54 एकदिवसीय मैच खेले हैं. वह टेस्ट मैचों 44.87 की औसत से 1077 रन और 54 एक दिवसीय मैचों में 31 की औसत से 1584 रन बना चुके हैं. जिसमें तीन टेस्ट और दो एकदिवसीय शतक शामिल हैं. उन्हें प्रारंभ से साल 2012 में खेले गए आईपीएल के पांचवें सीजन तक टी-20 फॉर्मेट के लिए का एक कुशल खिलाड़ी नहीं समझा जाता था, लेकिन उन्होंने पांचवें सीजन में इस मिथक को तोड़ते हुए राजस्थान रॉयल्स के लिए 16 मैचों में 560 रन बनाए. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और राजस्थान रॉयल्स की रीढ़ की हड्डी बन गए. इससे पहले वह मुंबई इंडियंस में शामिल थे, वहां उन्हें खेलने के बहुत कम मौके मिले. आईपीएल-5 में 98 और नाबाद 103 रन की दो पारियों की बदौलत राष्ट्रीय टीम में शामिल होने के लिए बीसीसीआई के दरवाजे पर धमाकेदार दस्तक दी. जो काम घरेलू क्रिकेट में उनकी शानदार बल्लेबाजी नहीं कर सकी, वह काम आईपीएल के दो मैचों ने कर दिखाया.

रहाणे ने अपने रणजी करियर की शुरूआत साल 2007-08 में की थी. इसके बाद 2008-09 में अपने दूसरे ही रणजी सत्र में 1089 रन बनाकर सबको प्रभावित किया था और वे मुंबई की 38वीं रणजी खिताबी जीत के सूत्रधार रहे थे. रहाणे ने अगले सत्र में 809 रन बनाए और मुंबई ने अपने खिताब का बचाव किया. रहाणे ने अपने पहले पांच रणजी सत्र में तीन बार एक हजार से ज्यादा रन बनाये. इसके बाद उनकी टेस्ट टीम में शामिल होने की संभावनायें बढ़ गईं थीं. साल 2011 में ईरानी टॉफी के एक मैच में राजस्थान के खिलाफ उन्होंने 152 रनों की पारी खेली थी, इसके बाद उन्हें चोटिल शिखर धवन की जगह टेस्ट टीम में शामिल किया गया था. 2011 के विश्वकप के 30 संभावितों में रहाणे को शामिल किया गया था लेकिन वह अंतिम 15 में जगह नहीं बना सके थे. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में खेले गए इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट में उन्होंने दो शतक जड़े जिसकी बदौलत उन्हें 2011 के इंग्लैंड दौरे के लिए एकदिवसीय टीम में जगह दी गई थी. इसी दौरे में 3 सितंबर 2011 को चेस्टर ली स्ट्रीट में इंग्लैंड के खिलाफ रहाणे ने अपना वनडे पदार्पण किया था. इसी दौरे में 31 अगस्त 2011 उन्होंने अपना अंतरराष्ट्रीय टी-20 पदार्पण मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ ही किया था.

सफलता का नशा रहाणे के सिर चढ़कर नहीं बोला है, यह एक शुभ संकेत है. जिस सादगी विनम्रता का परिचय रहाणे मैदान के बाहर देते हैं उनका व्यवहार ऐसा ही मैदान पर भी होता है. उनकी आक्रामकता बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण में दिखाई देती है. कुल मिलाकर रहाणे एक लंबी रेस के घोड़े हैं, जो कि लंबे समय तक देश का प्रतिनिधित्व करेंगे. वह क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. उनमें क्षमता है कि वह आवश्यक्ता के अनुरूप बल्लेबाजी के तरीके में बदलाव कर सकते हैं.

साल 2011-12 में ऑस्ट्रेलिया दौरे में जब भारतीय टीम एक के बाद एक टेस्ट मैचों में पिट रही थी तो रहाणे ड्रेसिंग रूम में बेबसी से यह नज़ारा देख रहे थे, लेकिन चारों टेस्टों में उन्हें एक भी चांस नहीं दिया गया. इसके बाद हुई त्रिकोणीय सिरीज और एशिया कप में रहाणे को वनडे टीम में जगह नहीं दी गई थी. उन्हें बिना कोई मौका दिए टीम से बाहर कर दिया गया. लेकिन रहाणे ने आईपीएल-5 में अपने शानदार प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को याद दिलाया है कि वे उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं. इसके बाद रहाणे टीम इंडिया के साथ नियमित रूप से जुड़ गये.

अजिंक्य रहाणे की पैदाइश महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अश्विन केडी में हुई. जब अजिंक्य महज सात साल के थे तब उनके पिता उन्हें एक छोटे से क्रिकेट कोचिंग कैंप में ले गए जो डोम्बिविली में था. वहां मैटिंग विकेट पर खेल सिखाया जाता था. इस छोटे से कैंप में रहाणे को क्रिकेट का ककहरा इसलिए सीखना पड़ा क्योंकि उनके परिवार की माली हालत अच्छी नहीं थी. अजिंक्य कैंप तक अपनी मां के साथ जाते थे. उन्हें और उनकी मां को कैंप तक पहुंचने के लिए रोजाना 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था. रहाणे भले ही आज क्रिकेट में नाम कमा रहे हैं, लेकिन बचपन के दिनों में वे कई अन्य खेल भी बेहतर खेलते थे. उनके पिता ने अपने एक दोस्त की सलाह पर अजिंक्य को मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए डोंबिवली स्थित युनिटी कराटे सेंटर भेजने का फैसला किया और वहीं से रहाणे कराटे में ब्लैक बेल्ट हुए. तकरीबन 17 साल के होने के बाद रहाणे ने पूर्व भारतीय टेस्ट बल्लेबाज प्रवीण आमरे से कोचिंग प्राप्त की. लेकिन उससे पहले अरविंद कदम नाम के एक व्यक्ति ने रहाणे परिवार की बहुत मदद की थी. रहाणे के पिता का कहना है कि अरविंद ने हमारे परिवार की बहुत सहायता की. उन्होंने हमसे बिना कोई पैसे लिए रहाणे को अपनी क्रिकेट अकादमी में अभ्यास करने का मौका दिया. अजिंक्य रहाणे के पास आज भले ही पैसे की कमी न हो, लेकिन एक ऐसा वक्त भी था, जब उनका परिवार क्रिकेट से जुड़े उनके खर्चों को उठाने की स्थिति में नहीं था. उनके पिता के पास अजिंक्य के लिए ज्यादा वक्त नहीं था. वह बताते हैं कि मेरा काम सिर्फ परिवार के लिए धन कमाना था, एक छोटी सरकारी नौकरी में परिवार बड़ी मुश्किल से चल पाता था. हमारे लिए रहाणे के क्रिकेट के खर्चे का वहन करना मुश्किल था. कई बार मैंने इस ओर गंभीरता से सोचा, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे अजिंक्य को खेलने से रोकने से मना कर दिया. उन्हें शायद उसी समय से मां को अपने बेटे की प्रतिभा पर यकीन था.

विश्वकप से ठीक पहले हुए ऑस्ट्रेलिया दौरे में अजिंक्य रहाणे ने चार टेस्ट मैचों में 399 रन बनाये जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल थे. सीरीज में रन बनाने के मामले में रहाणे केवल विराट कोहली(692) और मुरली विजय (482) से पीछे थे. उनकी बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय मिडिल ऑर्डर मजबूत रहा और टीम इंडिया दो टेस्ट मैच बराबरी पर समाप्त करने में कामयाब रही. एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट मैच में कोहली और रहाणे के बीच चौथे विकेट के लिए 101 रनों साझेदारी हुई. इस दौरान अजिंक्य ने 62 रन बनाए, लेकिन दूसरी पारी में वह अपना खाता भी नहीं खोल सके. पहला टेस्ट टीम इंडिया महज 48 रनों के अंतर से हार गई. ब्रिस्बेन में खेले गए दूसरे टेस्ट की पहली पारी में रहाणे ने मुरली विजय के साथ चौथे विकेट के लिए 124 रन जोड़े, इसके बाद रोहित शर्मा के साथ पांचवे विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी की. इस दौरान रहाणे ने 81 रन बनाये. तीसरे टेस्ट में रहाणे ने 147 और 48 रनों की पारी खेली और मैच ड्रा कराने में अहम योगदान दिया. इसी दौरान उन्होंने टेस्ट करियर में हजार रन भी पूरे किए. रहाणे से पहले भारत के दो दर्जन बल्लेबाजों ने एक हजार रन के आंकड़े को पार किया है, लेकिन करियर का 13 वें टेस्ट मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल करने वाले रहाणे को उन सभी से अलग दिखाई दिए क्योंकि टेस्ट करियर में खेले कुल 14 टेस्ट मैचों में से उन्होंने केवल एक टेस्ट मैच भारत में खेला है. दिल्ली में साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में उन्होंने मजह शून्य और सात रन बनाये थे. उनके अधिकांश टेस्ट रन विदेशी धरती पर ही बने हैं. पिछले एक साल में रहाणे ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए तीन टेस्ट शतक लगाए, उनके नाम आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ शतक हैं, वहीं डरबन में पिछले साल जुलाई में रहाणे ने 96 रनों की पारी खेली थी, जो किसी शतक से कम नहीं थी. रहाणे ने मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी में 147, फरवरी 2014 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंग्टन में 118 और लॉर्डस में जुलाई 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ 103 रनों की पारी खेली थी. रहाणे मैच दर मैच परिपक्व खिलाड़ी के तौर पर उभरे हैं और विदेशी पिचों पर खुद को साबित किया है. विश्वकप में भी रहाणे ने सधी हुई बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को संतुलित किया था और मध्यम क्रम को संभाला था. विश्वकप में रहाणे ने 9 मैचों की 7 पारियों में 34.66 की औसत से 208 रन बनाये. रहाणे की 60 गेंदों पर 79 रनों की तेजतर्रार पारी विश्वकप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ निर्णायक साबित हुई थी.

सफलता का नशा रहाणे के सिर चढ़कर नहीं बोला है, यह एक शुभ संकेत है. जिस सादगी विनम्रता का परिचय रहाणे मैदान के बाहर देते हैं उनका व्यवहार ऐसा ही मैदान पर भी होता है. उनकी आक्रामकता बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण में दिखाई देती है. कुल मिलाकर रहाणे एक लंबी रेस के घोड़े हैं, जो कि लंबे समय तक देश का प्रतिनिधित्व करेंगे. वह क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. उनमें क्षमता है कि वह आवश्यक्ता के अनुरूप बल्लेबाजी के तरीके में बदलाव कर सकते हैं. देश हो या विदेश हर जगह वह अपनी काबीलियत साबित कर चुके हैं और टीम में अपनी जगह भी सुनिश्चित कर चुके हैं, ऐसे में लोगों को उनमें भविष्य का कप्तान भी दिखाई देने लगा है. महेंद्र सिंह धोनी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से उपकप्तान का पद खाली पड़ा है, हालांकि इस पद के लिए उम्मीदवार अश्विन और रहाणे दोनों हैं, सीनियरिटी के आधार पर अश्विन को उपकप्तान बनाया जा सकता है, यदि चयनकर्ता और बोर्ड भविष्य के लिए कप्तान तैयार करने के बारे में सोचते हैं तो निश्चित तौर पर रहाणे ही उप-कप्तान बनेंगे.■

navinonline2003@chauthiduniya.com

ऐश्वर्या मेरे लिए खोज हैं इरफान खान

ऐश्वर्या मीडिया द्वारा बनायी गयी छवि से बहुत अलग और अच्छी हैं. वह मानवीयता और जमीन से जुड़ी, ख्याल रखने वाली और अपने भीतर के अभिनेता को खंगालने वाली हैं.

ऐश्वर्या राय बच्चन को इरफान खान ने मानवीयता और जमीन से जुड़ा हुआ बताया और उन्होंने कहा कि वह मीडिया द्वारा बनायी गयी छवि से कहीं अलग और बेहतर हैं. 48 वर्षीय इरफान 41 वर्षीय ऐश्वर्या के साथ संजय गुप्ता निर्देशित एक्शन थ्रिलर फिल्म जज्बा में साथ काम कर रहे हैं. इरफान ने बताया ऐश मेरे लिए खोज हैं. मैं उनके बारे में जो कुछ भी जानता था, मीडिया के माध्यम से था. वह मीडिया द्वारा बनायी गयी छवि से बहुत अलग और अच्छी हैं. वह मानवीयता और जमीन से जुड़ी, ख्याल रखने वाली और अपने भीतर के अभिनेता को खंगालने वाली हैं. इरफान ने कहा कि किसी भी निर्देशक के लिए उन्हें अपनी फिल्म में लेने और कोई चुनौतीपूर्ण भूमिका देना बहुत अच्छा रहेगा, जहां वह महसूस करती हैं कि मुझे कुछ नया करने दें, मुझे एक किरदार निभाने दें. वह ऐसा करने को तैयार हैं. वह इसके लिए बहुत उत्साहित हैं. मैंने उनके बारे में यही खोजा है. उनके साथ काम करना बहुत अच्छा रहा. इरफान का कहना है कि उनके जज्बे में काम करने की एक कारण ऐश्वर्या भी थीं.■

रणवीर को शादी के लिए दीपिका की ना

दीपिका सही तरीके से सही व्यक्ति के साथ शादी के बंधन में बंधना चाहती हैं.

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी की प्लानिंग की खबरें पिछले कई दिनों से आ रही हैं, लेकिन दीपिका ने स्पष्ट किया है कि वे अभी शादी के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं.रणवीर सिंह की दीपिका के पिता से मुलाकात के बाद दोनों की शादी की अटकलें तेज हो गई थीं. दीपिका ने कहा है कि उन्हें शादी करने की कोई जल्दबाजी नहीं है. यह जीवन में एक बार होता है. वे सही तरीके से सही व्यक्ति के साथ शादी के बंधन में बंधना चाहती हैं. दीपिका को यह भी डर है कि कहीं सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो जल्दबाजी को दोष जाएगा. रणवीर शादी के लिए जलदी में हैं, लेकिन दीपिका अभी शादी नहीं करना चाहती हैं. चाहते हैं, लेकिन दीपिका अभी शादी नहीं करना चाहती हैं.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

शादी मजबूरी नहीं होना चाहिए : कंगना

बिना इच्छा के शादी करने से भविष्य बर्बाद हो जाता है. उन्होंने कहा, शादी करनी है या नहीं, यह एक व्यक्ति का निजी फैसला है.

अभिनेत्री कंगना रनौत का अभी शादी का कोई इरादा नहीं है. वह कहती हैं कि शादी करना एक व्यक्ति की अपनी पसंद है और किसी सामाजिक दबाव में आकर शादी नहीं करनी चाहिए. 28 वर्षीय अभिनेत्री कंगना का मानना है कि बिना इच्छा के शादी करने से भविष्य बर्बाद हो जाता है. उन्होंने कहा, शादी करनी है या नहीं, यह एक व्यक्ति का निजी फैसला है. मेरा मानना है कि यह एक मजबूरी नहीं बल्कि एक पसंद होनी चाहिए. मेरे ख्याल से हमें लड़कों व लड़कियों पर उनके भविष्य, शादी या किसी अन्य चीज के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए. उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से ये चीजें समाज की वजह से नहीं थोपी जानी चाहिए, क्योंकि इससे दोनों लोगों का भविष्य खराब होता है.■

सनी लियोन पर एफआईआर

यह मामला ठाणे की एक महिला द्वारा दर्ज कराया गया है. उन्हें विभिन्न वेबसाइट पर अपलोड सनी लियोन के अश्लील फोटो और वीडियो पर आपत्ति थी.

पॉर्न स्टार से बॉलीवुड अभिनेत्री बनीं सनी लियोन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. यह उनके इंटरनेट पर मौजूद अश्लील वीडियो और फोटो को लेकर मामला दर्ज किया गया है. सनी लियोन के खिलाफ ठाणे के डोंबीवली पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज किया गया है. बताया जाता है कि सनी लियोन के खिलाफ यह मामला ठाणे की एक महिला द्वारा दर्ज कराया गया है. उन्हें विभिन्न वेबसाइट पर अपलोड सनी लियोन के अश्लील फोटो और वीडियो पर आपत्ति थी. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद सनी लियोन के खिलाफ 292, 292ए, 294 और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. गौरतलब है कि सनी लियोन भारतीय मूल की हैं और कनाडा की बेहद लोकप्रिय पॉर्न स्टार रह चुकी हैं. रियलिटी शो बिग बॉस के जरिए उनकी भारतीय मनोरंजन जगत में एंट्री हुई और उसके बाद वे कई बॉलीवुड फिल्मों में लीड रोल में नजर आ चुकी हैं. वो गूगल इंडिया में सर्वाधिक सर्च की जाने वाली शख्सियत हैं. ■

यूलिया हो सकती हैं सलमान की दुल्हन

सलमान खान अपनी जिंदगी के एक बड़े फैसले के बारे में सोच सकते हैं. सलमान खुद ही कह चुके हैं कि सबकुछ ठीकठाक रहा तो वे इस साल के अंत तक शादी कर लेंगे. यह सवाल है कि आखिर सलमान शादी किससे करेंगे. वो हैं यूलिया वांतुर रोमानिया की टीवी प्रेजेंटर और एक्ट्रेस. कुछ दिन पहले उन्हें मुंबई में सलमान और उनके परिवार के साथ भी देखा गया. 24 जुलाई, 1980, लासी रोमानिया में जन्मी यूलिया ने लॉ ग्रेजुएट हैं. उन्होंने 19 साल की उम्र में यूरोपा नोवा चैनल में नौकरी कर करियर की शुरूआत की और फिर 15 साल टीवी प्रेजेंटर रहीं. 2006 में वे राजधानी बुखारेस्ट आ गईं, जहां उन्होंने मॉर्निंग न्यूज शो और डांस शो टीवी पर प्रेजेंट किए. वह वॉलीबॉल, टेनिस और बास्केटबॉल की अच्छी खिलाड़ी रही हैं. 2010 में डबलिन में सलमान फिल्म बॉडीगार्ड की शूटिंग कर रहे थे. उसी दौरान यूलिया का परिचय उसके ब्वॉयफ्रेंड मारियस मोगा ने कराया. मोगा पश्चिमी–मध्य यूरोप के नामचीन प्रोड्यूसर, कंपोजर और सिंगर हैं. दोनों 2011 में भारत भी आए. लेकिन जल्द ही उनका ब्रेकअप हो गया. इसके बाद यूलिया डिप्रेशन में चली गईं. बताया गया कि तनाव से बाहर आने के लिए उन्हें मनोचिकित्सक की मदद भी लेनी पड़ी. लेकिन इसी दौरान में सलमान दोबारा परिदृश्य में आए. दो साल पहले एक विदेश दौरे के दौरान सलमान यूलिया से मिले. उसके बाद से लगातार दोनों संपर्क में रहे और एक–दूसरे के करीब आ गए. परिवार में शामिल यूलिया पिछले दिनों भारत आईं और डेढ़ महीने तक सलमान और उनके परिवार के साथ रहीं. इस दौरान उन्होंने मोगा से उनके अलगाव में मदद की. यूलिया अब ज्यादातर दुबई में रहती हैं.■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार झारखंड

01 जून –07 जून 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

हर सीट अपनी क्यों लगती है

सरोज सिंह

स्थानीय निकाय की 24 और बिहार विधानसभा की 243 सीटों को लेकर इन दिनों हर दल में घनघोर माथापच्ची जारी है. खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा बिहार में सिंतबर–अक्टूबर में चुनाव कराये जाने के संकेत देने के बाद से तो यह सिलसिला और भी जोर पकड़ रहा है. फिलहाल भाजपा को छोड़कर हर दल सीटों के बंटवारे के मसले को जल्द से जल्द निपटा लेने के लिए जतन कर रहा है. पर यह मसला ऐसा है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है. ऐसा नहीं है कि भाजपा में इस पर मंथन नहीं हो रहा है लेकिन विधानसभा की सीटों को लेकर वह इतनी जल्दबाजी में नहीं है जितना की दूसरे दल. इसकी वजह यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही भाजपा लगातार विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में लगी रही, पर दूसरे दलों ने देर से इसकी शुरूआत की. इसलिए दूसरे सारे दल चाहते हैं कि विधान परिषद के लिए सीटों के फैसले के तुंरत बाद विधानसभा सीटों का भी बंटवारा हो जाता, ताकि केंद्रीकृत तरीके से चुनाव की तैयारी की जा सके. प्रस्तावित जनता परिवार में यह प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. जानकार सूत्र बताते हैं कि जदयू और राजद सिद्धांत: कांग्रेस और एनसीपी के साथ तालमेल कर चुनाव लड़ने के लिए लगभग तैयार हैं. लेकिन सीटों के पेंच ने बहुत सारी अड़चनों को सामने कर दिया. यदि विधानसभा चुनाव सामने नहीं होते तो विधान परिषद की सीटों के बंटवारे में इतनी परेशानी नहीं आती. दरअसल एक दूसरे से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर ये दल आगे के चुनाव के लिए अपना दावा मजबूत बनाने का खेल खेल रहे हैं. दूसरी बात यह है कि हर दल को ऐसा लग रहा कि हमारे सहयोगी दल बेवजह हम पर दबाव बना रहे हैं. उनका अपना गणित कहता है कि जितनी सीटों पर वह लड़ेंगे उन पर उनका जीतना तय है इसलिए हर सीट उन्हें अपने लिए महफूज़ लगती है.

भाजपा के सहयोगी दल भी इसी मनोदशा के शिकार है. लोजपा और रालोसपा की चाहत है कि विधान परिषद की ज्यादा से ज्यादा सीटें भाजपा से ली जाये ताकि जब भी विधानसभा सीटों के लिए मंथन हो तो उसमें ज्यादा सीटों पर दावा किया जा सके और ली जा सके. यही वजह है कि लोजपा ने छह और रालोसपा ने चार सीटों पर अपना दावा ठोंका है. लोजपा पिछले चुनाव में तीन सीटों पर विजयी हुई थी, पर दुर्भाग्यवश उसके सभी एमएलसी ने पाला बदल लिया. इसलिए लोजपा ने उन तीन सीटों के अलावा जमुई सहित तीन अन्य सीटों पर अपना दावा जताया है. लेकिन भाजपा के सूत्र कहते हैं कि दावा जताना अलग बात है और चुनाव लड़ना अलग बात है. जबकि सच्चाई यह है कि स्थानीय चुनाव के लिए अच्छे और मजबूत उम्मीदवार की खोज बहुत मुश्किल काम है. यहां तक कि भाजपा को भी इस संकट से गुजरना पड़ रहा है. भाजपा इस बात का पूरा ख्याल रख रही है कि कहीं बदनाम छवि वाले उम्मीदवार को उनके सहयोगी दल टिकट न दे दें. खासकर रणजीत डॉन जैसे प्रत्याशियों को लेकर सहयोगी दलों को सर्तक रहना होगा. क्योंकि, यदि भाजपा ऐसे उम्मीदवारों के साथ खड़ी नजर आती है तो इसका गलत संदेश विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है. भाजपा ने अपने सहयोगी दलों को यह संदेश भी दे दिया है. अब यह सहयोगी दलों पर है कि वे भाजपा की इस सलाह पर कितना अमल करते हैं. जानकार सूत्र बताते हैं कि भाजपा ने लोजपा के लिए तीन और रालोसपा के लिए एक सीट छोड़ने का फैसला किया है. बाकी बची बीस सीटों पर वह अपना दावा कर रही है. भाजपा को भी यह लगता है कि सभी 24 सीटों पर वह जीतने की स्थिति में हैं बस सहयोगी दलों का सम्मान रखने के लिए वह चार सीटों का त्याग कर रही है. भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि यह सही है कि भाजपा चार सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ने का मन बना रही है लेकिन यदि दबाव बढ़ा तो वह एक या दो अन्य सीटों पर भी अपना दावा वापस ले सकती है क्योंकि भाजपा के लिए हर हाल में प्राथमिकता विधानसभा के चुनाव हैं. इस समय भाजपा अपने सहयोगी दलों को यह कहकर भी चुप करा सकती है कि परिषद के चुनावों में आपको ज्यादा सीटें दी गई थीं इसलिए विधानसभा के चुनाव में आपको त्याग करना होगा. भाजपा चाहती है कि जीतनराम मांझी के खेमे को भी इस मोर्चे में शामिल किया जाए ताकि विधानसभा चुनाव से पहले तालमेल पर एक टेस्ट हो जाए. लेकिन मांझी खेमा अभी अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं है. भाजपा की तरह उसकी प्राथमिकता भी विधानसभा का चुनाव है. लेकिन हाल ही में जीतनराम मांझी ने जो एक दो बयान लालू प्रसाद को लेकर दिए हैं उससे भाजपा में नाराजगी है. जीतन राम मांझी ने लालू को भी स्वीकार करने की बात कही थी. भाजपा ने मांझी खेमे को यह संदेश भिजवाया है कि इस तरह की बयानवाजी से मांझी को परहेज करना चाहिए. भाजपा जिसे जंगलराज का सुप्रीमो मानती है उसे लेकर इस तरह की बयानवाजी सही नहीं है.

सूत्रों का कहना है कि यह सही है कि भाजपा चार सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ने का मन बना रही है, लेकिन यदि दबाव बढ़ा तो वह एक या दो अन्य सीटों पर भी अपना दावा वापस ले सकती है, क्योंकि भाजपा के लिए हर हाल में प्राथमिकता विधानसभा के चुनाव हैं. इस समय भाजपा अपने सहयोगी दलों को यह कहकर भी चुप करा सकती है कि परिषद के चुनावों में आपको ज्यादा सीटें दी गई थीं इसलिए विधानसभा के चुनाव में आपको त्याग करना होगा. भाजपा चाहती है कि जीतनराम मांझी के खेमे को भी इस मोर्चे में शामिल किया जाए ताकि विधानसभा चुनाव से पहले तालमेल पर एक टेस्ट हो जाए. लेकिन मांझी खेमा अभी अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं है. भाजपा की तरह उसकी प्राथमिकता भी विधानसभा का चुनाव है. लेकिन हाल ही में जीतनराम मांझी ने जो एक दो बयान लालू प्रसाद को लेकर दिए हैं उससे भाजपा में नाराजगी है.

लोजपा के सूत्र बताते हैं कि दागी को लेकर भाजपा जो परिभाषा थोप रही है. वह ठीक नहीं है. दागी छवि के लोग हर पार्टी में हैं और भाजपा इससे अलग नहीं है. इसलिए इस तरह की चर्चा करना कि लोजपा दागी छवि वाले लोगों को टिकट देना चाहती है यह ठीक नहीं है. जीत की संभावनाओं को देखते हुए यह हर पार्टी का विशेषाधिकार है कि वह अपना सिंबल किसे देती है. हालांकि लोजपा के सूत्र यह मानते हैं कि सीटों के बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं आयेगी और भाजपा सहयोगी दलों के साथ सम्मानजक समझौता करेगी. जहां तक जनता परिवार का सवाल है तो पहले राजद और जदयू ने आपस में बातचीत की और यह सहमति बनाई कि चार सीटें दूसरे दलों के लिए छोड़ी जाए. यानि की दस दस सीटों पर राजद और जदयू के प्रत्याशी लड़ेंगे और चार सीटें कांग्रेस और एनसीपी के लिए छोड़ी जायेंगी. इन चार सीटों में से तीन कांग्रेस और एक एनसीपी के लिए छोड़ी गई है. अगर किसी वजह से बात नहीं बनी तो बारह–बारह सीटों पर राजद और जदयू के प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में उतरेंगे. लेकिन जानकार सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार हरसंभव कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव व्यापक तालमेल के साथ लड़ा जाए और इसमें कांग्रेस को भी शामिल किया जाए. नीतीश कुमार मानते हैं कि अगर परिषद के चुनाव में वह बेहतर तालमेल बनाने में सफल रहे तो इसका लाभ विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा और उस समय तालमेल करने में कोई परेशानी नहीं होगी. क्योंकि तालमेल में इस समय सबसे ज्यादा परेशानी सीटिंग–गेटिंग वाले फार्मूले के कारण हो रही है. अगर इस फार्मूले को माना गया तो 118 जीती हुई सीटों पर जदयू का स्वाभाविक दावा बनता है. राजद की दिक्कत यह है कि अगर वह इस फार्मूले को मानती है तो कई जिलों में उसका एक भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में दिखाई नहीं पड़ेगा और इसका बुरा असर पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ेगा. लालू प्रसाद को किसी भी हालत में यह स्थिति स्वीकार नहीं है. राजद के सूत्र बताते हैं कि जिस जिले से पार्टी का एक भी प्रत्याशी नहीं होगा, उस जिले के कार्यकर्ताओं को हम कैसे समझायेंगे. इसलिए राजद चाहता है कि सेटिंग गेटिंग वाले फार्मूले को छोड़कर कोई जीतने वाला फार्मूला बनाया जाए ताकि जमीनी स्तर पर किसी तरह की भ्रम की स्थिति पैदा न हो. राजद का साफतौर पर मानना है कि लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को आधार बनाया जाय और उसी के आधार पर तालमेल की बात की जाए. इस आधार पर राजद का तकरीबन 145 सीटों पर दावा बनता है. इसमें उन्नीस बीस की गुंजाइश हो सकती है. राजद की यह एप्रोच नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा टॉस्क है. नीतीश कुमार आज की तारीख में भी चाहते हैं कि महाविलय ही हो तो ज्यादा अच्छा है. महाविलय से सीटों के बंटवारे का झमेला ही खत्म हो जाएगा क्योंकि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि सीटों का बंटवारा कोई आसान काम नहीं है. इसलिए कहीं बात बिगड़ न जाए, इसलिए महाविलय पर ही फोकस किया जाए. हफ्ता, दस–दिन में बिहार की राजनीति के बहुत सारे सवालों से परदा उठना है इसलिए हम भी इंतजार करते हैं और आप भी दिल थाम के इंतजार कीजिए.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

हीरो मोटोकार्प में फाइनेंस की सुविधा

ग्राहकों के लिए टू-व्हीलर खरीदना अब और आसान करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी टू व्हीलर निर्माता हीरो मोटोकॉप लिमिटेड ने बिहार में हीरो फिनकॉर्प का शुभारंभ किया है. इस मौके पर अजय शास्त्री बुधी नेशनल हेड, हीरो फिनकॉर्प और आशुतोष वर्मा, जोनल हेड सहित पटना के तीन डीलर उपस्थित थे. श्री वर्मा ने बताया कि आसान फाइनेंस विकल्प की उपलब्धता हमेशा से ही बिहार में एक समस्या रही है. पिछले साल हीरो ने सभी गाड़ियों में से मात्र 5 प्रतिशत गाड़ियां फाइनेंस सुविधा से बिक्री की है. हीरो फिनकॉर्प के बिहार में अपना काम शुरू करने के साथ ही ग्राहकों को हीरो टू-व्हीलर खरीदते समय आसान फाइनेंस सुविधा का अनुभव प्राप्त होगा. उन्होंने बताया कि यह सुविधा पहली मई से पटना, मुजफ्फरपुर में प्रारंभ हुई है. अन्य शहरों में जल्द ही शुरू की जायेगी. हीरो फिनकॉर्प के माध्यम से गाड़ियों के ऑन रोड मूल्य 90 प्रतिशत तक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है. *–रजनीकान्त*

दिव्य शांति स्थल का रूप लेगा प्रतिमा स्थल

सूक्ष्म-साधना-पद्धति इस्सयोग के प्रवर्तक तथा अंतरराष्ट्रीय इस्सयोग समाज के संस्थापक महात्मा सुशील कुमार का प्रतिमा-स्थल, दिव्य-शांति-स्थल के रूप में विकसित होगा. यहां मौन बैठने वालों को अपूर्व शांति और आनंद की प्राप्ति होगी. यह बात स्थानीय गोला रोड स्थित इस्सयोग के नव-निर्मित उत्सवालय एमएसएमबी भवन में, ब्रह्मलीन महात्मा सुशील कुमार तथा माताजी की प्रतिमाओं की स्थापना के प्रथम वार्षिकोत्सव पर आयोजित समारोह में अपने आशीर्वचन में ब्रह्मनिष्ठ सद्‌गुरु माता मां विजया जी ने कही. मौन रहकर वन के भी संगीत सुने जा सकते हैं. आज ही के दिन महात्माजी तथा माताजी के लौकिक सायुज्य हुआ था. समारोह का आरंभ संस्था के संयुक्त सचिव और छोटे भय्या संदीप कुमार गुप्ता ने दीप-प्रज्वलित कर तथा अभियंता उमेश कुमार ने प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर किया. इसके पश्चात सद्‌गुरुदेव के आं वान की साधना की गयी और वीरेन्द्र राय तथा प्रभाकर के संगीत-निर्देशन में सामूहिक गायन किया गया. साधक प्रभात चन्द्र झा ने वेद-ऋचाओं से मंत्रोचार सहित स्वस्ति-वाचन किया. इस अवसर पर इस्सयोगियों की ओर से श्रद्धांजलि स्वरूप, संस्था के सचिव कुमार सहाय वर्मा, संदीप गुप्ता(मुंबई), डॉ अनिल सुलभ (मुख्यालय,पटना), नीतिन साहू (लखनऊ), डॉ गीता जेना (उड़ीसा) तथा दीना नाथ शास्त्री (दिल्ली) ने अपने उद्‌गार व्यक्त किये. समारोह में संयुक्त सचिव सरोज गुटगुटिया, लक्ष्मी प्रसाद साहू, शिवम झा, अनंत कुमार साहू, श्रीप्रकाश सिंह, रामचन्द्र चौधर, किरण प्रसाद, राज कुमार प्रसाद, राजीव कुमार सिंह समेत बड़ी संख्या में संस्था के अधिकारी व स्वयं सेवक सक्रिय थे.■ *–भारती*

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE
1 YEAR GUARANTY
Contact : 9386595926, 9334115955

बेकाबू क्रोध
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
Carbo-XT
A Colic
Siliplex
Oflogyl-OZ
Acoba
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma
रजनीकान्त पाण्डेय

भोजपुर-बक्सर विधान परिषद् चुनाव

धनबल तथा बाहुबल से तय होगा परिणाम

जय मंगल पांडेय

विधान सभा चुनाव से पहले ही भोजपुर सह बक्सर जिले में त्रिस्तरीय विधान परिषद् के चुनाव को लेकर मोल भाव के साथ जोड़तोड़ की राजनीति से वोटरों के भाव भी बढ़ गये हैं. वोट के सौदागरों द्वारा सियासत के बाजार में बोली लगाए जाने के कारण जनप्रतिनिधियों के भाव शेयर बाजार की तरह बढ़ रहे हैं. कल तक उपेक्षित पड़े पंचायत प्रतिनिधि भी धन कुबेरों की सक्रियता देख अपनी हैसियत का एहसास कराते हुए राजनीति के शेयर बाजार की नब्ज टटोलते मोल भाव के मूड़ में आश्वासन भी दे रहे हैं. चुनावी मौसम में रोज बदलते मिजाज और वोटों की खुलेआम सौदेबाजी को लेकर लोकतंत्र के स्याह होते सिस्टम पर आम व खास के बीच चर्चा भी शुरू हो गयी है. वोट के नाम पर लोकतंत्र के बाजारवाद में मतदान की ईमानदारी तथा निष्पक्षता के दावे कोरे सिद्धांत बन कर रह गये हैं. वास्तविकता यही है कि धन कुबेर पद पाने की महत्वाकांक्षा में राजनीति को बाजार में तब्दील कर पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं. जाहिर है कि सियासत में इसी फॉर्मूले पर राजनीतिक सक्रियता तेज हुई और इसी हथियार के कारगर होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है. लगातार बढ़ती पूछ के कारण ही वर्षों से गुमनाम जन-प्रतिनिधियों के चेहरे पर अचानक रौनक आ गयी है.

भोजपुर-बक्सर जिलों में त्रिस्तरीय विधान परिषदों का चुनाव इस साल जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है. दोनों जिलों में लगभग 6250 मतदाता हैं. भोजपुर में 288 तथा बक्सर में 142 पंचायतों के मुखिया, वार्ड सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य सहित जिला पार्षद एवं निकाय प्रतिनिधि भी शामिल हैं. नगर निकायों में आरा नगर निगम, बक्सर नगर परिषद् एवं डुमराव, पीरो, कोइलवर, जगदीशपुर, पीरो, बिहियां तथा शाहपुर के प्रतिनिधि भी मतदाता हैं. इस क्षेत्र से हुलास पांडेय विधान पॉर्षद हैं. वर्ष 2009 के चुनाव में पांडेय जदयू के समर्थन से राजद समर्थक लालदास राय को

हराकर चुनाव जीते थे. हुलास पांडेय को 2497 तथा लालदास राय को 1783 मत मिले थे. तब राधा चरण सेठ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे थे. लेकिन बाद में कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दिया और उन्हें 711 वोट प्राप्त हुए थे. विशेश्वर ओझा को भाजपा का समर्थन दिया था. पिछले चुनाव में भाजपा तथा जदयू में गठबंधन होने के बाद भी दोनों दलों के समर्थकों ने ताल ठोकी थी और इसमें जदयू समर्थक हुलास पांडेय को ही सफलता मिली थी. इस बार के चुनाव में बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच दो पुराने खिलाड़ियों के अलावा कुछ नये चेहरे भी मैदान में होंगे. अपने कार्यों के दावे के साथ विधान पॉर्षद हुलास पांडेय ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है.

पिछली बार की तरह इस बार भी जदयू के समर्थन के सहारे वे अपनी दावेदारी जता रहे हैं. इसी प्रकार पिछली बार कांग्रेस के समर्थन से चुनाव में उतरे राधा चरण सेठ इस बार राजद का समर्थन मिलने का दावा कर चुनावी तैयारियां शुरू कर चुके हैं. बक्सर जिले के चक्की में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की आमसभा में मंच साझा कर राधा शरण सेठ ने समर्थकों को यह संदेश देने का प्रयास किया कि पार्टी सुप्रीमो का समर्थन उन्हें प्राप्त है. पिछली बार चुनाव हारने वाले राजद के लालदास राय इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे.

विधान परिषद के नगर निकाय चुनाव से जुड़ा अहम सवाल यह है कि राजद तथा जदयू के जनता परिवार में विलय के बाद भी राजद तथा जदयू समर्थक प्रत्याशी खुलेआम ताल ठोक रहे हैं. ऐसी स्थिति में आपसी एकता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है. क्योंकि दोनों की जोरदार सक्रियता और जोड़-तोड़ से आपसी टकराव तय है. इस टकराव का असर विधान सभा चुनाव को भी प्रभावित कर सकता है. इन दोनों के अलावा बिल्डर अनिल कुमार भी मैदान में मुस्तैदी से ताल ठोक रहे हैं. फिलहाल भाजपा के समर्थन का दावा करने वाला कोई प्रत्याशी अभी मैदान में नहीं है. पिछले साल भाजपा के समर्थन से चुनाव लड़ने वाले विशेश्वर ओझा के इस बार चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है. अभी कुछ और नये चेहरों का मैदान में उतरना बाकी है.

वैसे इस चुनाव में बड़े नेताओं की न सभा होती है और न कोई मुद्दे होते हैं. इस चुनाव में धनबल और बाहुबल की आजमाइश होती है. हर पद के अलग-अलग रेट है. इसी फॉर्मूले के तहत वोट मैनेज किये जा रहे हैं. हद तो यह है कि एक ही वोटर कई जगहों पर बिक रहे हैं. इसके लिए गलत सर्टिफिकेट का भी प्रयोग किया जा रहा है. कुल मिलाकर भोजपुर सह बक्सर का नगर निकाय का चुनाव परिणाम धनबल तथा बाहुबल से ही तय होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

अन्य ख़बरें

बैठक आयोजित

भाजपा के वार्डों की कार्यशाला नगर अध्यक्ष जितेन्द्र यादव की अध्यक्षता में हुई. इस अवसर पर उपस्थित भाजपा कार्यकर्त्ताओं को संबोधित करते हुये भाजपा जिलाध्यक्ष रामानुज चौधरी ने कहा कि हम लोगों ने जितने भी सदस्य बनाये हैं, उन सबों के घर पर कुशल क्षेम पूछने पुन: जायेगें. समाज को संदेश पहुंचाने के लिए सभी कार्यकर्त्ता एकजुट हो जाएं. वरीय नेता राजकुमार विद्यार्थी ने कहा कि भाजपा ने सबके साथ निष्ठापूर्वक कार्य किया. कार्यशाला में अश्विनी चौधरी, विजय चन्द्रवंशी, रविराज, विजय यादव, सुशील अकेला सहित सैकड़ों कार्यकर्त्ता मौजूद थे. उधर भारतीय जनता पार्टी नगर ईकाई द्वारा बाबूलाल शौर्य के आवास पर बैठक आयोजित की गयी. वहीं नगर अध्यक्ष जितेन्द्र यादव ने कहा कि पार्टी सदर विधान सभा का चुनाव लड़ेगी. वहीं नगर उपाध्यक्ष व संपर्क प्रमुख अश्विनी कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार में आगामी चुनाव को देखते हुए बिहार में जुलाई तक सदस्यता अभियान चलेगा और 25 मई से 31 जुलाई तक महा जनसंपर्क अभियान चलाया जायेगा. जिसमें घर-घर जाकर टोल फ्री नम्बर 18001034444 पर सत्यापन किया जायेगा. वहीं नगर उपाध्यक्ष विजय राम चन्द्रवंशी ने कहा कि आने वाले चुनाव में बिहार में भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनायेगी.

वेतनमान की घोषणा के लिए लड़ाई जारी

सन्हौली दुर्गास्थान के कला मंच पर नियोजित शिक्षक संघ की जिला एवं प्रखंड कमेटी की संयुक्त बैठक आयोजित की गयी. बैठक में शिक्षकों का कहना था कि दो तीन छोटे-छोटे संगठन ने आंदोलन वापस ले लिया है तो ऐसी स्थिति में हमें भी विचार करना चाहिए. इस पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला सचिव मनीष कुमार सिंह ने कहा कि यह हड़ताल दूसरे संगठनों के सहयोग से नहीं आयोजित की गई थी. हड़ताल में जिन संगठनों ने साथ दिया वो बधाई के पात्र हैं. नियोजित शिक्षक संघ वेतनमान घोषणा होने तक लड़ाई जारी रखेगा. सरकार द्वारा बनायी गयी कमेटी अभी तक स्पष्ट नहीं कर रही है कि वेतनमान और सेवाशर्तों का स्वरूप क्या होगा. प्रदेश की बैठक के बाद प्रखंड स्तर पर शिक्षकों एवं अभिभावकों के जागरूक करने के लिए छोटे-छोटे कार्यक्रम चलाये जायेगें. बैठक में श्यामनंदन, पंकज राय, आलोक रंजन, दयानंद रजक, आदित्य कुशवाहा, राकेश कुमार, नीलेश कुमार, अमलेन्द्र कुमार पासवान, सुमित कुमार, अनिल पोद्दार, पारस, मनीष, अनुज, अंगद, सुधा कुमारी आदि दर्जनों शिक्षक उपस्थित थे.

सफाई कर्मियो की हड़ताल खत्म

नगर परिषद के सभा भवन में नगर सभापति मनोहर कुमार यादव की अध्यक्षता में नगर परिषद के हड़ताली सफाई कर्मियों की मांग पर विचार किया गया. इस अवसर पर नगर के उप सभापति राजकुमार फोगला, नगर कार्यपालक पदाधिकारी सुधीर कुमार उपस्थित थे. बैठक में सफाई कर्मचारियों के अध्यक्ष राजीव कुमार ने पांच सूत्रीय मांगों को रखते हुए कहा कि नगर सफाई कर्मी काफी मेहनत करते हैं. उनकी मांग सशक्त स्थाई समिति नगर परिषद द्वारा तय की गई मानदेय वृद्धि को अप्रैल 2015 से ही लागू किया जाये. नियोजन नियमावली-2015 में पारित निर्णय के आलोक में नियोजन अवधि 60 वर्ष तक के लिए अप्रैल 2015 से ही लागू की जाए. नियोजन नियमावली-2015 में पारित निर्णय के आलोक में सभी सफाई कर्मी, अनुसेवक, कार्यालय कर्मियों, वार्ड जमादार, ड्राईवरों का भविष्य निधि खाता खुलवाकर अप्रैल 2015 से भविष्य निधि का लाभ दिया जाये. हेल्थ कार्ड अविलंब उपलब्ध कराया जाये, सफाई कर्मियों के लिए रविवारीय अवकाश प्रदान करने के लिए बनाये गये रोस्टर के अनुसार प्रत्येक सफाई कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किया जाये आदि मांगों पर विचार विमर्श किया गया. पांचों मांगो पर सहमति के बाद हड़ताल खत्म कराई गई.

किराया भवन मालिक के एकाउंट में

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सुपरवाईजरों की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सियाराम सिंह ने भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के संबंध में जानकारी ली. साथ ही कहा कि जो आंगनबाड़ी केंद्र किराये के मकानों में चल रहे हैं उस मकान मालिक के एकाउंट लें और उसके एकाइंट में ही पैसा जमा करें. उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्र के संचालन के संबंध में भी विस्तृत जानकारी हासिल की. इस अवसर पर सदर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी किरण कुमारी, परबत्ता बाल विकास परियोजना पदाधिकारी वर्तिका सुमन सहित कई सुपरवाईजर बैठक में मौजूद थे.

नियोजन मेले का आयोजन

श्रम संसाधन विभाग द्वारा जेएनकेटी स्टेडियम खगड़िया में नियोजन सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया. मेले का उद्घाटन जिला नियोजन पदाधिकारी नूर अरशद ने किया. इस अवसर पर नूर अरशद ने बताया कि यह मेला बेरोजगार युवकों के लिए काफी फायदेमंद है. उन्होंने कहा कि इस मेले के आयोजन के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि बेरोजगार युवकों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जायें और उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया जाय. उन्होंने कहा कि इस मेले में तकरीबन 17 कंपनियों ने स्टॉल लगाये हैं. अरशद ने कहा कि हमलोग चाहते हैं कि बेरोजगार युवकों के स्किल डेवलपमेंट के साथ-साथ रोजगार के अवसर मुहैया कराये जायें. इस अवसर पर विभिन्न स्टॉलो पर युवाओं में काफी उत्साह दिखाई दिया. एक बेरोजगार युवक ने कहा कि शिविर में अधिकांश गार्ड के लिए ही स्टॉल लगाया गया है. उन्होंने कहा कि काफी संख्या में ऐसे बेरोजगार युवक हैं जो गार्ड की नौकरी करने से कतराते हैं.

सजाया सब्जी हाट

नगर पंचायत गोगरी द्वारा कई मुश्किलों का सामना करने व काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार सब्जी व अन्य फुटकर विक्रेताओं को मुख्य बाजार से अलग राम-जानकी ठाकुरबाड़ी परिसर में शिफ्ट करा दिया गया. जमालपुर बाजार के भीड़भाड़ वाली मुख्य सड़कों पर रेहड़ी-पट्टी व ठेला लगाकर सब्जी एवं फल बेचने वालों को एक ही जगह पर बाजार लगाकर अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए जमीन उपलब्ध कराकर नगर प्रशासन ने निश्चित ही आम लोगों के लिए एक सराहनीय प्रयास किया है, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है. लेकिन क्या जमालपुर बाजार के मुख्य चौराहों पर पिछले कई वर्षों से अपना व्यवसाय कर रहे दुकानदार शिफ्ट कराये गए ये दुकानदार नई जगह पर अपनी दुकानदारी पहले की तरह कर पायेगें. क्या ऐसे दुकानदारों के व्यवसाय पर अलग जगह चले जाने का असर नहीं पड़ेगा. इस तरह के कई सवाल व चिंता कुछ दुकानदारों को सता रही है. मौके पर प्रतिनियुक्त किये गये दंडाधिकारी किसलय कृष्ण की मौजूदगी में कनीय अभियंता सत्येन्द्र सिंह व सुनील कुमार सब्जी विक्रेताओं को उनके स्थान पर चिन्हित कर उसकी पड़ताल कर रहे थे. स्थानीय लोग भी सज रहे सब्जी दुकानदारों को देखने के लिये काफी संख्या में नजर आ रहे थे.

मतदाता सूची में दो बार नाम, क़ानूनी अपराध

जिलाधिकारी राजीव रौशन ने कहा कि मतदाता सूची में एक व्यक्ति का दो जगह नाम होना क़ानूनी अपराध है. यदि किन्हीं मतदाताओं का दो जगह नाम है तो वह एक जगह से नाम कटवा लें. यदि इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत की जाती है और इसपर कानूनी प्रक्रिया चलती है तो उसे छ: माह से दो वर्ष की सजा हो सकती है. उक्त बातें जिलाधिकारी ने समाहरणालय सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहीं. उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है. उन्होंने जागरूकता कार्यक्रम में मीडियाकर्मियों से भी सहयोग मांगा. बताया सत्यापन 16 मई से 22 मई तक, विशेष अभियान दिवस 24 मई से 7 जून तक, दावे एवं आपत्ति का निष्पादन 15 जुलाई तथा निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन 31 जुलाई को किया जायेगा. इस अवसर उपनिर्वाचन पदाधिकारी विपिन कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह मौजूद थे. वही राजनैतिक दलों में से जदयू के बबलू मंडल, राजद से प्रमोद यादव, रालोसपा से अमित कुमार मंटू माकपा से सुरेन्द्र महतो और संजय कुमार उपस्थित थे.■

feedback@chauthiduniya.com

नारी के सम्मान से ही होगा जन-कल्याण !

नारी उत्पीड़न के मामले भले ही कम हुए हों लेकिन खत्म नहीं हो पाए हैं. हालांकि महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए कई क़ानून बने, लेकिन महिलाओं के साथ होनी वाली घरेलू हिंसा के मामले थमे नहीं या यूं कहिए कि पुरुषों ने उनसे बच निकलने के रास्ते तलाश लिए. महिलाओं की घरेलू स्थिति तो अभी भी चिंताजनक है आज भी लाखों की संख्या में महिलाएं घरेलू हिंसा झेल रही हैं. जिनमें पढ़ी-लिखी व कामकाजी महिलाएं भी शामिल हैं. आज भी महिलाओं को कोई भी फैसला लेने से पहले घर के पुरुष से अनुमति लेनी पड़ती है. सैकड़ों लड़कियां दहेज की बलि चढ़ाई जा रही हैं.

राधिका

नारी का सम्मान सदा होना चाहिए. संस्कृत में एक श्लोक है- यस्य पूज्यंते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता:, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं. लेकिन फिर भी नारी को केवल भोग की वस्तु समझकर आदमी अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है जो एक बड़ी चिंता का विषय है. इस पुरूष प्रधान समाज में पुरुषवर्ग आदिकाल से नारियों के उत्सर्ग में बाधा उत्पन्न करते आये हैं. वे हमेशा खुद में खूबियां ढूंढते रहते हैं और समाज में खुद को साबित करने के लिए अपने बल का प्रयोग करते हैं. नारियों के उत्थान में जाने क्यों उन्हें खुद का पतन नजर आता है. आश्चर्य तो तब होता है जब पुरुष अपनी संर्कीण मानसिकता का दोषी एक नारी को ठहराते हैं. गलतियां खुद करते हैं और कारण नारी को बताते हैं.

सदियों तक नारी को उसकी पहचान से दूर रखा गया है, उसे पुरूषों की गुलाम बनाकर घर की चार दीवारी में कैद रखा गया है. लेकिन आज की नारी ने उस चार-दीवारी को तोड़कर बाहर निकलने का साहस दिखाया है. उसने हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. लेकिन फिर भी उस पर होने वाले अत्याचार का सिलसिला अभी भी थमा नहीं हैं. नारी उत्पीड़न के मामले भले कम हुए हों लेकिन खत्म नहीं हो पाए हैं. हालांकि महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए कई कानून बने, लेकिन महिलाओं के साथ होनी वाली घरेलू हिंसा के मामले थमे नहीं या यूं कहिए कि पुरुषों ने उनसे बच निकलने के रास्ते तलाश लिए.

महिलाओं की घरेलू स्थिति तो अभी भी चिंताजनक है आज भी लाखों की संख्या में महिलाएं घरेलू हिंसा झेल रही हैं. जिनमें पढ़ी-लिखी व कामकाजी महिलाएं भी शामिल हैं. आज भी महिलाओं को कोई भी फैसला लेने से पहले घर के पुरुष से अनुमति लेनी पड़ती है. सैकड़ों लड़कियां दहेज की बलि चढ़ाई जा रही हैं. न सिर्फ निम्न वर्ग की बल्कि उच्च वर्ग की कामकाजी महिलाएं भी दहेज के श्राप से मुक्त नहीं हैं. जब इस बारे में हमने महिला हेल्पलाईन की प्रोजेक्ट मैनेजर/ प्रोटेक्शन ऑफिसर प्रमिला कुमारी से बात की तो उन्होंने बताया कि जितने भी मामले हमारे पास रजिस्टर होते हैं उनमें से 60 प्रतिशत घरेलू हिंसा के होते हैं. घरेलू हिंसा में सबसे ज्यादा दहेज प्रताड़ना फिर फैमिली डिस्प्यूट्स के केसेज आते हैं. इनका ये भी कहना है कि जो कानून है अगर हम सिर्फ उस पर चलकर हल ढूंढने की कोशिश करें तो हल मिलना जैसे असंभव हो जाता है. इसलिए कई मामलों में हमें मानवता को आगे रखते हुए लीक से हटकर लोगों की मदद करनी पड़ती है.

इस बारे में सोशल एक्टिविस्ट अनामिका सिंह का कहना है कि हर दिन लड़कियों के खिलाफ जुर्म बढ़ते हीं जा रहे हैं. चाहे रेप हो या ईव टीजिंग या फिर घरेलू हिंसा, दिन ब दिन इनका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है. लड़कियां कहीं भी चली जायें वो हर तरह से सुरक्षित नहीं हो सकती हैं. और इसका सबसे बड़ा कारण है ढीली कानून व्यवस्था. इसके अलावा लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है, जब तक लोगों का मानसिक विकास नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं घटती हीं रहेंगी. जब तक लड़कियों को सिर्फ भोग की वस्तु समझा जाएगा तब तक लड़कियों के खिलाफ बढ़ रहे जुर्म को खत्म नहीं किया जा सकता है. विकास के कई पायदान चढ़ने के बाद भी हमारा समाज लड़का और लड़की के बीच के फर्क को छोड़ नहीं पाया है. कन्या भ्रूण हत्या बदस्तूर जारी है. तमाम प्रतिबंधों के बावजूद बेटे की चाहत में बेटियों की बलि देने का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है, जब बच्चियां गर्भ में हीं सुरक्षित नहीं हैं तो बाहर क्या होगीं?

यदि यही हाल रहा तो एक समय ऐसा भी आ सकता है, जब लड़की का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा. महिलाओं के प्रति आपराधिक घटनाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ोत्तरी ही नजर आ रही है. वर्ष 1995 से लेकर अब तक महिलाओं के साथ आपराधिक मामलों में 55 फीसदी इजाफा हुआ है. घर, स्कूल, चिकित्सालय, हर जगह महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं. अबोध बच्चियों के साथ आए दिन हो रहे दुष्कर्म की घटनाएं भी समाज को कलंकित कर रही है. विडंबना यह है कि समाज के कई प्रावधानों के बावजूद सरकार या प्रशासन दुष्कर्म की घटनाओं पर रोक नहीं लगा पा रहा है. सरकारी आंकड़ों की माने तो देश के महानगरों में एक लाख से ज्यादा महिलाएं किसी न किसी मजबूरी के कारण अपना जिस्म बेचती हैं. मुख्य रूप से इसका कारण गरीबी है.

अगर हम चाहते है कि स्त्री के व्यक्तित्व का विकास बेहतर तरीके से हो, तथा वह पढ़-लिखकर आत्म निर्भर बने, तो इसके लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा. जब तक नारी को भोग की वस्तु समझा जाएगा तब तक नारी की स्थिति में फर्क आना नामुमकिन है. लड़की के जन्म के साथ ही उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार शुरू कर दिया जाता है. यह भेदभाव घर में ही नहीं बल्कि कार्य स्थल पर भी दिखता है. हालांकि जब-जब नारी को स्वयं को सिद्ध करने का मौका मिला तब-तब उसने खुद को साबित कर के दिखाया है. इसलिए महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है. उन्हें स्वतंत्रता देनी होगी.

महिलाओं के विकास के संदर्भ में जहां तक क़ानून की बात है तो क़ागजों में तो कई क़ानून बने हैं. लेकिन उनका उचित लाभ महिलाओं को कभी नहीं मिल पाया. आज क़ानून से ज्यादा सामाजिक समर्थन और जागरूकता की जरूरत है. महिलाएं सबसे अधिक घरेलु हिंसा का शिकार बन रहीं हैं, जिसका मुख्य कारण दहेज उत्पीड़न है, जो कि आगे चलकर दहेज हत्या का रूप ले लेता है. मिट्टी का तेल छिड़ककर जिन्दा जलाई गई, जलाकर मारी गई बहुओं की पीड़ा शायद समाज और कानून के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि लड़कियों को उनकी ताकत और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी ही नहीं है. इसके अलावा पढ़ी-लिखी और शिक्षित लड़कियां भी इस तरह के उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं. अब सवाल यह उठता है कि शिक्षित होते हुए भी वह घरेलू हिंसा का शिकार कैसे हो जाती है? इसका जवाब है हाई-प्रोफाइल सोसाइटी का हिस्सा होना, जो कि उन्हें सबकुछ सहने के लिए मजबूर कर देता है. बदनामी के डर से वह अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं. लेकिन कुछ नहीं कहतीं, क्योंकि इससे उनका नाम और ओहदा दोनों प्रभावित हो सकता है. आज बड़े-बड़े घरों का यही हाल है. बाहर से देखने में सब कुछ सुहाना लगता है लेकिन जब अंदर से देखा जाए तो सब कुछ खोखला नजर आता है.■

feedback@chauthiduniya.com

महिलाओं की सुरक्षा केलिए हेल्पलाईन (बिहार)- 18003456247/ 0612-2320047/2214318

महिला सुरक्षा के लिए बनाये गए ऐप्प

विथु- यानी एमरजेंसी एप, इस एप को डाउनलोड करने केबाद आप जब भी इसकेलिए अपना पॉवर बटन दो बार दो मिनट केलिए क्लिक करेंगें, तो हर दो मिनट बाद की आपकी लोकेशन आपके फीडेड ग्रुप्स तक पहुंच जाती है.

गो सुरक्षित एप- इस एप से आपके कांटेक्ट पर्सन को जानकारी मिलती है कि आप सुरक्षित हैं या नहीं. इसके जरिए ऐप अपने मोबाईल से अपने कांटेक्ट केलोगों के मोबाईल पर आई एम सेफ का मैसेज भेज सकती हैं.

सेंटिनल एप- यह जीपीएस के अकॉर्डिंग चलता है. इसमें आपके दोस्तों और आपके अपनों को एसएमएस, ई-मेल, वॉयस कॉल, कॉल तक मिल सकती है. यह इमरजेंसी में भी काम करता है.

निर्भया एप- इस एप पर अप्लाई करने से एक सिक्योरिटी टीम आपके सपोर्ट के लिए आपको मिल जाती है. इसमें रजिस्ट्रेशन करने से आपके साथ यदि किसी तरह की अनहोनी होने की आशंका हो तो आप इस पर क्लिक करें. आपकी मदद के लिए उस एसओएस के सहारे डेंजर का अलार्म बज जाएगा, जिसे सुनकर कोई अवश्य ही आपकी मदद को आएगा.

सेफ ब्रिज एप- यह एप सुरक्षा के लिहाज से काफी फायदेमंद साबित होता है. इस एप में आई एम नॉट सेफ टेक्स्ट मी मैसेज होता है. यह मैसेज उसी क्षेत्र के पुलिस, एनजीओ, हॉस्पीटल के पास जाता है. इससे आप तुरंत सुरक्षित महसूस करेंगे.

फाईट बैक- फाइट बैक एक ग्लोबल सॉल्युशन सेफ्टी एप है. इस में आप जिस भी सिचुएशन में हो उससे जुड़े सुरक्षा के उपाय व संबंधित जानकारी ले सकती हैं.

वन टच एसओएस- यह बिल्कुल निर्भया एप से मिलता जुलता है. इसमें एक अलार्म भी होता है.

आई फॉलो- आई फॉलो में आप अपने तीन पर्सनल मेंबर्स के नंबर सेव कर सकती हैं. इसे इंस्टॉल करने के बाद आप इस आई फॉलो में जिनकेनंबर डालती हैं वो लोग आपको फॉलो कर सकते हैं.

वुमेंस सेक्योरिटी- विमेन सिक्योरिटी एप में आप जिस भी लोकेशन में होती हैं. आपको तुरंत उस एरिया की पुलिस, एनजीओ, महिला पुलिस या फिर हॉस्पीटल या किसी भी तरह की सिक्योरिटी मिल सकती हैं .

अन्य ख़बरें

समीक्षा बैठक आयोजित

नवपदस्थापित प्रमंडलीय आयुक्त लीयान कुंगा ने बेलदौर तथा चौथम प्रखंड का दौरा कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अधिकारियो को कई निर्देश दिये. चौथम में अधिकारियों के साथ बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश कुमार रजक एवं अंचलाधिकारी से आपदा को लेकर तैयारी एवं फसल क्षतिपूर्ति के संबंध में जानकारी ली. वही बेलदौर प्रखंड में अधिकारियों के साथ बैठक कर आयुक्त ने फसल क्षतिपूर्त्ति एवं भूकंप से क्षति के संबंध में जानकारी हासिल की. वही आपदा के संबंध में तैयारी की समीक्षा की. आयुक्त ने आपदा को लेकर विशेष तैयारी करने का निर्देश दिया. इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि मौजूद थे.

अतिक्रमण हटाओ अभियान

शहर के रेलवे के जमीन अवैध तरीके से घर बनाकर रह रहे लोगों के विरूद्ध रेल प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. इस अभियान में पूर्वी केबिन से लेकर बखरी बस स्टैंड तक अवैध रूप से दुकान और घर बनाकर रह रहे लोगों को हटा दिया गया. हालांकि अतिक्रमण के हटाने से आमलोगों में खुशी ही थी. लेकिन जो लोग यहां पर रहकर व्यवसाय कर जीवनयापन कर रहे थे. उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. *–मनेन्द्र कुमार*

सुविधाओं से परिपूर्ण अपार्टमेंट

आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण अम्बापाली अपार्टमेंट निर्माण के लिए बाबानगरी में विधिविधान से भूमिपूजन किया गया. अम्बापाली अपार्टमेंट में लोगों के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है. कैंपस के अंदर जिम, क्लब, स्वीमिंग पूल, बच्चों के लिए खेल का मैदान जैसी सुविधायें दी जाएंगी. आधुनिक बेड रूम, किचन और टॉयलेट के साथ निर्माण किया जा रहा है. उक्त जानकारी अम्बापाली ग्रुप के निदेशक पुरुषोत्तम चौबे ने देते हुए बताया कि एक, दो तथा तीन कमरों वाले फ्लैट्स का निर्माण कराया जा रहा है जिसकी कीमत भी सामान्य रखी गई है. श्री चौबे ने बताया कि शहर के हृदयस्थल पर निर्माण हो रहे अम्बापाली अपार्टमेंट बाबानगरी का गौरव होगा. ■ *– चौथी दुनिया ब्यूरो*

एक नज़र

खेलों की नर्सरी है बेगूसराय

बेगूसराय को खेलों की नर्सरी कहा जाता है. कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ताइक्वान्डो, कराटे, तैराकी, कुश्ती, खो-खो, क्रिकेट, हैंडबॉल, शतरंज आदि खेलों में बेगूसराय जिले के खिलाड़ियों की खास पहचान है. राज्य एवं राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व यहां के खिलाड़ी करते आ रहे हैं. जिले में खेलकूद की स्थिति और अधिक सुदृढ़ करने, खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, सभी खेलों का आयोजन करने के उद्देश्य से बेगूसराय जिला खेल महासंघ का गठन किया गया है. नवगठित महासंघ की बैठक अध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता एवं मुख्य संरक्षक उपेन्द्र प्रसाद सिंह के पर्यवेक्षण में रिफाइनरी टाउनशीप के कल्याण केन्द्र में आयोजित की गई. बैठक में महासंघ के सभी खेलकूद संघो के अध्यक्ष/सचिव/प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में महासंघ का बाइलॉज तैयार करने के लिए जिला फुटबॉल संघ के सचिव सुरेश चौहान के संयोजकत्व में छ: सदस्यीय उपसमिति का गठन किया गया. समीर शेखर, उमाकांत राय, श्यामनन्दन सिंह पन्नालाल, मृत्युंजय कुमार, वीरेश एवं रंधीर कुमार उप-समिति के सदस्य होंगे. बायलॉज स्वीकृत होने के पश्चात इसके अनुरूप महासंघ के पदाधिकारियों का चुनाव होगा. *–सुरेश चौहान*

जलसा-ए-दस्तारबंदी का आयोजन

संग्रामपुर प्रखंड के दरियापुर में संचालित मदरसा इस्लामिया आजाद के तत्वाधान में जलसा-ए-दस्तारबंदी का आयोजन किया गया.जलसा की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल वहाब नदवी ने की, जबकि संचालन अल्कीर खां अलिग ने किया. जलसे को संबोधित करते हुए मौलाना असलम नदवी चतुर्वेदी ने कहा कि मजहब-ए-इस्लाम हमेशा इंसानियत का संदेश देता है और एक मनुष्य को दुसरे मनुष्य से जोड़ता है.मौके पर मौजूद इस्लाम चतुर्वेदी ने वेद में लिखे गए श्लोकों पर विस्तार से चर्चा की. कार्यक्रम में सीवान से आये नातखां नईम अहमद सीवानी ने अपनी सुरीली आवाज में नात-ए-शरीफ पढ़ी और लोगों को खुब झुमाया.अतिथियों का स्वागत ओजैर सलीम ने किया जबकि मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. इमिन्नतुल्लाह, मोतिहारी के उपमुख्य पार्षद मोहिबुल हक खां,जावेद अख्तर खां,जिला पार्षद यहिया खां उर्फ नारंगी खां,मुखिया रामध्यान दुबे,पूर्व मुखिया नागा तिवारी,जमील अख्तर,अवध किशोर तिवारी,बृजकिशोर तिवारी,मदरसा के सचिव परवेज अख्तर खां, उपसचिव अशफाक अली खां,अध्यक्ष साबिर खां,व हेड मौलवी मो जिलानी समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे.

भूकंप पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी

नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए पराम्बा शक्ति पीठ सेवा ट्रस्ट द्वारा जीवनोपयोगी आवश्यक सामग्री की खेप भेजी गई. भाड़े के ट्रक से मंदिर परिसर से भेजी गयी सामग्री में चूड़ा और चावल पांच क्विंटल, दो क्विंटल नमक, दाल और गुड़ एक-एक क्विंटल, बिस्किट सोलह कार्टून, ग्यारह सौ लीटर पानी बोतल, साड़ी उन्नीस, कम्बल नौ, तिरपाल सैंतीस तथा दस हजार रुपये मूल्य की दवा थी. प्राकृतिक आपदा में मिसाल बने योगी राज चंचल बाबा ने ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. उक्त मौके पर उन्होंने बताया कि हिन्दू राष्ट्र रहे नेपाल की कमर टूट गई है. नेपाल को फिर से पटरी पर लौटने में एवं पहले जैसा होने में ज्यादा समय लगेगा. भारत का सहयोग हमेशा से नेपाल को मिला है, लेकिन वर्तमान त्रासदी के समय सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक क्षेत्र के लोगों को बढ़-चढ़ कर नेपाल की मदद के लिए आगे आना चाहिए. चंचल बाबा ने बताया कि सेवा कार्यकारी रहेगा. ट्रस्ट मंदिर से भेजा गया सामान रक्सौल राहत कैम्प में पहुंचाने में अनिल सिंह एवं मंटू सिंह का योगदान रहा. कैम्प से तमाम सामान लदा ट्रक सीधे अत्यधिक प्रभावित काठमांडू क्षेत्र के लिए गया और धार्मिक संस्था द्वारा भेजी गई सामग्री जरूरतमंदों के बीच वितरित की जाएगी.

ईसाई बच्चों का दृढ़ीकरण संस्कार

स्थानीय बरियारपुर स्थित संत फ्रांसिस असीसी चर्च में पच्चीस ईसाई बच्चों को दृढ़ीकरण संस्कार किया गया. मोतिहारी से बीस, छपवा के दो तथा रक्सौल के तीन इसाई बच्चों को यह संस्कार किया गया. इस दौरान बेतिया धर्मप्रांत के प्रशासक लौरेंस पास्कल ने दृढ़ीकरण संस्कार के बारे में लोगों को बताया. उन्होंने कहा कि दृढ़ीकरण संस्कार में हमे पवित्र आत्मा द्वारा सात दान प्राप्त होते हैं जिसमें ज्ञान, बुद्धि, परामर्श, धैर्य, श्रद्धा, समझदारी तथा ईश्वर का भय आदि. इस अवसर पर चर्च के पल्ली पुरोहित फादर जेरम कापूचिन ने कहा कि आज हम सब ईसामसीह के स्वर्गारोहन का पर्व मना रहे हैं. स्वर्गारोहन के साथ ही ईसा मसीह का अपने शिष्यों के साथ धरती का जीवन समाप्त हो जाता है. स्वर्गारोहन का पर्व पुनर्जीवित ईसा मसीह के साक्षी बनने के लिए हमें प्रेरित करता है. ईश्वर का कार्य करने में हमेशा ईश्वर की सहायता मिलती है. *–इन्तेजारूल हक*

जलवा डांस शो के लिए ऑडीशन

जलवा डांस शो तथा वॉयस ऑफ मगध सीजन-3 के लिए आईएमए हॉल गया में ऑडीशन का आयोजन किया गया. इसमें दो सौ प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. इस ऑडिशन में जून में होने वाले सेमीफाइनल व फाइनल प्रतियोगिता के लिए 40 प्रतिभागियों का चयन किया गया. चयनित प्रतिभागियों को स्पेशल ट्रेनर द्वारा ट्रेनिंग दी जायेगी. ऑडीशन में निर्णायक पटना की कोरियोग्राफर मौसम शर्मा, मोहिनी अग्रवाल व निदेशक सुरेन्द्र प्रसाद वर्मा थे.■ *–सुनील सौरभ*

आशुतोष अध्यक्ष बने

एमएमटी प्रयास के कार्यकारिणी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक मोतिहारी में हुई जिसमें सवसम्मति से डॉ आशुतोष शरण को अध्यक्ष चुना गया. संस्था के सचिव अशोक वर्मा ने डॉ शरण के नाम का प्रस्ताव सदस्यों के समक्ष रखा. सभी सदस्यों ने इसका समर्थन कर दिया. गौरतलब हो कि डॉ शंभुशरण के निधन के बाद अध्यक्ष पद रिक्त हो गया था. बैठक में रामनाथ सिंह को उपाध्यक्ष एवं रामभजन को कोषाध्यक्ष का प्रभार दिया गया. मौके पर भूमि दाता बैधनाथ सिंह,महेन्द्र प्रसाद यादव, सत्यपाल सिंह छावड़ा, डॉ सचिदानन्द पटेल, प्रोजेक्ट मैनेजर विजय शर्मा, राजेन्द्र यादव, मिथलेश कुमार व विनोद तिवारी आदि उपस्थित थे.■ *–चौथी दुनिया ब्यूरो*

इनका प्यार दूसरों के लिए प्रेरणा है

इस जोड़े की कहानी आज केहर उस जोड़े केलिए मिसाल है जो प्रेम विवाह केबंधन में बंधना चाहते हैं. इनकी शादी को बरसों बीत गए, पर उनका प्यार ज्यों का त्यों ही है. डॉ कर्नल ए के सिंह बिहार केनिवासी हैं और उनकी पत्नी कश्मीर के पुंछ की हैं. कर्नल सिंह बताते हैं कि उनकी सास एक बहुत ही एक्टिव लीडर हुआ करती थीं. उस समय पुंछ में कोई भी लेडी डॉक्टर नहीं थी. इस बात की गंभीरता को देखकर उन्होंने पुंछ के तात्कालिक महाराजा केसामने एक प्रस्ताव रखा था कि पुंछ में एक लेडी डॉक्टर होनी चाहिए. लेकिन पुंछ जैसी जगह पर कोई भी लड़की काम नहीं करना चाहती थी. इस बात का हल निकालने केलिए उन्होंने सुदेश को डॉक्टर बनाना तय किया गया. उस समय सुदेश मिडिल स्कूल में पढ़ रही थीं. उन दिनों कश्मीर में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ करता था. ऐसे में सुदेश को एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए पटना भेजा गया, और उनका दाखिला पटना मेडिकल कॉलेज में हुआ.

राधिका

प्यार की राह में चाहे कितने भी कांटे आ जाए, अगर प्यार सच्चा हो उसे कोई हिला भी नहीं सकता है. प्यार में एक दूसरे का साथ निभाना सबसे बड़ी चुनौती होती है क्योंकि दो प्यार करने वालों का साथ इस समाज को आज भी गंवारा नहीं है. समाज ने इस तरह के कई दकियानूसी नियम बनाए हैं, जो इन नियमों केखिलाफ जाता है उन्हें समाज की मार झेलनी ही पड़ती है. लेकिन अगर प्यार में सच्चाई है तो ये सारी बातें प्यार केसामने बेमानी हो जाती हैं. इस बार की कहानी है एक ऐसे जोड़े की जिनका प्यार उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी कम नहीं हुआ है, बल्कि दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है. हम बात कर रहे हैं डॉ कर्नल ए के सिंह और उनकी पत्नी डॉ सुदेश सिंह की.

इस जोड़े की कहानी आज केहर उस जोड़े केलिए मिसाल है जो प्रेम विवाह केबंधन में बंधना चाहते हैं. इनकी शादी को बरसों बीत गए, पर उनका प्यार ज्यों का त्यों ही है. डॉ कर्नल ए के सिंह बिहार केनिवासी हैं और उनकी पत्नी कश्मीर के पुंछ की हैं. कर्नल सिंह बताते हैं कि उनकी सास एक बहुत ही एक्टिव लीडर हुआ करती थीं. उस समय पुंछ में कोई भी लेडी डॉक्टर नहीं थी. इस बात की गंभीरता को देखकर उन्होंने पुंछ के तात्कालिक महाराजा केसामने एक प्रस्ताव रखा था कि पुंछ में एक लेडी डॉक्टर होनी चाहिए. लेकिन पुंछ जैसी जगह पर कोई भी लड़की काम नहीं करना चाहती थी. इस बात का हल निकालने केलिए उन्होंने सुदेश को डॉक्टर बनाना तय किया गया. उस समय सुदेश मिडिल स्कूल में पढ़ रही थीं. उन दिनों कश्मीर में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ करता था. ऐसे में सुदेश को एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए पटना भेजा गया, और उनका दाखिला पटना मेडिकल कॉलेज में हुआ. सुदेश और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे. हम दोनों ने अपनी पढ़ाई पटना मेडिकल कॉलेज से की थी. पढ़ाई केदौरान हम पहली बार मिले थे. हम दोनों में बातें शुरु हुईं. हम दोनों एक दूसरे को पसमद करने लगे और फिर बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरु हो गया.

सुदेश की मां की हामी के बाद हमने शादी केसिलसिले में सुदेश केघरवालों से बातचीत की और यह तय हुआ कि हमारी शादी 1 जुलाई को होगी. हमारी शादी वर्ष 1964 में हुई थी. हमारी शादी दिल्ली से पूरी रीति रिवाज केसाथ हुई थी. डॉ कर्नल एकेसिंह आगे कहते हैं कि हमारी शादी केबाद सुदेश की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हुई और उन्हें कश्मीर में प्रैक्टिस करने भेजा जा रहा था. लेकिन मैंने उन्हें जाने नहीं दिया.

डॉ सिंह आगे बताते हैं कि सुदेश एक छोटी जगह से आती थीं इसलिए उन्हें बड़े शहर में एडजस्ट करने में कई तरह की दिक्कतें आ रही थीं. नई जगह थी, नए लोग थे, इन सारी चीजों से घुलने मिलने और तालमेल बैठाने में सुदेश को वक्त लग रहा था. मैंने सुदेश की इस कठिनाई को भांपते हुए, उन्हें इस नये वातावरण में घुलने-मिलने में मदद करने केलिए उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था. हमारी दोस्ती दिन-ब-दिन अच्छी या यूं कहें गहरी होती चली गई. हम दोनों के बीच की दोस्ती कब प्यार में बदल गई इस बात का हमें पता भी नहीं चला. वह आगे बताते हैं कि मैंने सुदेश को अपने घरावालों से भी मिलवाया था. मेरे घरवालों को वह काफी पसंद भी आई थीं. सुदेश मेरे घरवालों केसाथ काफी घुल-मिल भी गई थी. फिर एक समय आया जब हमारे रिश्ते को पांच साल हो गए और मेरे घरवालों ने कहा कि अब मुझे और सुदेश को शादी कर लेनी चाहिए. मेरे घरवालों की तरफ से तो कोई खास दिक्कत नहीं हुई थी लेकिन सुदेश की मां को ये रिश्ता मंजूर नहीं था. बहुत ही मशक्क से उन्हें मनाया गया तब जाकर उन्होंने इस रिश्ते के लिए हां कहा था.

सुदेश की मां की हामी के बाद हमने शादी केसिलसिले में सुदेश केघरवालों से बातचीत की और यह तय हुआ कि हमारी शादी 1 जुलाई को होगी. हमारी शादी वर्ष 1964 में हुई थी. हमारी शादी दिल्ली से पूरी रीति रिवाज के साथ हुई थी. डॉ कर्नल एकेसिंह आगे कहते हैं कि हमारी शादी केबाद सुदेश की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हुई और उन्हें कश्मीर में प्रैक्टिस करने भेजा जा रहा था. लेकिन मैंने उन्हें जाने नहीं दिया. इसके साथ ही मैं जहां-जहां पोस्टेड रहा वहं वहां सुदेश को उनकी नौकरी छुड़वाकर साथ ले जाता था. लेकिन उन्होंने इसकी कभी शिकायत नहीं की. पर कहीं ना कहीं उनके अंदर इस बात को लेकर नाराज़गी जरुर थी जिसका असर हमारे रिश्ते पर पड़ा. लेकिन फिर समय के साथ सब कुछ ठीक हो गया.

डॉ सिंह अपनी पत्नी केबारे में बताते हुए कहते हैं कि वो बहुत ही घरेलु किस्म की महिला हैं. सब का बहुत ख्याल रखने वाली महिला हैं. मैं काफी डॉमिनेटिंग हूं लेकिन वो मेरी हर चीज को मान लेती हैं और कुछ बोलती भी नहीं. उनकेइसी नेचर की वजह से हमारा रिश्ता इतने अच्छे से निभ पाया है. सुदेश अपने पति डॉ सिंह केबारे में कहती हैं कि वो बहुत हीं सिन्सियर इंसान हैं. जिस चीज को करने की सोच लेते हैं उसे करे बिना नहीं रहते हैं. उनका व्यक्तित्व सुलझा हुआ है.

इन दोनों का एक बेटा था जिसका नाम डॉ रुबन सिंह था. लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है. उन्हीं केनाम पर रुबन हॉस्पीटल की स्थापना की गई. उनकी एक बेटी है जिनका नाम डॉ सारिका रॉय है जो अपने आप में एक बड़ा नाम हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

मोतिहारी

जर्जर भवनों में चल रहे हैं विद्यालय और कार्यालय

इंतेजारुल हक़

मोतिहारी का जिला प्रशासन जर्जर व पुरानी इमारतों में वर्षों से चल रहे विद्यालयों व कार्यालयों व उनकी छतों पर विभिन्न कंपनियों द्वारा लगाये गये टावरों को हटाने के प्रति गंभीर क्यों नहीं है? बार-बार शिकायते मिलने व संबंधित अधिकारियों तथा लोगों द्वारा निवेदन करने के बावजूद वहां से कार्यालय व विद्यालय को क्यों नहीं हटाया जा रहा? इसके पीछे अधिकारियों की मंशा क्या है और वे इस मामले पर खामोशी क्यों अख्तियार किये हुए हैं? एक तरफ जहां लगातार आ रहे भूकंप के झटकों से चारों तरफ लोग दहशत में जी रहे हैं और अनेक तरह की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की इस खामोशी से एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ गया है

और इस मुद्दे पर बहसें भी होने लगी हैं.

जब भूकंप के झटके से कई नई इमारतें टूट सकती है,भवनों में दरारें आ सकती हैं और हादसे हो सकते हैं तो क्या पुरानी इमारतों जिसमें दरारें आ गई हैं, उनमें कार्यालया चलाया जाना व जर्जर भवनों में बच्चों को बैठा कर पढ़ाना उचित है? क्या यह लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं है? भारत-नेपाल सीमा पर स्थित पूर्वी व पश्चिमी चंपारण जिले में बहुत सी ऐसी इमारते हैं जो जर्जर हो गई हैं जो कभी भी धराशायी हो सकती हैं. वहां अभी भी कार्यालय चल रहे हैं और दिन भर अधिकारी व कर्मचारी अपना काम तो कर ही रहे हैं साथ ही आम लोगों का भी उन कार्यालयों में आना-जाना लगा रहता है. इसी तरह के हालात जिले में संचालित कई सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के भवनों केभी हैं, जहां हजारों बच्चे भगवान भरोसे दिनभर पढ़ाई करते हैं. कब यह भवन गिर जाए और कितने बच्चे इसमें दब जायें यह कहना काफी मुश्किल है.

अब हम बात करते हैं सरकारी कार्यालयों की. समाहरणालय के निकट एसपी कार्यालय के पीछे श्रम विभाग का कार्यालय है. श्रम विभाग का कार्यालय पूरी तरह जर्जर है और इसमें दरारें तो आई हैं ही साथ ही छत से ईंट व पत्थर भी लगातार गिरते रहते हैं. जानकार बताते हैं कि श्रम विभाग ने जिलाधिकारी को मामले से अवगत करा दिया है और भवन निर्माण विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है किन्तु भवन निर्माण विभाग की उदासीनता के कारण अभी तक यह मामला अधर में लटका हुआ है. सबसे चौकाने वाला तथ्य तो यह है कि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डाल कर काम तो करते ही हैं साथ ही मजदूरों का भी आना-जाना यहां लगा रहता है. आखिर भवन निर्माण विभाग जब इस भवन को देख चुका है तो फिर वह जिलाधिकारी को प्रतिवेदन क्यों नहीं दे रहा? अगर कोई हादसा होता है तो यह सीधा मामला भवन निर्माण विभाग पर जायेगा.

कमोबेश यही स्थिति पुरानी इमारतों की छतों पर वर्षों से लगे टावरों की है जिसे हटाने के लिए जिलाधिकारी समेत कई संबधित अधिकारियों को ज्ञापन दिए जा चुके हैं किंतु इस पर कोई कार्रवाई किसी अधिकारी द्वारा नहीं की गई. जानकार बताते हैं कि मोतिहारी शहर की मेन रोड जहां सुबह से लेकर शाम तक लोगों की भीड़ रहती है और हर तरह की मार्केटिंग वहां होती है, वहां स्थित रहमान कॉम्पलेक्स की तीस साल पुरानी बिल्डिंग पर लगा टावर कभी भी कोई बड़ी अनहोनी का कारण बन सकता है. यह टावर पांच साल से बंद है और काफी जर्जर हालत में है जो कभी भी क्षतिग्रस्त हो गिर सकता है और लोगों की जान जा सकती है. इसके अलावा भी शहर के विभिन्न इलाकों में बहुत सारे टावर स्थापित हैं जो मानदंडों को पूरा नही करते हैं. एक तरफ जहां भूकंप के झटके से बड़ी-बड़ी इमारतें डोल रही हैं और लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं. वहीं दूसरी तरफ इमारतों पर लगे ये टावर भूकंप पीड़ितों को मुंह चिढ़ा रहे हैं. उधर बाब संस्था के संस्थापक अध्यक्ष साजिद रजा बताते हैं कि कई बार इसकी शिकायत की गई और टावर हटाने के लिए नगर परिषद के सभापति सहित कई अधिकारियों से अनुरोध किया गया किन्तु अधिकारियों द्वारा अब तक कोई पहल नहीं की गई. ■

feedback@chauthiduniya.com

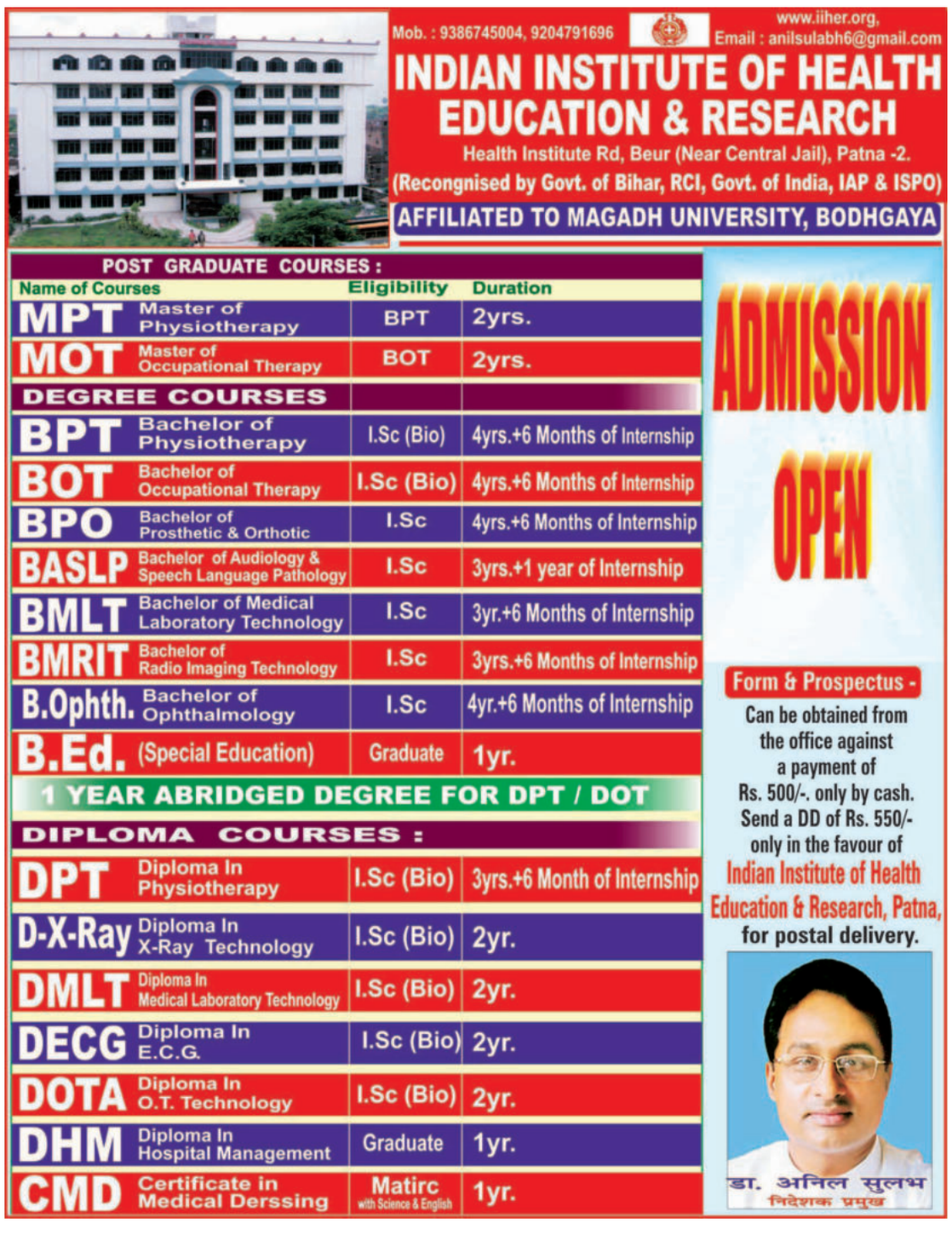

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

01 जून -07 जून 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आईएसआईएस के ख़िलाफ़ ठोकी ताल

प्रभात रंजन दीन

खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ भारत के शिया समुदाय के लोगों में भीषण नाराजगी बढ़ती जा रही है. इराक और पाकिस्तान में शिया समुदाय के लोगों के संहार को क्रमशः आईएसआईएस और पाकिस्तान में सक्रिय हिज्बुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों की करतूत बताया जा रहा है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष और प्रमुख शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक ने आईएसआईएस की बेदिमागी हिंसा के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए केंद्र सरकार को इसके खतरे की आशंका के प्रति सचेत किया है. इराक और पाकिस्तान में शियाओं के हो रहे कत्लेआम के खिलाफ शिया-बहुल लखनऊ में हो रहे प्रदर्शन और विरोध का नेतृत्व एक और शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने संभाल रखा है. आईएसआईएस के खिलाफ विरोध का लखनऊ केंद्र बनता जा रहा है.

आईएसआईएस की बढ़ती शैतानियों को लेकर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत सरकार इसे गंभीरता से ले. इराक और इरान की यात्रा से लौटे शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे सादिक ने कहा कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) की गतिविधियां काफी भयावह है. उन दहशतगर्दों का न तो कोई मजहब है और न ही कोई उद्देश्य. आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन देश में धार्मिक गतिविधियों को भड़का कर देश का अमन-चैन बर्बाद करने की फिराक में हैं. शिया धर्म गुरु ने इसके प्रति भारत सरकार को आगाह करते हुए इस दिशा में उचित कदम उठाने की मांग की है.

मौलाना कल्बे सादिक लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित जिस कार्यक्रम में बोल रहे थे, उसमें केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद थे. मौलाना ने कहा कि इराक और इरान की स्थिति काफी खराब है. आतंकी संगठन की तरफ से ऐसा बयान भी आया है कि दुनिया के मुसलमान अपने देश को छोड़ आईएसआईएस ज्वाइन करें. यदि वह ऐसा नहीं कर सकते तो अपने देश में ही रह कर जेहाद करें और हथियार उठाकर मुकाबला करें. इराक-इरान की यात्रा से लौटे मौलाना ने कहा कि आईएसआईएस के लोग वहां खूनी खेल रहे हैं. निर्दोषों को पकड़कर सरेआम गोली मारी जा रही है. उन्होंने भारत सरकार को आगाह करते हुए कहा कि आईएसआईएस की गतिविधियां समाज में तेजी से पैर पसार रही हैं, जिसके प्रति सख्ती से निपटने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि धार्मिक किताबों के जरिए जहर फैलाया जा रहा है. लखनऊ शहर और देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो आईएसआईएस, अलकायदा और तालिबान को अपने कलम से मदद दे रहे हैं. धार्मिक किताबों के जरिए शहर में जेहाद का बीज बोया जा रहा है. समाज में कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो युवाओं को बरगलाने की कोशिश भी कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा, मैं एक सच्चा मुसलमान हूं, मुझे अपने देश से प्यार है, तालिबान से नहीं.

मौलाना कल्बे सादिक धार्मिक कट्टरता, तथाकथित जेहाद, धर्म पर आधारित बेदिमागी हिंसा, मध्यकालिक तालिबानी बददिमागी और आईएसआईएस की शैतानियत के खिलाफ पहले भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते रहे हैं. अभी हाल ही में लखनऊ के इमामबाड़ा गुफरानमाब में जस्टिस मुर्तजा हुसैन की बरसी की मजलिस को संबोधित करते हुए मौलाना सादिक ने कहा था कि कोई धर्म ऐसा नहीं है, जिसके नाम पर लोगों को धोखा न दिया गया हो. इस्लाम का भी इसी तरह दुरुपयोग किया गया है. मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए सेफ हैवन बनाने के नाम पर उनकी भावनाओं को भड़काकर खुद तो कायदे आजम बन गए और पाकिस्तान को ऐसा मुल्कन बना गए, जहां मुसलमान ही मुसलमान के खून का प्यासा है. उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान सबसे अधिक सुरक्षित हैं. उन्होंने कहा कि इस्लाम तो मानवता की सेवा के लिए आया था, लेकिन आज तालिबान, आईएसआईएस, अलकायदा सब मानवता के लिए एक समस्या बन चुके हैं. यह इस्लाम नहीं है. इस्लाम मजहब नहीं, किरदार का नाम है.

इसके पहले इब्ने सीना एकेडमी में नेशनल काउंसिल प्रमोशन फॉर उर्दू लैंग्वेज लेक्चर सीरीज में मौलाना सैयद कल्बे सादिक ने कहा था कि सुन्नी सिर्फ मस्जिद बनवाने व शिया सिर्फ इमामबाड़ा बनवाने में व्यस्त हैं. इससे इन धार्मिक स्थानों की अहमियत कम हो रही है. मोहम्मद साहब के जमाने में मस्जिदों में तालीम भी मिलती थी. आज जितनी संख्या में मस्जिद व इमामबाड़े बनाए जा रहे हैं, उतनी ही तेजी से मुसलमान तालीम से दूर होता जा रहा है. उन्होंने मुसलमानों को झगड़ा फसाद से दूर रहने और बच्चों को तालीम देने पर जोर दिया. इस्लाम में दहशतगर्दी कहां विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी में मौलाना ने कहा कि इस्लाम को मानने वाला कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता. इस्लाम में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज नहीं है. सभी आतंकी गैर-इस्लामी हैं. मजहबे-इस्लाम दहशतगर्दों को पनाह देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बेनकाब करने का संदेश देता है. इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने का गंदा खेल कुछ चुनिंदा राजनीतिज्ञ और संगठन अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रहे हैं.

दूसरी तरफ, पाकिस्तान में शियाओं के नरसंहार के खिलाफ राजधानी लखनऊ में पिछले दिनों जोरदार प्रदर्शन हुआ और आतंकी संगठनों के साथ-साथ अमेरिका, इजराइल के झंडे जलाए गए और सऊदी के शाह का पुतला फूंका गया. लेकिन पाकिस्तान में शियाओं के कत्लेआम के खिलाफ पाकिस्तान का झंडा फूंकने से परहेज किया गया. पाकिस्तान के कराची शहर में इसमाइलियों पर पिछले दिनों हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ और सऊदी अरब में आयातुल्लाह बाकिरुन्नम्र की रिहाई की मांग को लेकर मजलिसे उल्माए हिन्द की तरफ से आसफी मस्जिद में आतंकवादी संगठनों और सऊदी अरब की इस्लाम विरोधी नीतियों के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजरायल के झंडे फूंके और सऊदी के शाह सलमान की तस्वीर भी जलाई. लेकिन पाकिस्तान का झंडा फूंकने से परहेज किया. प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए मजलिसे उल्माए हिन्द के महासचिव व शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी ने कहा कि पूरी दुनिया में शियों के खिलाफ हिंसा हो रही है. बड़ी बेदर्दी से शियों का नरसंहार किया जा रहा है. कराची में जिस संगठन के आतंकवादियों ने इसमाइलियों को बर्बर निशाना बनाया वह दाइश का समर्थक संगठन है. मौलाना ने कहा कि अफसोस है अभी भी दाइश का समर्थन हो रहा है जबकि उसका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है. हद यह है कि अखबारों में दाइश के समर्थन में लेख प्रकाशित हुए. यहां तक कि लखनऊ के अखबारों में भी दाइश के समर्थन में लिखा गया और उन्हें मुजाहिदे इस्लाम कहा गया. जब तक यह गुट मुसलमानों का नरसंहार करता रहा किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक अमेरिकी की हत्या हुई तो तुरंत दाइश को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया. सच यह है कि सऊदी अरब अमेरिका और इजरायल की गुलामी कर रहा है. उनके फतवे भी विश्व शक्तियों के इशारों पर आते हैं और जो लोग सऊदी अरब की खाते हैं, वे उनकी इस्लाम विरोधी हरकतों पर भी चुप रहते हैं.

प्रदर्शन में मौलाना रजा हुसैन ने कहा कि आतंकवाद कहीं भी किसी भी देश में हो, उसका कोई धर्म नहीं होता. इस्लाम के नाम पर कुछ गिरोह ऐसे निकल आए हैं जो इस्लाम की दुश्मन ताकतों के हाथों का खिलौना बने हुए हैं. यही लोग अलग-अलग संगठन बनाकर आतंकवाद फैला रहे हैं. इसमाइली समुदाय को निशाना बनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि ये लोग किसी भी समुदाय और किसी भी धर्म के लोग नहीं हैं, बल्कि इस्लाम का नकाब ओढ़े हुए हैं. मौलाना तसनीम मेहन्दी ने कहा कि इस हमले की जोरदार निंदा की जानी चाहिए. इस्लाम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ है. मौलाना ने कहा कि जिस तरह सऊदी अरब, अमेरिका और इजरायल के इशारों पर यमन में निर्दोषों की हत्या करा रहा है और आयातुल्लाह बाकिरुन्नम्र जो शिया व सुन्नी एकता की जिंदा मिसाल हैं, को फांसी देने की कोशिश में है, यह घनघोर अनुचित अमानवीय प्रक्रिया है .

मौलाना फिरोज हुसैन ने कहा कि अफसोस इस बात का है कि संयुक्त राष्ट्र ने भी यमन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया. आज की त्रासदी यह है कि मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है. उन्होंने सवाल भी पूछा कि आतंकवाद केवल मुसलमान देशों में ही क्यों है? उन्होंने कहा कि मुस्लिम विश्व शक्तियों की कठपुतली बने हुए हैं, इसीलिए उनकी यह स्थिति है. मौलाना ने मांग की कि सऊदी अरब आयातुल्लाह बाकिरुन्नम्र को रिहा करे और यमन पर तुरंत हमले बंद किए जाएं. यह मानवता विरोधी प्रक्रिया है, इसकी सर्वत्र निंदा की जानी चाहिए. प्रदर्शन में मौलाना हसन जाफर, मौलाना जव्वार हुसैन, मौलाना तसनीम मेहन्दी, मौलाना शबाब हैदर समेत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया.

गृहमंत्री भी जता चुके हैं चिंता

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी आईएसआईएस के बढ़ते खतरे के प्रति चिंता जाहिर कर चुके हैं. लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि आतंकवादियों के मंसूबे को भारत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने आईएसआईएस के प्रति युवाओं में बढ़ते आकर्षण को चिंता का विषय बताया और कहा कि दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा. भारत अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से अछूता नहीं है और इस्लामिक स्टेट की गतिविधियां हमें भी प्रभावित कर रही हैं. हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं और चाहे कितने भी आतंकी संगठन हों, हम उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे.

लोगों ने फूंका आईएसआईएस का पुतला

हापुड़ जिले के पिलखुवा में स्थानीय नागरिकों ने पिछले दिनों आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का पुतला फूंका. इराक में आईएसआईएस द्वारा 39 भातीय लोगों की गोली मारकर हत्या किए जाने की खबर से गुस्साए लोगों ने पिलखुवा रेलवे स्टेशन के पास आईएसआईएस का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया और विदेशों में फंसे भारतीयों को जल्द निकालने की केंद्र सरकार से गुहार लगाई. हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली इलाके के समाजसेवी पंकज शर्मा ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आईएसआईएस का पुतला फूंका. लोगों का कहना था कि इराक में 39 भारतीयों की निर्मम हत्या के विरोध में आईएस आईएस का पुतला फूंका गया और मृतकों के परिजनों के लिए भारत सरकार से मुआवजा देने की मांग की गई. जो भारतीय आतंकवादी प्रभावित देशों में फंसे हैं उन्हें भी सुरक्षित निकालने का भारत सरकार से आग्रह किया गया है.

जब लखनऊ में हुआ था जोरदार स्वागत

छह महीने पहले ही आईएसआईएस के आतंकियों से जंग लड़कर लौटे 28 साल के मौलाना सैयद अब्बीस नसीर सईद अबकाती का शिया समुदाय के लोगों ने लखनऊ में जोरदार स्वागत किया था. कहा गया था कि अबकाती अकेला ऐसा भारतीय है, जो आईएसआईएस के खिलाफ युद्ध में शामिल रहा. 2014 के जुलाई महीने में आईएसआईएस ने जब इराक पर हमला किया था तब वह नजफ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था. अबकाती का दावा है कि इराकी सेना के साथ मिलकर स्थानीय नागरिकों ने करीब एक महीने तक आईएसआईएस आतंकियों से युद्ध लड़ा. इस जंग में वह भी शामिल थे. अबकाती ने बताया था कि आतंकियों से लड़ने के लिए सेना ने आम नागरिकों को प्रशिक्षण दिया था, जिसमें कई अन्य देशों के लोग भी शामिल थे. प्रशिक्षण के बाद इराकी सेना ने उन्हें बगदाद से 125 किलोमीटर दूर समारा में आईएसआईएस का मुकाबला करने के लिए भेजा था. अबकाती के सम्मान में नक्खास रोड पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. ■

सऊदी अरब कर रहा आईएसआईएस की मदद

सऊदी अरब आईएसआईएस की मदद कर रहा है. सऊदी अरब आईएसआईएस को वैचारिक, आर्थिक और फौजी मदद मुहैया करा रहा है. सऊदी अरब कट्टर सुन्नी इस्लाम को बढ़ावा देने और उसके जरिए सीरिया, इराक जैसे देश में सुन्नियों की सत्ता स्थापित होते हुए देखना चाहता है. आईएसआईएस एक सुन्नी आतंकवादी संगठन है. इसका एक अन्य नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट (आईएसआईएल) भी है. लेवेंट का मतलब उस इलाके से है जो दक्षिण तुर्की से मिस्र तक फैला हुआ है. इसमें सीरिया, जॉर्डन और इजरायल तक शामिल हैं. आईएसआईएस का मकसद तुर्की से लेकर मिस्र तक इस्लामी राज की स्थापना और शरिया कानून का पालन करवाना है. शियाओं के लिए इराक अत्यंत अहम है. इराक में मौजूद कर्बला, नजफ और समारा में शिया इमामों की मजारें हैं. इसलिए दुनिया भर के शिया इराक के इन शहरों की यात्रा करते हैं. इराक में आईएसआईएस की हिंसा का दौर जारी रहा तो पूरे पश्चिम एशिया में सांप्रदायिक विवाद हिंसक जंग की शक्ल अख्तियार कर लेगा. इससे पेट्रोलियम पदार्थों पर आधारित अर्थव्यवस्था डांवाडोल हो जाएगी. तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे. अमेरिका चाहता है कि इराक संकट खत्म हो जाए ताकि पश्चिम एशिया में शांति बहाल हो सके. अमेरिका को इस बात की भी चिंता है कि युद्ध और अस्थिरता की वजह से तेल के दाम बेकाबू हो सकते हैं. लेकिन अमेरिका इराक में अपने सैनिक नहीं उतारना चाहता. वह इस देश में पिछले करीब एक दशक तक लड़ता रहा है. लेकिन अमेरिका ने अपने सैकड़ों सुरक्षा विशेषज्ञ और राजनयिक इराक भेजे हैं. यह अमेरिकी टीम आईएसआईएस के विद्रोह को कुचलने और इराक में कानून व्यवस्था कायम करने में अल मलीकी सरकार की मदद कर रही है. नूरी अल मलीकी शिया समुदाय से आते हैं. मलीकी सऊदी अरब पर आरोप लगा चुके हैं कि वह आईएसआईएस को आर्थिक और सैन्य मदद दे रहा है. विशेषज्ञ बताते हैं कि अमेरिका-ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर उपजे विवाद से निपटने और ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के हटने की संभावनाओं के चलते सऊदी अरब को लगने लगा था कि तेल की सप्लाई बढ़ेगी और इस वजह से दाम घटेंगे. अपने बढ़ते खर्चों की वजह से सऊदी सरकार का घाटा बढ़ता जा रहा है. तेल को ऊंचे दाम में बेचकर सऊदी अरब अपने बजट घाटे को पूरा करना चाहता है. आईएसआईएस के आतंकी सीरिया और इराक में तेल के कुओं और रिफाइनरियों पर कब्जा कर रहे हैं. वे दुनिया को भेजे जा रहे तेल की सप्लाई को रोक कर महंगे दाम में तेल बेचने का सौदा कर रहे हैं. इसका फायदा सऊदी अरब को हो रहा है. ताजा संकट की वजह से तेल के दाम बढ़ने शुरू हो चुके हैं. ऐसी स्थिति का फायदा सऊदी अरब जैसे देश अपना खजाना भरने में कर रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार

शासन पर भारी पंचायतें

वैष्णवी वंदना

उत्तर प्रदेश और बिहार ने तालिबानियों को काफी पीछे छोड़ दिया है. इन राज्यों की पंचायतों ने बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ डाली हैं. बिहार के गया जिले में पिछले दिनों एक प्रेमी प्रेमिका को जिंदा जला कर मार डाला गया. पंचायत के आदेश पर युवक-युवती को जिंदा ही चिता पर लिटा कर आग लगा दी गई. उसके बाद उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला सुर्खियों में आ गया, जहां महिलाओं को काम करने की सजा में कोड़े की पिटाई मिली. जाति पंचायत ने महिलाओं को पेड़ से बांध कर कोड़े मारने का हुक्म सुनाया और हुक्म की तामील हुई. कार्रवाई की जगह महिला आयोग ने मौका-मुआयना करने की औपचारिकता निभाई और औचित्य पूरा किया. महिलाओं को कोड़े मारने या उनके साथ सार्वजनिक बदसलूकी करने का यह कोई अकेला मामला नहीं है. काम करने घर से बाहर निकली मेरठ की कुछ महिलाओं पर भी पंचायत ने कोड़े बरसाए और जुर्माना किया. शाहजहांपुर जलालाबाद में तो पांच महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनके साथ सार्वजनिक रूप से बदसलूकी की गई.

मुरादाबाद के कांठ में छजलैट के गांव सलावा की एक कबीलाई बस्ती में बिरादरी की पंचायत ने दो महिलाओं को पेड़ से बांधकर कोड़े मारे जाने की सजा सुनाई थी. पंचायत का खौफ इतना है कि पीड़ित महिलाओं के साथ-साथ अन्य लोग भी चुप्पी साधे बैठे हैं. कुछ लोगों ने गुपचुप तरीके से पंचायत की सजा और महिलाओं को बांध कर कोड़े लगाए जाने की बात स्वीकार की. छजलैट के गांव सलावा के एक छोर पर कबीलाई बस्ती है. इसमें करीब चालीस घर हैं. पिछले दिनों एक परिवार की दो बहुओं (देवरानी और जेठानी) और उनकी सास के झगड़े का प्रकरण बिरादरी की पंचायत में रखा गया था. बिरादरी के आपसी व घरेलू विवाद इसकी अपनी पंचायत में ही सुलझाने की परंपरा रही है.

सास बहुओं के झगड़े को लेकर जुटी इस पंचायत में दोनों के पति भी मौजूद थे. पतियों के कहने पर ही पंचायत जुटी थी. इस पंचायत में दोनों बहुओं की गलती मानते हुए पेड़ से बांधकर कोड़े मारने की सजा सुनाई गई थी. इस फरमान पर अमल भी किया गया. हैरत की बात यह है कि इस घटना के बारे में छजलैट थाने को कुछ जानकारी ही नहीं थी. अखबारों में खबर छपने के बाद पुलिस को इस बारे में पता चला. लेकिन फिर भी इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. केवल दोनों जख्मी महिलाओं को थाने लाकर उनका चिकित्सीय परीक्षण कराने की औपचारिकता निभाई गई. पुलिस की रिपोर्ट भी रोचक है, जिसमें महिलाओं के शरीर पर कोई चोट नहीं पाए जाने की बात कही गई. जबकि कोड़े की मार से महिलाएं बुरी तरह चोटिल हैं. लोग बताते हैं कि महिलाओं से पुलिस ने जबरन लिखवा लिया कि उनके साथ किसी भी प्रकार की न तो मारपीट हुई और न उन्हें पेड़ से बांधा गया और न ही कोड़े मारे गए. लेकिन दोनों बहुएं और सास आपसी झगड़े की बात स्वीकार कर रही हैं. दबाव का हाल यह है कि महिला आयोग की टीम के सामने भी पीड़िताओं ने पेड़ों से बांधे जाने और कोड़े मारे जाने से इनकार कर दिया. लेकिन इसी बस्ती की तीन महिलाओं और कुछ युवकों ने पंचायत में फरमान सुनाए जाने, दोनों बहुओं को पेड़ से बांधे जाने और कोड़े मारे जाने की बात कही, और यह बात राज्य महिला आयोग तक पहुंची.

उस बस्ती के बारे में पता चला कि कबीलाई बस्ती की अपनी पंचायती न्याय व्यवस्था अत्यंत खौफनाक और भयानक है. कबीलाई बस्ती में आपसी विवादों व गलतियों पर बिरादरी की पंचायतें ही दंडित करने का काम करती रही हैं. चोरी की बात सामने आने पर दोषी को गर्म लोहे की छड़ों से दागा जाता है. ऐसे ही बहुत सारी सजाएं और प्रताड़ना के मामले जमाने से चले आ रहे हैं. ग्राम प्रधान मोहम्मद यासीन कहते हैं कि इस बिरादरी में पंचायत में आपसी मामले दंड के आधार पर ही जमाने से निपटाए जाते रहे हैं. मेरठ के ग्रामीण एसपी जन-परिचित रटे-रटाए अंदाज में कहते हैं कि महिलाओं को कोई चोट नहीं है. फिर यह भी कहते हैं कि किसी ने भी कार्रवाई के लिए कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है. फिर वे महिलाओं को दी गई सजा से इन्कार भी नहीं करते और कहते हैं कि पंचायत के द्वारा महिलाओं को सार्वजनिक दंड दिए जाने की बात सामने आई है. इसकी गहनता से जांच की जा रही है. यदि दोष निर्धारण हुआ तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई निश्चित की जाएगी. पुलिस अपने स्तर से जांच में जुटी है. एसपी के बयान से ही आप कानूनी कार्रवाई की गंभीरता का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं.

ऐसी ही घटना मेरठ में भी हुई है. यहां पीपलीखेड़ा गांव में पंचायत ने नट समुदाय की महिलाओं को सौ कोड़े मारने और एक लाख रुपये जुर्माने का ऐलान किया. महिलाओं की गलती यह थी कि उन्होंने घर से बाहर निकलकर मेहनत-मजदूरी की थी. पंचायत ने उनके बाहर निकलकर काम करने पर रोक लगा दी है और इस फरमान को न मानने पर सौ कोड़े और एक लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित किया है. पीपलीखेड़ा में नट समुदाय के लगभग सौ परिवार रहते हैं. गरीबी की वजह से नट महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर मेहनत-मजदूरी करने का साहस किया. कट्टर पंचायतों को उनका यह फैसला रास नहीं आया और उन्होंने महिलाओं के बाहर निकलने पर रोक लगा दी. फिर भी जब महिलाओं ने इनकी नहीं सुनी तो उन पर कोड़े बरसाए गए.

महिलाओं ने जब पुलिस से शिकायत करनी चाही तो वह उन्हें टरकाने में लग गई. अब पंचायत ने पुलिस से शिकायत करने पर भी 10 हजार रुपये जुर्माने का ऐलान कर दिया है. जुर्माना न देने पर बस्ती छोड़ने का भी फरमान सुना दिया गया है. अब पीड़ितों का परिवार बहुत डरा हुआ है. पूर्व ग्राम प्रधान जहरुद्दीन ने माना कि महिलाएं उनके पास शिकायत लेकर आई थीं. वहीं खरखौदा पुलिस स्टेशन के एसओ का कहना है कि यह कोई बड़ी बात नहीं, यह नटों का आपसी मामला है. उन्होंने कहा कि अगर हमें इस मामले में लिखित अर्जी मिली तो हम कार्रवाई करेंगे.

शाहजहांपुर जलालाबाद के हरेवा गांव में पांच महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के शर्मनाक मामले में नामजद दस आरोपियों में दो और महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया. लेकिन इस गिरफ्तारी से मामले की गंभीरता थोड़ी कम हो जाती है. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जरीना उस्मानी भी जांच के लिए गांव पहुंचीं. उन्होंने घटना को लेकर पुलिस की भूमिका को बेहद लापरवाह करार दिया. घटना की जानकारी के बाद कमिश्नर और डीआइजी ने भी गांव का दौरा कर पीड़ित परिवार को कार्रवाई का भरोसा दिलाया. इसके बाद आरोपी महिलाएं फूलवती पत्नी संतराम और मीना पत्नी राकेश को गिरफ्तार कर लिया. पांच आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं. पांच महिलाओं को सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र किए जाने का मामला एक लड़की के अपहरण से जुड़ा है. हालांकि अगवा की गई लड़की दिल्ली में बरामद भी कर ली गई थी, लेकिन उसके नाम पर पांच महिलाएं सार्वजनिक रूप से बेइज्जत हो गईं. पूरे गांव में दहशत का माहौल है. एहतियातन फोर्स तैनात है. गवाही से बचने के लिए गांव से लोगों का पलायन भी हो रहा है. कई संगठनों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है.

किशोरी के अपहरण मामले में पुलिस ने अगर त्वरित गति से कार्रवाई की होती तो दलित महिलाओं के साथ बदसलूकी की शर्मनाक घटना नहीं होती. उल्लेखनीय है कि जलालाबाद थाना क्षेत्र के हरेवा गांव निवासी सर्वेश कुमार की पत्नी अपनी पंद्रह वर्षीय पुत्री पूजा के साथ खेत पर जा रही थी. तभी गांव के ही संतोष पुत्र नन्हे और उसके साथियों ने पूजा का अपहरण कर लिया था. विरोध करने पर पूजा की मां को तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर अपहरणकर्ता चले गए. सर्वेश की पत्नी ने गांव लौटकर पूजा को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से बचाने की चीख-चीखकर गुहार लगाई. फौरन ही घटना की तहरीर स्थानीय पुलिस को दी गई. लेकिन पुलिस ने इस घटना को लेकर कतई गंभीरता नहीं बरती. पुलिस के रवैये से निराश किशोरी के परिजनों ने आरोपी युवक के घर पर हमला बोल दिया और घर में मौजूद आरोपी की मां, ताई तथा चाचियों को पीटते हुए उनके कपड़े फाड़कर निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया. ■

feedback@chauthiduniya.com

नाइंसाफी नहीं होने देंगे : मुलायम

हाशिमपुरा मामले में हाईकोर्ट जाएगी यूपी सरकार

सूफी यायावर

मेरठ के हाशिमपुरा दंगा कांड मामले में दिल्ली की निचली अदालत द्वारा अभियुक्तों को बरी किए जाने के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में अपील दाखिल करेगी. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय ध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह फैसला किया है. हाशिमपुरा कांड के पीड़ितों ने पिछले दिनों मुलायम सिंह यादव से मुलाकात भी की थी. राज्य सरकार के फैसले की आधिकारिक पुष्टि करते हुए प्रदेश के अपर महाधिवक्ता जफरयाब जिलानी ने कहा कि दिल्ली की निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में ही मई के आखिरी हफ्ते तक अपील दाखिल कर दी जाएगी. जिलानी ने कहा कि इसके लिए दिल्ली में संबंधित वकीलों को अपील का मसविदा भेज दिया गया है. उनकी तरफ से राय मिलते ही अपील दाखिल कर दी जाएगी. प्रदेश सरकार की कोशिश है कि 29 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले यह काम मुकम्मल हो जाए.

आप सब जानते हैं कि 22 मई 1987 को मेरठ के हाशिमपुरा में हुए दंगे में आरोप है कि पीएसी के जवानों ने कई मुस्लिम युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उनके शव एक नहर में फेंक दिए थे. इस मामले में दिल्ली की निचली अदालत ने 21 मार्च को निर्णय सुनाते हुए सभी 16 आरोपी पीएसी जवानों को सुबूत के अभाव में बरी कर दिया था. अदालत ने पीएसी के जवानों को बरी करते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष संदिग्ध पुलिसकर्मियों की पहचान साबित करने में नाकाम रहा है. इस मामले में 19 अभियुक्त बनाए गए थे, लेकिन तीन अभियुक्तों की इस दरम्यान मौत हो गई. समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने पिछले दिनों अपने निवास स्थान पर हाशिमपुरा दंगे के पीड़ितों से मुलाकात की थी. सपा प्रमुख ने पीड़ितों के परिवारजनों को राज्य सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपये की सहायता देने का आश्वासन भी दिया. सपा नेता आशु मलिक की अगुवाई में प्रतिनिधि दल ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी. प्रतिनिधि दल ने सपा प्रमुख के सामने ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग रखी. सपा प्रमुख से मुलाकात करने आए प्रतिनिधिमंडल में जमात उलेमा-ए-हिंद के सदस्यों के अलावा हाशिमपुरा इंसाफ़ कमेटी के छह सदस्य भी शामिल थे. उन्होंने सपा प्रमुख को हाशिमपुरा और मलियाना के 121 लोगों की सूची भी सौंपी जिन्हें मुआवज़ा दिए जाने की मांग की गई. मलियाना कांड के पीड़ितों ने भी सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर अपनी मांगें सामने रखीं.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने दिल्ली सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील किए जाने का निर्णय बताते हुए प्रतिनिधिमंडल से कहा कि वे इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं और किसी भी गरीब, पीड़ित और शोषित के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी. एमएलसी आशु मलिक के नेतृत्व में हाशिमपुरा और मलियाना के पीड़ित तथा जमीयतुल उलमाये हिन्द के प्रदेश अध्यक्ष अशद रसीदी समेत सहारनपुर के मौलाना रियाज अहमद कांधला और मौलाना बद्र भी मुलायम से मिले. इस मौके पर राजनीतिक पेंशन मंत्री राजेन्द्र चौधरी भी मौजूद थे. मुलायम के आश्वासन के फौरन बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाशिमपुरा एवं मलियाना की घटनाओं में पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की. सरकार ने इस फैसले की भी घोषणा की कि हाशिमपुरा की घटना के आरोपियों को दिल्ली के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के फैसले के विरुद्ध प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील करने का निर्णय लिया है.

सरकार पर ही उठ रही उंगली

इंडियन नेशनल लीग ने भी हाशिमपुरा कांड को लेकर समाजवादी पार्टी के रवैये पर तीखा हमला बोला है. पिछले दिनों कानपुर में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीग के नेताओं ने कहा कि बेगुनाहों की सामूहिक हत्या के अपराध में प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार, खासकर मुलायम सिंह यादव बराबर के भागीदार हैं. लीग ने कहा कि मुलायम सिंह ने हाशिमपुरा हत्याकांड में इस्तेमाल राइफलों को जब्त करते हुए उसे केस से जोड़ा ही नहीं. यही नहीं, अदालत में चल रहे इस मुकदमे में लंबे समय तक सरकारी वकील तक नहीं उपलब्ध कराया गया. इस दौरान मशावरत की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई और उसके बाद इस केस को दिल्ली स्थानांतरित किया गया. समाजवादी पार्टी सरकार ने अदालत में इतनी लचर पैरवी की कि उसका नतीजा सबके सामने है. इंसाफ की हत्या के इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी सरकार तथा मुलायम सिंह यादव की भूमिका रही है. लीग ने यह भी कहा कि पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए अब वे सड़क पर उतरेंगे. लीग ने मांग की कि इस मामले में सूबे की समाजवादी पार्टी सरकार हाशिमपुरा प्रकरण में तत्काल पुनरविवेचना कराने की घोषणा करे. बताया गया कि रिहाई मंच को हाशिमपुरा पीड़ितों के इंसाफ के सवाल पर लखनऊ में कार्यक्रम तक नहीं करने दिया जाता और आजम खान दिल्ली में कैंडिल जुलूस का आयोजन करते हैं. अगर आजम खान अदालत के फैसले से इतने ही दुखी हैं तो फिर सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में पूरे मामले की सबीआई या एसआईटी से जांच की घोषणा अपनी पार्टी से क्यों नहीं कराते? हाशिमपुरा के पीड़ितों को इंसाफ तब तक नहीं मिल सकता जबतक कि इस पूरे प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में फिर से जांच नहीं होती. लीग ने मांग की प्रदेश की सांप्रदायिक हिंसा पर अब तक जितने भी आयोग गठित हुए हैं उनकी जांच रिपोर्ट समाजवादी पार्टी सरकार तत्काल सार्वजनिक करे. प्रेस कार्फ्रेंस को इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्म्द सुलेमान, रिहाई मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शुऐब एडवोकेट, सामाजिक कार्यकर्ता एखलाक हुसैन चिश्ती वगैरह ने संबोधित किया था.

मुस्लिम नेता सेंकते हैं रोटियां

हाशिमपुरा के लोगों से मिलने कोई मुस्लिम नेता नहीं आता. समझाने-बुझाने या उनकी पीड़ा कम करने के लिए प्रयास करने की किसी नेता को फुर्सत नहीं. याकूब कुरैशी जैसे वाचाल नेता हाशिमपुरा से कुछ ही दूरी के फासले पर रहते हैं, लेकिन वहां झांकने तक नहीं जाते. कार्टून के मसले पर इस्लाम-परस्त होने का ढोंग करते हुए आपराधिक ऐलान करने से नहीं हिचकते, लेकिन हाशिमपुरा जाने से हिचकते हैं.

अदालत का फैसला आने के बाद हाशिमपुरा के लोग नेताओं से अधिक नाराज हैं. यह नाराजगी इसीलिए है कि किसी भी पार्टी के नेता ने वहां आकर लोगों की तकलीफ बांटने की जहमत नहीं उठाई. जबकि हाशिमपुरा से कुछ ही दूर राज्य सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री रफीक अंसारी और अय्यूब अंसारी रहते हैं. पूर्व सांसद और मेयर हाजी शाहिद अखलाक भी मेरठ शहर में ही रहते हैं, जिनके पिता हाजी अखलाक मरहूम ने इस त्रासदी के बाद नारा दिया था कि दंगा नहीं व्यापार देंगे, नफरत नहीं प्यार देंगे, मगर उनके वारिस ने भी हाशिमपुरा के पीड़ितों से मिलना जरूरी नहीं समझा. हाशिमपुरा के लोग कहते हैं कि वोट के लिए जो दर-दर मांगते दिखते हैं, आज सब नदारद हैं.

बुखारी ने याद दिलाया वादा

दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना बुखारी ने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव को पत्र लिख कर उन्हें उनका वादा याद दिलाया है. बुखारी ने मुलायम को पत्र लिख कर पूछा है कि मुस्लिमों के हित में सपा ने क्या-क्या किया. बुखारी ने कहा है कि सपा ने वादा किया था कि प्रदेश में सरकार बनते ही निमेष कमीशन की सिफारिशें लागू करेंगे. लेकिन सरकार बनने के बाद सपा इन वादों को भूल गई है. सरकार ने आतंकवाद के नाम पर जेल में बंद बेगुनाहों को छोड़ने का वादा भी किया था, लेकिन उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ. बुखारी ने कहा कि उन्होंने मुलायम को पहले भी पत्र लिख कर इन बातों को उठाया था. बुखारी का कहना है कि सरकार की वादाखिलाफी के कारण मुसलमानों में मायूसी बढ़ती जा रही है. यदि यही हाल रहा तो विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय सपा के प्रति अपनी राय बदल सकता है. बुखारी ने सपा मुखिया को आगाह भी किया है कि 2012 में किए गए वादे नहीं पूरे किए गए तो 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को मुसलमानों की नाराजगी भारी पड़ सकती है.

पत्र में बुखारी ने सपा प्रमुख से पूछा है कि सपा की सरकार बनने के बाद यूपी में मुस्लिमों के हित के लिए क्या-क्या काम किए गए? 2012 के विधानसभा चुनाव के समय सपा की ओर से मुस्लिमों के लिए किए गए वादे अभी तक पूरे न किए जाने पर बुखारी ने अफसोस जताया है. इमाम ने मुलायम को याद दिलाया है कि मुसलमानों की आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक हालत बेहतर बनाने के लिए चुनावी घोषणा पत्र में 16 वादे किए गए थे. सरकार बने तीन साल हो गए लेकिन उनमें से ज्यादातर पर अब तक अमल नहीं हो सका है. इमाम बुखारी ने कहा कि मुलायम ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्र आयोग और निमेष कमीशन की सिफारिशें लागू की जाएंगी, लेकिन सरकार बनने के बाद सपा इन वादों को भूल गई. ■

feedback@chauthiduniya.com

कोमा में पड़े विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग

रामझरोखे दास

पिछले दो वर्ष से कोमा में पड़े बहराइच के विधायक और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता वकार अहमद शाह की विधायकी जन-प्रतिनिधित्व कानून की आंख में किरकिरी की तरह चुभ रही है. बहराइच विधानसभा क्षेत्र जन-प्रतिनिधि होते हुए भी वह लंबे अर्से से अपने जन-प्रतिनिधित्व से वंचित हैं. बीमार वकार अहमद शाह की विधायकी संवैधानिक पेंच की तरह घुस गई है. अब समस्या यह है कि वकार अहमद शाह के जिंदा (तकनीकी रूप से) रहते हुए उनकी सीट खाली कैसे की जाए. इस समस्या के समाधान के लिए या कहें उनकी विधायकी रद्द कर बहराइच विधानसभा सीट रिक्त घोषित किए जाने की राज्यपाल से मांग की गई है.

कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने बहराइच विधान सभा क्षेत्र के विधायक वकार अहमद शाह के लम्बे समय से कोमा में होने के कारण उन्हें संविधान के अनुच्छेद-191 के अनुसार अयोग्य बताते हुए उनकी सदस्यता समाप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक के समक्ष याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया जब व्यक्ति कोमा में होता है तो उतने समय के लिए उसके सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह समाप्त हो जाती है. इस प्रकार वह अनुच्छेद 191 में पारिभाषित (अनसाउंड माइंड) की परिभाषा के अंतर्गत आ जाता है. वकार अहमद शाह जैसे वरिष्ठ नेता के कोमा में चले जाने को अफसोसजनक बताया गया है, लेकिन कहा गया है इससे व्यवहारिक राजनीति में अड़चनें आ रही हैं और बहराइच विधानसभा क्षेत्र खुद को विधानसभा में उपेक्षित और प्रतिनिधित्वहीन महसूस कर रहा है. शाह दो साल से कोमा में हैं. इसी वजह से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें मंत्री पद से हटा कर उनके बेटे यासिर शाह को राज्य मंत्री बनाया था. ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्र की जनता को विधान सभा में जनप्रतिनिधि पाने के संवैधानिक अधिकारों से वांछित नहीं रखा जा सकता है. लिहाजा, राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद-192 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वकार अहमद शाह की सदस्यता नियमानुसार रद्द करते हुए नए चुनाव कराए जाने की अधिसूचना जारी करें. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें श्रम एवं सेवायोजन मंत्री के पद से मुक्त कर उनके बेटे को राज्य मंत्री बनाने का फैसला किया था. तब इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से संवैधानिक सलाह-मशविरा लेकर ही कार्रवाई की थी. शाह बहराइच से विधायक हैं और वे बहराइच से लगातार पांच बार से चुनाव जीत रहे हैं. वर्ष 2013 में ही मार्च में बजट सत्र के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई थी. तब से वह लगातार अस्वस्थ चल रहे हैं. शाह विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

लेकिन अब वह समय आ गया है जब यूपी के श्रम मंत्री रहे विधायक वकार अहमद शाह के लंबे समय से कोमा में रहने के चलते उनकी सदस्यता जा सकती है. सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने राज्यपाल राम नाइक से संविधान के अनुच्छेद-192 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए शाह की सदस्यता नियमानुसार रद्द कर नए चुनाव कराए जाने की मांग की है. उनका कहना है कि शाह के लगातार अस्वस्थ रहने से क्षेत्र का विकास बाधित हो रहा है. अभी फिलहाल वकार अहमद शाह गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मेदांता अस्पताल जाकर उनका हाल-चाल ले चुके हैं. पिछले दिनों अखिलेश यादव ने शाह का हाल-चाल लेने के बाद इस सिलसिले में मेदांता मेडिसिटी के प्रमुख डॉ. नरेश त्रेहन से भी मुलाकात की थी. वकार अहमद शाह की हालत अभी भी काफी गंभीर बनी हुई है. उन्हें कई किस्म की जटिलताएं हैं, उन्हें आईसीयू में रखा गया है. वकार अहमद शाह पिछले आठ मार्च से ही मेडिसिटी में भर्ती हैं.

राजनीतिक विरासत

डॉ. वकार अहमद शाह खुद बहराइच विधानसभा सीट से सपा विधायक हैं. उनकी पत्नी रुबाब सईदा बहराइच की पूर्व सांसद हैं और उनके बेटे यासर शाह पूर्व जिला पंचायत सदस्य और वर्तमान में सपा के विधायक हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

राष्ट्रपति ने सदन की बहस के गिरते स्तर पर चिंता जताई

रेनू शर्मा

उत्तराखंड के इतिहास का एक गौरवशाली दिन था. जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रदेश की विधानसभा को पहली बार संबोधित कर विधायकों को संसदीय परंपराओं व संसदीय शिष्टाचार का ज्ञान दिया. विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुखर्जी ने जहां एक तरफ विधायकों को उनके कर्तव्यों का बोध कराया वहीं सदन में बहस लगातार गिरते स्तर पर चिंता जताई. पूरे देश में विधायक कानून बनाने के काम पर कम समय दे रहे हैं और सदन की बैठकों का समय कम हो गया है. उन्होंने काह कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहां आने का अवसर उनको मिलता रहता है. वर्ष 2013 में आई आपदा के बाद राज्य को काफी नुकसान हुआ था, राज्य सरकार की हिम्मत से एक बार फिर यहां चारधाम यात्रा शुरु हो पायी है और देश के अंदर सुरक्षित यात्रा का सन्देश देने में राज्य सरकार सफल हुई है. उन्होंने कहा कि राज्य का विकास सभी दलों को मिलकर करना होगा तभी प्रदेश को आगे ले जाया जा सकता है.

राष्ट्रपति मुखर्जी ने अपने संबोधन में बीते 14 वर्षों में उत्तराखंड के विकास की प्रशंसा तो की, लेकिन इस बात पर चिंता जाहिर की कि प्रदेश में समान विकास नहीं हो रहा है और पहाड़ी क्षेत्र विकास की दौड़ में कहीं पिछड़ गए हैं. राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2000 में बने उत्तराखंड ने भारतीय संघ का 27वां राज्य बनने के बाद महत्वपूर्ण प्रगति की है. उत्तराखंड में गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोगों का प्रतिशत कम करने में कामयाबी मिली है. यह 2004-05 में 32.7 फीसद था जो 2012 में 11.3 फीसद पहुंच गया है. राज्य के 99 फीसद गांवों में अब बिजली पहुंच चुकी है. प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर करीब 10 फीसद रही है, यह एक समान नहीं है और पहाड़ी क्षेत्र इसमें पिछड़े हुए हैं. राष्ट्रपति ने सतत विकास के प्रयासों के लिए उत्तराखंड की प्रशंसा करते हुए वन व पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आम जनता के प्रयासों की भरपूर प्रशंसा की. उन्होंने चिपको आंदोलन की प्रणोता गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा के प्रयासों को याद करते हुए राष्ट्रपति ने चिपको का गीत जल है हमारा, जमीन है हमारी, जंगल है हमारा, इन्हें हमारे पूर्वजों ने रोपा है, अब हमें ही इनकी रक्षा करनी होगी, भी सुनाया. राष्ट्रपति ने यह जिक्र इस राज्य के लिए किया जिसके लिए जंगल एक ऐसी धरोहर है जिसे विकास में बाधा बताया जा रहा है. कहा कि आज सामुदायिक सहभागिता से राज्य के वनों के बड़े हिस्सों का प्रबंधन करने वाली 12 हजार वन पंचायतें देश की अनोखी संस्थाएं बन चुकी हैं. उत्तराखंड को अपने गठन के बाद से 10 वर्षों में अपने वन क्षेत्र में 1100 वर्ग किमी से ज्यादा बढ़ोतरी का श्रेय जाता है. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस बात पर खुशी जताई कि राज्य में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की पहल हो रही है. नए विधानसभा भवन का निर्माण शुरू हो गया है. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा शासन में सुधार के लिए ई-कोष, भू अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण, जन सेवाओं की ऑनलाइन सुपर्दगी, ऑन लाइन शिकायत निवारण व्यवस्था जैसे कदमों को सराहा व कागज रहित विधायिका बनाने की पहली की भी सराहना की. मुखर्जी ने प्रदेश की जनता को उसकी लोकतंत्र में आस्था के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता पर्वतीय व जंगली भूभाग जैसी भौतिक बाधाओं पर विजय पाते हुए लोकतांत्रित प्रक्रिया में हिस्सा लेती है. इसी वजह से विधानसभा चुनावों के मत प्रतिशत में निरंतर सुधार हो रहा है. 2002 में जहां 54.34 फीसद मतदान हुआ 2012 में यह बढ़कर 67.22 फीसद हो गया. उन्होंने तीन विस चुनावों में सत्ता के बदलाव को जीवंत लोकतंत्र की कसौटी बताया और कहा कि लोकतंत्र में बदलाव का आधार जनता के मत ही बनते हैं. उत्तराखंड के पौराणिक इतिहास को याद करते हुए उन्होंने कहा कि माना जाता है कि उत्तराखंड के पहाड़ देवताओं के पसंदीदा निवास स्थान हैं. महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना यहीं की थी और गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम भी देहरादून के नजदीक ही था. पांडव भी अपनी अंतिम यात्रा की ओर जाते हुए उत्तराखंड में रुके थे. जगतगुरु आदि शंकराचार्य 8वीं सदी में केदारनाथ आए थे कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने यहीं निर्वाण प्राप्त किया. स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित सुविख्यात अद्वैत आश्रम चंपावत जिले के मायावती में है. राष्ट्रपति ने चारों धामों के साथ हेमकुंड साहिब व पीरान कलियर के महत्व पर भी प्रकाश डाला और कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक मार्ग भी उत्तराखंड से ही निकलता है. राष्ट्रपति ने केदारनाथ आपदा के बाद राज्य के पुनर्निर्माण व चारधाम यात्रा को समय पर शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार की प्रशंसा भी की. संविधान में विधानसभा को राज्य में शासन के केंद्र में रखा गया है और इसे सुशासन तथा सामाजिक-आर्थिक बदलाव का उपकरण माना गया है. उन्होंने कहा कि विधायक का काम 24 घंटे 7 दिन की जिम्मेदारी के लिए होता है. विधायकों को हर समय जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए और जनता की शिकायतों को विधायिका के समक्ष उठाकर उनकी आवाज बन कर सरकार व जनता के बीच कड़ी बनना चाहिए. इन्होंने कहा कि यह हमेशा याद रखा जाना चाहिए कि देश के युवा व महत्वाकांक्षी नागरिक इनसे सेवा प्रदाता बनने की अपेक्षा रखते हैं और पांच साल के अंत में वे यह हिसाब मांगेंगे कि विधायक ने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाई. चुने हुए प्रतिनिधियों को यह याद रखना चाहिए कि जनता हमारी मालिक है. राष्ट्रपति ने इस बात पर खेद जताया कि पूरे देश में विधायकों का कानून बनाने पर लगने वाला समय कम होता रहा है.. अध्यक्षों के सम्मेलनों में बार-बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि सदन की हर वर्ष कम से कम 100 बैठकें होनी चाहिए. प्रशासन की बढ़ती जटिलताओं के मद्देनजर कानून पारित करने से पहले पर्याप्त परिर्चचा व जांच होनी चाहिए. ऐसा न हुआ तो सदन अपेक्षित परिणाम देने में असमर्थ रहेगा. उन्होंने आग्रह किया कि उत्तराखंड विधानसभा भी अपनी बैठकों की संख्या बढ़ाने पर विचार करे ताकि राज्य के मसलों पर गंभीरता से विचार विमर्श हो सके. राष्ट्रपति ने जनता को विधानमंडलों के और करीब लाने के लिए और जनता को विधायिका की कार्यप्रणाली से परिचित कराने के लिए विधानसभा का संग्रहालय स्थापित करने का सुझाव दिया. साथ ही उन्होंने सत्रों के अवलोकन के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित करने व ग्राम सभाओ व पंचायत जैसे स्थानीय निकायों के सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने की भी सलाह दी. मुखर्जी ने अपना अभिभाषण उत्तराखंड के प्रसिद्ध हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता की पंक्तियों के साथ समाप्त किया. उन्होंने कहा कि देवताओं ने उत्तराखंड व जनता को भरपूर सौंदर्य से नवाजा है. कठोर परिश्रम व दृढ़ निश्चय से राज्य के हर नागरिक का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण होगा. अपने भाषण के अंत में राष्ट्रपति ने सुमित्रा नंदन पंत की कविता की ये पंक्तियां बोलीं- कोटि-कोटि हम श्रमजीवी सुत, सर्व एक मत, एक ध्येय रत, जय भारत हे, जाग्रत भारत हे! ■

लोकतंत्र में केवल तीन डी को स्थान

राष्ट्रपति ने कहा कि डेमोक्रेसी (लोकतंत्र) में तीन डी यानी डिबेट (परिर्चचा), असहमति (डिस्सेंट)व निर्णय(डिसीजन) का स्थान होना चाहिए न कि चौथे डी यानी डिसरप्शन(व्यवधान)का. विधानसभा में अनुशासन व शालीनता के साथ नियमों परंपराओं, प्रक्रियाओं व परिपाटियों का पालन होना चाहिए. असहमति को शालीनता के साथ संसदीय व्यवस्थाओं की सीमाओं में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए. संसदीय प्रणाली के प्रभावी संचालन का बुनियादी सिद्धांत है कि बहुमत शासन करेगा व अल्पमत विरोध करेगा, खुलासा करेगा और संभव हो तो अपदस्थ करेगा, अल्पमत को बहुमत का फैसला स्वीकार करना चाहिए व बहुमत को अल्पमत के विचारों का सम्मान करना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

कांग्रेस की अंदरुनी सियासत गर्माई

रेनु शर्मा

कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद भी मुख्यमंत्री हरीश रावत का प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रति बरकरार मोह कांग्रेस के लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकता है. उत्तराखंड कांग्रेस में नए समीकरणों की आहट महसूस की जा रही है. लगभग सवा तीन साल पहले बैसाखी बनकर कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने वाले प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट की मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी अब कांग्रेस के दिग्गजों को इस कदर खटकने लगी है कि एक-दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले एक मंच पर साथ नजर आने लगे हैं. राजनीति के जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों कांग्रेस की यह अदरुनी सियासत कोई बड़ा गुल खिला सकती है. नई टिहरी में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में दिग्गज भी शामिल हुए. पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, उनके पुत्र साकेत बहुगुणा और टिहरी के प्रभारी कैबिनेट मंत्री डा. हरक सिंह रावत तो इसमें मौजूद थे ही, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर यह संदेश दे दिया की राजनीति में सब कुछ जायज और संभव है. किशोर, मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा विरोधी गुट के, किशोर उपाध्याय स्वयं टिहरी से ही चुनाव लड़ते हैं, लिहाजा इनकी मौजूदगी लाजिमी भी थी. कार्यक्रम में जिस तरह उन्होंने पीडीएफ पर निशाना साधा, उसने कई संकेत मिलते हैं. उपाध्याय ने साफ कहा कि पीडीएफ हमारे कार्यकताओं की बली चढ़ाता रहे और हम मुक दर्शक बने रहे यह अब नहीं चलेगा.

पीडीएफ के मंत्रियों को हटाने की मांग के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि कांग्रेस अब भगवानपुर विधानसभा उपचुनाव जीतकर अपने बूते 70 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी 36 विधायकों का आंकड़ा जुटा चुकी है. पीडीएफ की बैसाखी की अब कांग्रेस की हरीश सरकार को कोई जरूरत नहीं. वर्तमान में छह सदस्यीय पीडीएफ के हिस्से चार मंत्री पद हैं, जबकि 36 विधायकों वाली कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री समेत आठ पद हैं.

किशोर उपाध्याय की परेशानी पीडीएफ कोटे के कैबिनेट मंत्री दिनेश धनै हैं, जो वर्तमान में टिहरी के ही विधायक हैं. इस लिहाज से वह सीधे तौर पर किशोर उपाध्याय के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं. दोनों की राजनीतिक जमीन एक ही है. धनै मंत्री बने रहते हैं तो इसका सीधा नुकसान किशोर को ही होगा, जो उनके राजनीतिक भविष्य के लिहाज से भी ठीक नहीं है. यही वजह है कि नई टिहरी में कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने विरोधी गुट के नेताओं के साथ मंच साझा करते हुए उनके सुर में सुर मिलाने से गुरेज नहीं किया. पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा खुद कई दफा पार्टी एवं कार्यकर्ताओं के हित में मुख्यमंत्री हरीश रावत के समक्ष मंत्रिमंडल में पीडीएफ के कोटे में कटौती कर उनके स्थान पर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों को शामिल किए जाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन बहुगुणा की इस मांग को हरीश ने हमेशा अनदेखा किया है. किशोर का इस सम्मेलन में शामिल होना, हरीश के लिए चिंता का विषय बन गया है. पीडीएफ के मंत्रियों को हटाने की मांग के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि कांग्रेस अब भगवानपुर विधानसभा उपचुनाव जीतकर अपने बूते 70 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी 36 विधायकों का आंकड़ा जुटा चुकी है. पीडीएफ की बैसाखी की अब कांग्रेस की हरीश सरकार को कोई जरूरत नहीं. वर्तमान में छह सदस्यीय पीडीएफ के हिस्से चार मंत्री पद हैं, जबकि 36 विधायकों वाली कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री समेत आठ पद हैं. कांग्रेस का विरोधी गुट अब पीडीएफ को ज्यादा तवज्जो न देने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पर दबाव बना रहा है, और अब तो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसके सुर में सुर मिला दिए हैं. इसके अलावा विरोधी गुट इस बात को लेकर भी परेशान है कि डेढ़-पौने दो साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और बेहतर हो कि कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा विधायक मंत्री के रूप में मतदाता के समक्ष जाएं. राजनीतिक हलकों में पीडीएफ के मुद्दे पर कांग्रेस के परस्पर विरोधी गुटों के एक मंच पर आने के तमाम निहितार्थ निकाले जा रहे हैं. एक तरह से यह मुख्यमंत्री को भी संदेश देने की कोशिश कही जा सकती है कि राजनीतिक भविष्य को लेकर पार्टी नेता कोई बड़े कदम भी उठा सकते हैं. डा.हरक सिंह, बहुगुणा एवं किशोर की तिकड़ी राजनीति की दिशा दशा भी बदल सकती है. ■

feedback@chauthiduniya.com